चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

मूल्य 5 रुपये

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 08 अगस्त– 14 अगस्त 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

कश्मीर

बैलेट बड़ा या पैलेट

हारुन रेशी

कश्मीर घाटी अशांत है. बुरहान वानी के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा में 50 लोग मारे गए, सैकड़ों लोग जख्मी हुए और जिस तरह तनातनी बढ़ी उससे घाटी में यह सवाल तेजी से उठा कि कश्मीर में बैलेट बड़ा है या पैलेट. श्रीनगर के दो सबसे बड़े मेडिकल इंस्टिट्यूट्स और हॉस्पिटल, शेर–ए–कश्मीर इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (सौरा, श्रीनगर) और श्री महाराजा हरी सिंह हॉस्पिटल (श्रीनगर) इस वक़्त ज़ख्मियों से भरे पड़े हैं. इसके अलावा घाटी के जो दूसरे जिला अस्पताल हैं, वहां भी ज़ख्मियों का इलाज चल रहा है. ज़ख्मियों में कम उम्र के लड़के भी हैं, कुछ नौजवान भी हैं और कुछ लड़कियां भी हैं. ये सभी लोग पिछले कुछ दिनों के दरम्यान जख्मी हुए हैं. यानि यह सारा सिलसिला उस समय शुरू हुआ जब 8 जुलाई की शाम साढ़े आठ बजे सुरक्षा बलों ने श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर, दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में कार्रवाई करके वहां मौजूद तीन आतंकवादियों को मार गिराया. सुरक्षा बलों की टीम श्रीनगर से मिली एक खास सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन करने गई थी. मारे गए तीन आतंकियों में एक बुरहान वानी भी था. उसकी उम्र 22 साल थी. उसे पिछले दो साल में कश्मीर में बड़ी शोहरत मिली थी, क्योंकि वह कम्प्यूटर का जानकार था और फेसबुक पर सक्रिय था. जब उसके मारे जाने की ख़बर कश्मीर घाटी में फैली तो शहर और कस्बे के नौजवान सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने लगे और यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा. दूसरे दिन उसके जनाज़े में दो लाख से ज्यादा लोग शरीक हुए.

दरअसल, मसला यह है कि उसके इलाके में बुरहान के साथ लोगों की हमदर्दी रही है. लोगों का कहना है कि बुरहान की उम्र उस वक़्त 15 साल थी जब उसके बड़े भाई खालिद को सुरक्षा बालों ने बहुत पीटा था. इस घटना से उसका दिल टूट गया था और उसने फैसला किया था कि वह मिलिटेंट बनेगा. बाद में उसका भाई खालिद मारा भी गया. बुरहान के माता पिता का कहना है कि उसे फर्जी मुडभेड़ में मारा गया. वह मिलिटेंट नहीं था. वह पोस्ट ग्रेजुएट लड़का था. फेसबुक पर बुरहान की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी थी. वह अगर कोई पोस्ट या वीडियो अपलोड करता था तो उसे देखते ही देखते सैकड़ों लाइक्स आ जाती थीं.

बहरहाल, पिछले 26 साल से कश्मीर में आतंकवाद जारी है. सुरक्षा बलों के मुताबिक यहां कई आतंकवादी मारे जा चुके हैं. लेकिन बुरहान पहला ऐसा मिलिटेंट है जिसके मरने पर इतना बवाल मचा. लोगों का कहना है कि वह दहशतगर्द था लेकिन असल में वह विक्टिम भी था और उसके साथ ज्यादती हुई थी. एक बच्चा जिसने अपनी आंखों के सामने एक बेगुनाह भाई को पिटते देखा था और गुस्से में आतंकी बन गया. बहरहाल, अभी तक सरकार ने पुष्टि की है कि 8 जुलाई से 27 जुलाई के बीच 50 लोग मारे जा चुके हैं. आधिकारिक तौर पर 2500 लेकिन अनधिकृत तौर पर 3500 लोग ज़ख्मी हैं, इनमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.

लोग तीन तरीकों से ज़ख्मी हुए हैं. एक सुरक्षा बलों की फायरिंग से हुए, दूसरे पैलेट गन के इस्तेमाल से और तीसरे पत्थरबाजी से. पैलेट गन एक ऐसी गन होती है जिससे छोटे–छोटे छर्रे निकलते हैं, जिससे आदमी मरता नहीं है लेकिन जिस्म पर बहुत ज़्यादा चोट लगती है. डॉक्टरों का कहना है कि 170 ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी सर्जरी होगी. उनमें से बीस लोगों की आंखें प्रभावित हुई हैं. बीस में से दस ऐसे हैं जिनकी एक आंख खराब हो चुकी. इनमें से चार लोगों को एम्स ले जाया गया. सरकार ने इलाज का इंतज़ाम किया. उनमें एक लड़की भी है 14 साल की, जिसका नाम है इंशा मलिक, दक्षिण कश्मीर की है. उसकी मां से जब इस संवाददाता ने बात की तो उसका कहना था कि इंशा घर में बैठी थी जब बाहर प्रदर्शन हो रहे थे. सुरक्षा बल के पैलेट गन की फायरिंग से एक छर्रा आ उसे लग गया और उसकी दाईं आंख चली गई. राज्य सरकार ने एम्स से डॉक्टरों की एक टीम भी बुलाई है (शेष पृष्ठ 2 पर)

लोग तीन तरीकों से जख्मी हुए. एक सुरक्षा बलों की फायरिंग से, दूसरे पैलेट गन के इस्तेमाल से और तीसरे पत्थरबाजी से. पैलेट गन से छोटे–छोटे छर्रे निकलते हैं, जिससे आदमी मरता तो नहीं पर बहुत चोट लगती है. 170 ज़ख्मी ऐसे हैं जिनकी सर्जरी होगी. उनमें से बीस लोगों की आंखें प्रभावित हुई हैं

डॉ. फ़रहा यूसुफ़

कश्मीर में काफी दिनों से तनाव चल रहा है. बुरहान वानी के इन्काउंटर में मारे जाने के बाद इसकी शुरुआत हुई. बुरहानी वानी के बारे में यह सामने आया है कि वह हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था. वह 22 या 23 साल का एक नौजवान लड़का था जो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल का रहने वाला था. पिछले करीब 26 सालों से त्राल दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले का संवेदनशील इलाका है. आज जो मिलिटेंसी हम देख रहे हैं इसकी शुरुआत ज्यादातर इसी इलाके से हुई है. आज भी इस इलाके को मिलिटेंसी के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. बुरहान वानी पुलवामा, अनंतनाग और पहलगाम में ज्यादातर सक्रिय था. उसे अनंतनाग जिले से पकड़ा गया था या इसे ट्रेस किया गया था, जैसा कि बाद में सेना की तरफ से रिपोर्ट आई कि उसे कई दिनों से ट्रेस करने की कोशिश हो रही थी. साइबर सेल करीब डेढ़ महीने से सक्रिय था. बताया जा रहा है कि इसके पास 5 से 6 मोबाइल नंबर थे जिसको यह रोटेशन पर इस्तेमाल करता रहता था, जिसके जरिए यह अलग–अलग लोगों के संपर्क में था. बुरहानी वानी सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय था. बुरहानी वानी की उम्र बहुत कम थी और वह करीब 2010 से मिलिटेंसी में पूरी तरह से शामिल था. जैसा कहा जाता है कि पुलिस की बदसलूकी से आहत होकर उसने आतंकवाद का रास्ता चुना था. बुरहान वानी काफी मशहूर हुआ. उसने कभी नकाब का इस्तेमाल नहीं किया और खुलेआम उसने फेसबुक पर अपनी फोटो डाल दी. इस वजह से लोगों को वह बहुत बहादुर लगा. उसके दाएं बाएं ऑटोमेटिक हथियार भी देखे गए. कहा जाता है कि उसने आईएसआईएस की तरह क्लिप्स भी बनाईं. इन्हीं हरकतों की वजह से सरहद पार वालों ने उसे हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बना दिया था. भाई के मारे जाने के कारण भी बुरहान में काफी गुस्सा था. बुरहान वानी के इन्काउंटर पर कई सवाल खड़े होते हैं. निर्धारित मानकों के तहत बुरहान को सरेंडर करने का मौका नहीं दिया गया. पुलिस खुद कह रही है कि तीन मिनट में ही इन्काउंटर खत्म कर दिया गया था. सिर्फ तीन मिनट के अंदर बुरहान वानी और उसके दोनों साथियों को मार डाला गया. स्पष्ट है कि मुठभेड़ के लिए बुरहान की तरफ से कितनी तैयारी थी.

सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है, जिसके तहत यह साफ हो जाए कि कश्मीर में क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है और क्यों हो रहा है. बुरहान वानी की मौत के बाद जैसा कि तय था और जैसा कि पिछले 25 सालों से होता आ रहा है, यह तय था कि कश्मीर एक बार फिर जल उठेगा. लोग पिछली बातों को भूल जाते हैं और कश्मीर को ऐसी आफतों की तरफ जान–बूझकर ढकेल देते हैं. बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का चेहरा बन चुका था. उसके साथ नौजवान थे और उसके साथ लोगों की सहानुभूति थी. इसलिए उसकी मौत के अगले ही दिन हर जगह पत्थरबाजी शुरू हो गई. पत्थरबाजी पर काबू पाने के लिए एक दो बार आंसू गैस का इस्तेमाल होता फिर उसके बाद सीधे गोलियां चलतीं. पैलेट गन का इस्तेमाल तो मौका मिलने पर होता है, नहीं तो आमतौर सुरक्षाबल गोली ही चलाते हैं. सरकार के रवैये पर एक सवाल यह भी है कि बुरहान के मारे जाने के तुरंत बाद कर्फ्यू नहीं लगा. इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं की गईं. दो दिन के बाद कर्फ्यू लगा. तब तक दक्षिण कश्मीर में हिंसा फैल गई थी और वहां हालात बेकाबू हो गए थे. हालात पुलिस के नियंत्रण से बाहर चले गए थे क्योंकि दक्षिण कश्मीर के साथ–साथ हिंसक प्रदर्शन की इस लहर ने पूरे कश्मीर को अपनी चपेट में ले लिया था. बुरहान वानी का जिस तरह से इन्काउंटर किया गया उस पर बहुत से लोगों ने सवाल उठाए. कर्फ्यू लगने के बाद कश्मीर की मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े नेता या हर्रियत जिसका आम जनता पर दबादबा है, उन्होंने अनियंत्रित हड़ताल या सिविल नाफरमानी की घोषणा कर दी जो आज तक चल रही है. इस बार के हड़ताल में जबरदस्त हिंसा देखने को मिली. कश्मीर में पिछले 25 साल से हिंसा हो रही है. इस अवधि में यहां कई नेता ऐसे हैं जो नौजवान से बूढ़े हो गए, लेकिन हैरानी यह है कि इतने सालों में नीति नहीं बदली. आज भी कश्मीर को लेकर रवैया वैसा ही है जैसा 1990 के दशक में था. लाखों लोगों के मरने के बाद भी कोई सरकार, कोई राजनीतिज्ञ या कोई (शेष पृष्ठ 2 पर)

बुरहान वानी हिजबुल मुजाहिदीन का चेहरा बन चुका था. उसके साथ नौजवान थे और लोगों की सहानुभूति थी. इसलिए उसकी मौत के अगले ही दिन हर जगह पत्थरबाजी शुरू हो गई. पत्थरबाजी पर काबू पाने के लिए एक दो बार आंसू गैस का इस्तेमाल होता फिर उसके बाद सीधे गोलियां चलतीं

कश्मीर : बैलेट बड़ा या पैलेट

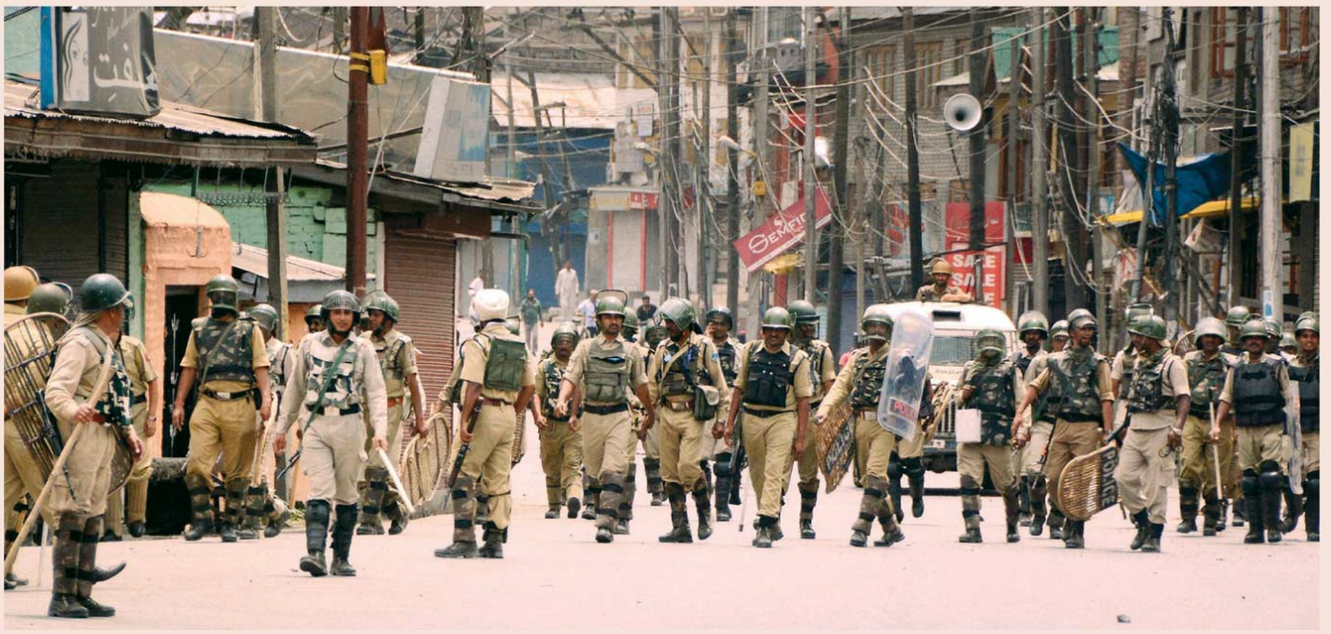

पृष्ठ 1 का शेष

जो आंखों का इलाज करेगी. एम्स की टीम ने देखा कि ज़ख्मियों में से कुछ लोगों की हालात गंभीर है, जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया है. इससे मरने वालों की संख्या बढ़ने का भी अंदेशा है. पत्थरबाजी में सुरक्षा बल के लोगों को भी गंभीर चोटें आईं. आधिकारिक तौर पर 15 सौ सुरक्षा कर्मी जख्मी हुए, जिनमें 244 सुरक्षाकर्मियों को गंभीर जख्म आए और अलग-अलग अस्पतालों में उनका भी इलाज चल रहा है.

यह प्रकरण बुरहान वानी के इन्काउंटर से शुरू हुआ, जिसने सबके सामने यह सवाल छोड़ा कि बुरहान को इतनी लोकप्रियता क्यों मिली? पहली बार ऐसा हुआ कि किसी मिलिटेंट के ज़नाज़े में दो लाख लोग शामिल हुए. इतना ही नहीं, दूसरे दिन घाटी के अलग अलग इलाकों में गायबाना नमाज़-ए-जनाज़ा पढ़ा गया, जिसमें तकरीबन पांच लाख लोगों ने बुरहान के जनाज़े की नमाज़ पढ़ी. माना जा रहा है कि मिलिटेंसी अब नई नस्ल में ट्रांसफर हो गई है. इस वक्त सड़कों पर जो हंगामे कर रहे हैं, ज़ख़्मी हो रहे हैं, इनकी उम्र भी बीस साल और तीस साल के बीच है. समीक्षकों का कहना है कि यह हिंसा की जो लहर है यह नई नस्ल में ट्रांसफर हो गई है. सवाल है कि ये सब क्यों हुआ? क्या वजह है कि पिछले 26 साल से (1989 में कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई थी) मिलिटेंसी को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. बुरहान के मरने के बाद जो स्थिति पैदा हुई, उससे यह साबित हो गया कि मिलिटेंसी को पूरी तरह समाप्त करने में सुरक्षा बल नाकाम हैं. इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि सरकार को राजनीतिक पहल करनी चाहिए. लेकिन समस्या यह है कि केंद्र सरकार उस मूड में नज़र नहीं आ रही है. इसकी साफ़ वजह है कि मोदी सरकार ने पूरे मुल्क में एक खास एजेंडा लेकर ही वोट हासिल किया है. यह कश्मीर के लिए हिंदुस्तान की अपनी जनता को नाराज़ नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर इनका एक हार्ड लाइन स्टैंड है. इनके चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि कश्मीर में आर्टिकल 370 भी ख़त्म कर देंगे, राम मंदिर बनाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे. ऐसे में इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि मोदी सरकार कोई पहल करेगी. लेकिन पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का स्टेटमेंट आया है. उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों को कश्मीर को लेकर बहुत गलतफहमी है. वे कश्मीर के हालात को समझने में गलती कर रहे हैं. उनका कहना था कि आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि कश्मीर के लोग भारत से कट जाना चाहते हैं या पाकिस्तान से जुड़ जाना चाहते हैं. उनका कहना था कि दरअसल कश्मीर के लोग अपनी शिनाख्त चाहते हैं, अपनी पहचान चाहते हैं. वे वैसी स्थिति को बहाल करना चाहते हैं जिस स्थिति में कश्मीर का भारत में विलय हुआ था. 1964-1965 तक कश्मीर का अपना एक (शेष पृष्ठ 3 पर)

पृष्ठ 1 का शेष

स्टेट्समैन ऐसा नहीं है जो ऐसे उपाय कर सके जिससे कश्मीर से हिंसा का माहौल खत्म हो जाए और कश्मीर के लोगों को थोड़ी शांति मिले. इससे कश्मीर के नौजवानों, बच्चों और बुजुर्गों को लगे कि उनके लिए किसी के दिल में दर्द है. उनकी मौतों को रोकने के लिए पहल की जा रही है, उनकी घुटन को कम करने के लिए पहल की जा रही है. लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है. नौजवान मारे जाते हैं, राजनेता आते हैं और सहानुभूति की दो-चार बातें कर वापस चले जाते हैं. यही कहानी बार-बार दोहराई जा रही है. लेकिन ऐसा कब तक चलेगा. हर कोई जानता है कि कश्मीर एक विवादित और राजनीतिक मुद्दा है. कश्मीरियों को इससे मतलब है कि सरकार यह स्वीकार करे कि कश्मीर एक समस्या है और उनसे पूछा जाए कि इस समस्या का समाधान क्या है. सरकार यह कहकर कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं यह कहकर उनसे बात नहीं कर रही है. लेकिन कश्मीरियों ने कभी नहीं कहा कि वह पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहे हैं. अगर कुछ लोग ऐसा कह भी रहें तो सरकार को उसको नजदीक से देखना और समझना चाहिए कि ये कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है. कश्मीर में कोई सौ दो सौ लोग नहीं रहते हैं, लाखों लोग रहते हैं, क्या सरकार ने इनसे पूछा है?

अगर कश्मीर के एक या दो प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान का नाम ले लिया या पाकिस्तान कश्मीरियों से मजहबी नजदीकी की वजह से प्यार जताता है, तो उसका हव्वा खड़ा करके भारत की तरफ से ये कहा जाता है कि कश्मीरियों को छोड़ देंगे तो वो पाकिस्तान चले जाएंगे. कश्मीरियों को मालूम है कि पाकिस्तान कैसा देश है, उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान कितना विकसित है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, अमीर है गरीब है. कश्मीर में भी कुछ सोचने-समझने वाले लोग हैं जिनका दिमाग काम करता है. यह अंदाजा लगना ठीक नहीं है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं. कश्मीर की अपनी जमीन है, उसके पास संसाधन हैं, उन्हें पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है. भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि उन्हें कुछ करने दे, उन्हें उनके संसाधनों का इस्तेमाल करने दे. उन्हें वो छूट दे, जिसके सहारे वह जिंदा रहने की कोशिश करें.

हालिया हिंसा में कश्मीर में पैलेट गन का बुरा इस्तेमाल हुआ. किसी के पेट, किसी की छाती तो किसी के मुंह पर छर्रे लगे हुए हैं. एक भी मरीज ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी टांग पर हमला हुआ हो. कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई. क्यों नहीं कश्मीर से अफ्सपा को हटा दिया जाता है. पत्थरबाजी करने वाले पकड़े जाते हैं, जेल में ठूंस दिए जाते हैं. क्या कोई सीआरपीएफ वाला भी कभी सस्पेंड हुआ? नहीं. इतने दिनों तक यहां ये सब होता रहा, जब विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि डॉक्टर भेज दो तो दो चार डॉक्टर आ जाते हैं.

जब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को लगा कि हालात बेकाबू हो रहे हैं तो उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई. उमर अब्दुल्ला ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया. जब केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आए तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया. लेकिन संसद मेंगुलाब नबी आजाद ने लंबा चौड़ा भाषण दे डाला. जब कश्मीर की सिविल सोसायटी के लोग मंत्री के साथ बात कर रहे थे तब कांग्रेस के लोगों ने अपनी बात क्यों नहीं रखी? वही गुलाब नबी आजाद, जिनके वक्त यहां सौ से ज्यादा लोग मरे थे, जब वो पीडीपी के साथ गठबंधन सरकार बनाए हुए थे, वो कह रहे थे कि भाजपा को तजुर्बा नहीं है. गुलाम नबी आजाद को तर्जुबा है तो फिर उनकी कुर्सी क्यों चली गई थी.

कश्मीर में इस तरह का पॉलिटिकल ड्रामा खूब चलता है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियां हमारे साथ ऐसा कर रही हैं. यहां की क्षेत्रीय पार्टियां भी अपनी बातें खुलकर सामने नहीं रख पा रही हैं. राज्यसभा में कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद और भाजपा से अरुण जेटली खूब जमकर बोले. कश्मीर पर बेहतर भाषणबाजी के लिए उन्हें दुनिया भर में खूब वाहवाही भी मिली. हर नेता को यह याद है कि कश्मीर में किस साल कितनी हिंसा हुई, कितने नौजवान मरे, कितनी मौतें हुईं, कितने दिन कर्फ्यू रहा, ये सभी आंकड़े सबकी उंगलियों पर हैं, लेकिन (शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 23
08 अगस्त- 14 अगस्त 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कश्मीर : बैलेट बड़ा या पैलेट

पृष्ठ 2 का शेष

प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, यहां गवर्नर नहीं बल्कि सदर होता था, जिसे सदर-ए-रियासत बोलते थे. डॉक्टर कर्ण सिंह कश्मीर के सदर-ए-रियासत थे. उस समय राज्य को स्वायतत्ता थी. पिछले 30-40 साल में जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार के तीन सौ से साढ़े तीन सौ कानून लागू हैं. इसका मतलब यह है कि पहले जो स्वायतत्ता हासिल थी वह तकरीबन छिन चुकी है. चिदम्बरम का यही कहना था कि ये लोग अपनी पहचान की बहाली चाहते हैं या ये उस स्थिति पर आना चाहते हैं जिसपर इन्होंने भारत के साथ विलय किया था. विलय दरअसल महाराजा हरी सिंह ने किया था, लेकिन वो शर्त आधारित विलय थी. शर्त में यह था कि भारत के अधिकार में केवल रक्षा, विदेश निति और संचार रहेगा बाकी के जितने भी मामले हैं वह सब जम्मू और कश्मीर की सरकार के अधिकार में होंगे. लेकिन उस स्थिति को धीरे धीरे समाप्त किया गया. इसके नतीजे में अलगाव की भावना बढ़ गई है. लोगों को लग रहा है उनसे उनकी पहचान छीनी जा रही है. यह भारत का एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य है. यहां के लोगों को एक शंका है कि मुस्लिम मेजोरिटी कैरेक्टर को बदला जा रहा है. आबादी की संरचना को बदला जा रहा है. इसकी बहुत सारी मिसालें देखने को मिल रही हैं. जबसे पीडीपी और भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद कुछ ऐसे क़दम उठाए गए हैं जिनकी वजह से यह आशंका बढ़ गई है. मिसाल के तौर पर इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को यहां वापस बसाने के लिए अलग सिटीज बसाएंगे. कश्मीरी पंडितों को वापस आने पर कश्मीरियों को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि यह रियासत जितनी कश्मीरी पंडितों की है, उतनी ही मुसलमानों की है. लेकिन समस्या यह कि कश्मीरी अवाम को एक अलग शहर बसाना संदेहास्पद लग रहा है.

हाईकोर्ट के एक पूर्व जज जीडी शर्मा की एक किताब है कश्मीर के बारे में. इस किताब में शर्मा साहब ने कहा कि आर्टिकल 370 को ख़त्म करो. सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपने संबोधन में कहा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाओ लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए दस लाख पूर्व सैनिकों को भी वहां भेजो, उन्हें हथियार दे दो ताकि वो उनकी हिफाज़त करें. उस वक़्त इस बयान पर बड़ा शोर हुआ था. लोनों ने सोचा कि पंडित तो यहां के बाशिंदे हैं, लेकिन उनके साथ अगर दस लाख पूर्व सैनिकों को भी भेजा जा रहा है तो इसका मतलब है कि सरकार की की नीयत ठीक नहीं है. इस पर लोगों को ऐतराज़ था.

दूसरी बात यह कि हालिया दिनों में जब राज्य में गवर्नर रूल था, जब सरकार बनाने के मामले पर पीडीपी और भाजपा के बीच बातचीत चल रही थी, उस वक्त गवर्नर ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रस्तुत की थी. उस औद्योगिक नीति में उन्होंने एक प्रावधान रखा था कि यहां बाहर के जो उद्यमी हैं उन्हें औद्योगिक यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी. उस पर भी यहां बहुत शोर और हंगामा हुआ. लोगों ने कहा कि आर्टिकल 370 के तहत बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां ज़मीन नहीं खरीद सकता और न यहां बिजनेस कर सकता है. अगर ऐसा किया गया तो एक तरह से यहां फ्लड गेट खुलेगा. बाहर के लाखों उद्योगपति कश्मीर आकर यहां अपनी यूनिट चालू करने लगेंगे. दरअसल, कश्मीर के लोगों को भय है कि उनकी पहचान समाप्त की जा रही है. इस मसले का राजनीतिक हल निकला जाना चाहिए था. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है. बल्कि यहां के जो बुद्धिजीवी हैं वो यह साफ़ तौर पर कहते हैं कि भारत में सिर्फ दो लोग पैदा हुए जो असल में इस मसले को अच्छी तरह समझ पाए थे और जो सच्चे दिल से इसका सियासी तौर पर हल करना चाहते थे. इनमें पहले महत्मा गांधी थे और उनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी थे. (शेष पृष्ठ 4 पर)

विलय महाराजा हरी सिंह ने किया था, लेकिन वह शर्त आधारित विलय थी. शर्त में था कि केंद्र के अधिकार में रक्षा, विदेश नीति और संचार रहेगा बाकी के जितने भी मामले हैं वह सब जम्मू और कश्मीर की सरकार के अधिकार में होंगे. कश्मीरी फिर से वही स्थिति बहाल करना चाहते हैं

पृष्ठ 2 का शेष

किसी ने भी कश्मीर मसले पर आज तक कोई पहल नहीं की. आंकड़ों को तो कोई भी याद रख सकता है, तारीखें तो यहां भी लोगों को ज़ुबानी याद हैं. कश्मीरियों को भी पता है कि किस राजनीतिक पार्टी के शासनकाल में यहा क्या हुआ? किस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कश्मीर में कैसे हालात रहे? अगर कोई कुशल राजनेता है तो वह कश्मीर के हित में कोई बेहतर कदम उठाए, कश्मीरियों को जोड़ने के लिए कोई पहल करे. इन बातों का कोई अर्थ नहीं है कि इन दो दशकों में यहां कितनी मौतें हुईं. ये भी भूल जाने की बात है कि यहां कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, अब तक जितने लोग भी मरे, उन्हें भूल जाना चाहिए. राजनेता कश्मीरियों के हित में कोई रोडमैप लेकर आएं, यहां के लोगों के साथ संवाद कायम करें. लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है. कांग्रेस पार्टी भाजपा की गलतियों को याद रखती है और भाजपा कांग्रेस की गलतियों को. नेशनल कान्फ्रेंस (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की घटनाओं को याद रखती है तो पीडीपी, एनसी की गलतियां रटती है. सभी राजनेता उंगलियों पर यह गिना देंगे कि किस पार्टी के शासनकाल में कितनी मौतें हुईं, लेकिन पहल करने के लिए कोई तैयार नहीं है. कुर्सी का मोह छोड़कर लोगों के साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है.

नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर की जनता ने तीन मौके दिए, लेकिन पार्टी ने कोई भी बेहतर काम नहीं किया. आज महबूबा कुर्सी से उतर जाएं, अब्दुल्ला साहब आ जाएं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? दोनों कुर्सी से उतर जाएं, गवर्नर साहब कुर्सी पर आ जाएं, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. चेहरे बदल रहे हैं, पार्टियां बदल रही हैं, लेकिन नियम वही पुराने चल रहे हैं. कश्मीर के लोग बार-बार कह रहे हैं यह एक पॉलिटिकल इश्यू है, इससे इन्कार मत कीजिए. यह दुर्भाग्य ही है कि आज तक कश्मीर की तरक्की और विकास के मुद्दे पर राजनीतिक दल एकमत नहीं हुए. वे कभी राज्य के विशेष दर्जे को चुनौती देते हैं तो कभी आर्टिकल 370 हटाने की बात करते हैं, तो कभी अलग फ्लैग पर भी सवाल उठाते रहते हैं. इससे माहौल सुधरने वाला नहीं है. कश्मीर के मसले पर मुफ्ती साहब और अटल बिहारी वाजपेयी ने गंभीर पहल की थी. लोगों को उम्मीद बंधी थी कि जल्द कश्मीर का कोई हल सामने आएगा. दरअसल कश्मीर की जनता वाजपेयी में नेतृत्व कौशल की क्षमता को खुले मन से स्वीकार करती थी. यहां के लोग मानते थे कि वाजपेयी कश्मीर को लेकर कभी भेदभावपूर्ण विचार नहीं रखते थे.

किसी ने भी कश्मीर मसले पर आज तक कोई पहल नहीं की. आंकड़ों को तो कोई भी याद रख सकता है, तारीखें तो यहां भी लोगों को याद हैं. कश्मीरियों को भी पता है कि किस राजनीतिक पार्टी के शासनकाल में यहां क्या हुआ? किस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कश्मीर में कैसे हालात रहे?

भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार चला रहीं महबूबा मुफ्ती भी सुरक्षा बलों के विशेष अधिकारी वापस लेने और पैलेट गन के इस्तेमाल को रोकने की बात लगातार कर रही हैं. हाल में राजनाथ सिंह के दौरे के वक्त भी उन्होंने समझाने की कोशिश की कि प्रयोग के तौर पर कुछ इलाकों से अफस्पा को हटाया जा सकता है. महबूबा ने राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान यह मांग की कि पावर हाउसेज व पावर प्रोजेक्ट्स कश्मीर को लौटा दिए जाएं. उन्होंने राजनाथ सिंह से कहा कि आप कश्मीरियों को ये सिग्नल दे दो कि आप हमारे अपने हैं. आप उनके हमदर्द हैं. लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ. समझौते के तहत पावर प्रोजेक्ट्स को भी नहीं लौटाया जा रहा है. सवाल यह भी उठता है कि क्या कभी केंद्र सरकार ने सेना से कहा कि किसी आतंकवादी को इन्काउंटर में मत मारो, उन्हें जिंदा पकड़ो. कश्मीर के लोगों को याद नहीं कि कभी मीडिया से कहा गया हो कि यहां की हिंसा को इतना बढ़ा-चढ़ा कर मत दिखाओ जिससे यहां का युवा भड़क जाए, बहक जाए. दरअसल हो ये रहा है कि आतंकवादियों को मार भी रहे हैं और मीडिया को भी छूट दे रहे (शेष पृष्ठ 4 पर)

कश्मीर : बैलेट बड़ा या पैलेट

पृष्ठ 3 का शेष

हालांकि करगिल युद्ध हुआ था, संसद पर हमला भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वाजपेयी ने कई क़दम उठाए थे, जिससे कश्मीर में एक सच्चे अमन का वातावरण बना था. लोगों को लग रहा था कि वाजपेयी इस समस्या का समाधान निकालने के लिए गंभीर हैं. हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ शब्दों में कहा था कि सरहदों को बदला नहीं जा सकता है. यानि वह मौजूदा व्यवस्था में ही कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे थे. इतेफाक से उस समय पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ शासनाध्यक्ष थे. वह एक निरंकुश व्यक्ति थे. किसी से उनको पूछना नहीं था. शायद वह भी उनको सपोर्ट कर रहे थे. लेकिन बाद में समस्या यह हुई कि पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए. मुशर्रफ को हटा दिया गया और मामला खत्म हो गया.

यूपीए सरकार ने इसे जारी रखने की कोशिश की थी. राहुल गांधी को लांच करना था तो उन्हें लगा कि अगर हम कश्मीर पर कोई ढील देंगे तो देश में हमारे खिलाफ बीजेपी बवाल खड़ा कर देगी, तो डायलॉग रुक गया. उसके बाद से इस पर कोई पहल नहीं की गई. वर्ष 2010 में भी इसी तरह प्रदर्शन शुरू हुए थे, जैसे आज चल रहे हैं. हालांकि आज के प्रदर्शन की तीव्रता ज्यादा है. इसकी वजह है एक तो कम समय में ज्यादा लोग मारे गए हैं, दूसरे ढाई हज़ार लोगों का ज़ख्मी होना. इसलिए आज की जो स्थिति है वह ज़्यादा खतरनाक है. लेकिन 2010 में भी 120 लोग मारे गए थे. दरअसल सीमा से लगे कुपवाड़ा से सेना ने तीन लोगों को उठाया था, फिर उनको मार दिया था और कहा था कि वे आतंकवादी थे. उस मामले को लेकर भी प्रदर्शन शुरू हुआ था और

2010 में भी 120 लोग मारे गए थे. उस समय भी कुपवाड़ा में सेना ने तीन कथित आतंकियों को मार दिया था. उस मामले को लेकर भी प्रदर्शन शुरू हुआ था और फिर बहुत सारे नौजवान मारे गए थे. मरने वालों में आठ साल के बच्चे भी शामिल थे. उस समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी.

फिर बहुत सारे नौजवान मारे गए थे. मरने वालों में आठ साल के बच्चे भी शामिल थे. उस समय यूपीए की सरकार थी. उस समय सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आया था. कई राजनेता आए थे. उस समय लग रहा था कि केंद्र सरकार गंभीर है. उन्हें इस बात का एहसास था कि लोग मारे गए हैं. वो यहां आए थे और उन्होंने बहुत कोशिश की थी यहां के लोगों को मानाने की. पी चिदंबरम भी खुद दो तीन बार यहां आए थे. लोगों का गुस्सा उस वक़्त ठंडा हो गया था. बल्कि भारत सरकार ने उस समय दिलीप पडगांवकर की अध्यक्षता में बुद्धिजीवियों की एक टीम बनाई थी, जिसमें राधा कुमारी थीं. आठ महीने तक यह टीम जम्मू और कश्मीर में रही और तमाम प्रतिनिधिमंडलों और समाज के हर तबके के लोगों से मिली. उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश की थी. इस रिपोर्ट में समिति ने कुछ सुझाव दिए थे कि क्या क्या किया जाना चाहिए. लेकिन उस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया गया. वह रिपोर्ट अभी भी गृह मंत्रालय के किसी न किसी टेबुल पर धूल चाट रही होगी. कश्मीर के समीक्षक कहते हैं कि अगर इन वार्ताकारों की रिपोर्ट को पढ़ा गया होता तो शायद आज यह स्थिति नहीं होती. दूसरी बात यह है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते एक बार कश्मीर आए थे एक कार्यक्रम में. उन्होंने यह घोषणा की थी कि कुछ समितियां बनाई जाएंगी जो यह पता लगाएंगी कि हालात क्यों खराब हो रहे हैं. उन समितियों में एक समिति थी, जिसका काम था कि केंद्र और राज्य के रिश्तों को ठीक करने के लिए रास्ता तलाशना. उस समय हामिद अंसारी (मौजूद उपराष्ट्रपति) की अध्यक्षता में एक टीम बनी थी. इस टीम ने भी भारत सरकार को एक रिपोर्ट दी थी. उस रिपोर्ट पर भी कोई अमल नहीं हुआ.

समस्या यह है कि यहां के लीडर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है. मिसाल के तौर पर 2010 के हालात के बाद जब शांति प्रक्रिया शुरू हुई थी तो कश्मीरी अलगाववादियों ने भारत सरकार को बहुत सहयोग दिया था. यहां तक की मीरवायेज उमर फारूक गुप्त रूप से दिल्ली गए थे. वह एक रात खान मार्केट गए थे जहां वे चिदंबरम से मिले थे. लेकिन समस्या यह हुई कि तीसरे दिन प्रवीण स्वामी ने दी हिन्दू में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने उस कार का नंबर तक का ज़िक्र किया था, जिसमें बैठ कर मीर वायेज़ चिदंबरम से मिलने गए थे. यानि जब यह बात यहां फ़ैल गई तो मीर वायेज़ पर इलज़ाम लगा कि वह चोरी छिपे भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं. नतीजा यह हुआ कि मीर वायेज़ की इमेज ख़राब हो गई और मिलिटेंट्स ने उनके करीबी साथी फजलुल हक कुरैशी पर हमला किया. फजलुल हक कुरैशी कई महीनों तक कोमा में रहे.

बिल्कुल उसी तरह यासीन मालिक के साथ हुआ. यासीन मालिक अमेरिका गए थे. वहां वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से गुप्त रूप से मिले. लेकिन फिर इस चीज़ को भी लीक किया गया तो उनकी भी हालत बुरी हो गई. उसी तरह गिलानी के बेटे, जो पिछले दस साल से पाकिस्तान में थे, उसको ए.एस. दुल्लत की सिफारिश और मदद से वापस घर लाया गया तो उसकी वजह से भी गिलानी को लोगों ने कहना शुरू किया कि वे इनके साथ मिले हुए हैं. तुम्हारे बेटे को तो यहां ले आया गया, लेकिन जो बाकी लड़के सरहद के उस पार फंसे हुए हैं, उनको यहां नहीं आने दिया जा रहा है. यानि, लोग सोचते हैं कि भारत सरकार ने (शेष पृष्ठ 5 पर)

पृष्ठ 3 का शेष

हैं. सेना को भी छूट दे रहे हैं. इसके बाद कुछ लोगों को कश्मीरियों के जख्म पर नमक छिड़कने की छूट भी दे रहे हैं.

अभी पता चला है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर नहीं लौटना चाहते हैं. क्या इन बीस सालों में किसी कश्मीरी मुलाजिम या कश्मीर के किसी कर्मचारी को किसी ने एक थप्पड़ भी मारा है. कश्मीरी पंडित यहां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं. उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है. उन्हें आने-जाने के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं. कश्मीरी पंडितों को दर्जनों पैकेज दिए गए हैं. हिंदुस्तान के हर कोने में कश्मीरी पंडित इज्जत से बसा है. कश्मीरियों का कहना है कि धक्के हम लोग खाते हैं. हमलोग जो यहां परेशानियां झेल रहे हैं, वह किसी को नहीं दिख रहा है. हां, यह सच है कि कश्मीरी पंडितों की यहां पर जमीन है, मजे से उनको नौकरियां दी गईं. अब यहां के लोग देख रहे हैं कि जो उनके साथ कई वर्षों तक एक थाली में खाते रहे, आज कह रहे हैं कि वे कश्मीर नहीं लौटना चाहते हैं. क्या हम उन्हें आतंकवादी लग रहे है, जिनके डर से वे यहां नहीं लौटना चाहते हैं? उनके घरों की स्थानीय लोगों ने रखवाली की, पैसे देकर उनकी प्रॉपर्टी खरीदी. यहां किसी की प्रॉपर्टी हड़पी नहीं गई, न ही किसी ने नाजायज कब्जा किया और न ही उनके साथ कोई गुंडागर्दी की गई. आज सरकार उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रेस डील्स (मजबूरी या हालात से तंग आकर बेची गई संपत्ति) बता रही है. आज कोई भी कश्मीरी पंडित वापस आकर अपनी जमीन वापस ले सकता है. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आज यहां किसी माइग्रेंट प्रॉपर्टी का लेन-देन नहीं होने देते हैं. सरकार ने उन डील्स को खारिज कर दिया है. आज कश्मीरी पंडित वापस लौटकर आ रहे हैं और वे मुसलमानों से आज के हिसाब से पैसा मांगकर जमीन के कागजात देने की बात कर रहे हैं. तब अटॉर्नी दी थी, आज कागज देने की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आज की डेट में हमें पैसे दे दो. लोग यहां आकर देख सकते हैं कि यहां कश्मीरी पंडितों को कोई नुकसान नहीं हुआ है. लेकिन अब वे जम्मू सचिवालय से चीख-चिल्ला रहे हैं कि वहां मुजाहिद हैं, हम वहां नहीं जाएंगे. क्या कल तक वे मुजाहिद नहीं थे? कश्मीर के लोग मानते हैं कि 90 के दशक में कुछ राजनीतिक पार्टियों व मिलिटेंट्स ने उनको निशाना बनाया, जो गलत था. लेकिन उसके बाद से आज तक किसी ने कश्मीरी पंडितों पर हाथ नहीं उठाया. जो लोग यहां हैं, वे बड़े आराम से यहां रह रहे हैं. तत्कालीन गवर्नर जगमोहन ने रातो रात कश्मीरी पंडितों को यहां से किस तरह बाहर निकलवाया, ये पूरी दुनिया जानती है.

जब-जब यहां यात्रा आई, कभी यात्रियों पर कोई हमला नहीं हुआ. 2008-2010 में जब वहां हिंसा का दौर जारी था, तब सरकार ने खुद अंदेशा जताया कि शायद अमरनाथ यात्रियों पर हमला हो. हर बार सरकार ने अंदेशा जताया, लेकिन कभी अमरनाथ यात्रियों पर हमला नहीं हुआ. सरकार ने हमेशा अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा दी, लेकिन कभी उन पर हमला नहीं हुआ. आज इतने खराब हालात में भी यात्रा चली, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं हुआ. केंद्र सरकार हमेशा हमले की आशंका जताकर हाइप क्रिएट करती है, लेकिन उनपर कोई हमला नहीं होता है. इसके बदले, उनके यहां आने से हमारे बाजार में व्यापारिक गतिविधियां और बढ़ जाती हैं. वे धार्मिक यात्रा के लिए यहां आते हैं और दो-चार दिन

क्या इन बीस सालों में किसी कश्मीरी को किसी ने एक थप्पड़ भी मारा है. कश्मीरी पंडित यहां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं. उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाती है. उन्हें आने-जाने के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई जाती हैं. कश्मीरी पंडितों को दर्जनों पैकेज दिए गए हैं. हिंदुस्तान के हर कोने में कश्मीरी पंडित इज्जत से बसा है.

बाद यहां से चले जाते हैं. यहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं. लेकिन इन बीस सालों में एक भी टूरिस्ट को न तो यहां लूटा गया और न ही उनपर हमला हुआ. क्या यहां से हर टूरिस्ट सुरक्षित वापस नहीं लौटा है? एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि हिन्दू होने के कारण उसे वहां परेशान किया गया. लेकिन दिल्ली में इंटरनेशनल टूरिस्ट्स के साथ क्या हो रहा है? दिल्ली, मुंबई और न जाने कितने राज्यों से विदेशी टूरिस्ट्स के साथ दुष्कर्म की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं. वहीं, कश्मीर में दुनिया भर से टूरिस्ट्स आते हैं, वे अकेली आती हैं और हफ्तों यहां रहती हैं, लेकिन उनके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म की एक भी घटनाएं सामने नहीं आईं. दिल्ली में होटल तो जानें दें, एम्बेसी में भी राजदूतों के साथ बदतमीजी की घटनाएं होती हैं. कुछ दिनों पहले इजराइल की किसी टूरिस्ट के साथ दुष्कर्म हुआ है, ये किसी को नहीं दिखता है. लेकिन कश्मीर जैसे टूरिस्ट स्टेट में ऐसा कोई अपराध नहीं है, जिससे टूरिस्ट नाराज हों. लेकिन टूरिस्ट सीजन में तमाम एयरलाइंस कश्मीर की रेट दोगुनी तिगुनी बढ़ा देते हैं. सरकार से हर साल यह पूछा गया कि इस सीजन में एयरलाइंस रेट क्यों बढ़ा देते हैं? सर्दियों के मौसम में दो या तीन हजार में टिकट मिलती हैं, जबकि इस सीजन में बीस हजार की टिकट मिलती हैं. मुफ्ती मुहम्मद बराबर एयरपोर्ट अथॉरिटी से इस बात के लिए लड़ते रहे. वे कहते रहे कि आप ऐसा कीजिए कि पूरे साल एक ही रेट में टिकट मिले, जैसा शिमला, हिमाचल या मसूरी के लिए होता है. आप यहां के रेट्स बढ़ाकर टूरिस्ट को लूटते हैं. कश्मीर के लोग उन टूरिस्ट्स को लेकर फिक्रमंद हैं कि टिकट के रेट बढ़ाकर उन्हें (शेष पृष्ठ 5 पर)

कश्मीर : बैलेट बड़ा या पैलेट

पृष्ठ 4 का शेष

कश्मीरी लीडरों को बदनाम कर दिया. यह सिलसिला 1953 से शुरू हुआ था जब शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहते गिरफ्तार किया गया था. वह अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गुलमर्ग गए थे. वहां एक डीएसपी साहब ने उनके दरवाज़े पर दस्तक दी और शेख अब्दुल्ला से कहा कि उनके ख़िलाफ गिरफ्तारी का वारंट है. लोगों को लगा कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी रैंक के अफसर को भेजना सरासर बेइज्जती थी. हालांकि कश्मीर में यह भी कहा जाता है कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ही कश्मीर को प्लेट में रख कर उसे भारत सरकार को दे दिया था. शेख अब्दुल्ला खुद कहते थे कि पंडित जवाहरलाल उनके दोस्त हैं. उसके बाद शेख अब्दुल्ला को 11 साल तक जेल में रखा गया. उनकी जगह बख्शी गुलाम मोहम्मद को यहां का प्रधानमंत्री बनाया गया. बख्शी गुलाम मोहम्मद के बाद सादिक को लाया गया. उनके हाथों से यहां संविधान में संशोधन कराए गए, जिसकी वजह से आर्टिकल 370 कमज़ोर हो गया और जो ऑटोनोमी थी वह आहिस्ता-आहिस्ता छीन ली गई. यह पृष्ठभूमि लिखने की वजह यह है कि कश्मीरियों को आशंका है कि उनसे धीरे-धीरे सब छीना जा रहा है.

एक समस्या यह भी है कि भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा खुद ही मिस इन्फॉर्म्ड है. उसे ज़मीनी हकीकत का पता नहीं. मिसाल के तौर पर कुछ चैनल कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सौ करोड़ रुपये भेज कर यहां इतना बवाल मचा दिया है. लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान यही सौ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में या किसी अन्य राज्य में भेजता तो क्या वहां भी इतना हंगामा हो जाता. नहीं, दरअसल कश्मीर में हंगामे की जमीन तैयार है. यह जमीन खुद भारत सरकार ने तैयार की है. लोगों को धोखे में रख कर, लोगों के अधिकार छीन कर. ज़ाहिर है, पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठा रहा है. 23 जुलाई को कश्मीर मामले पर पाकिस्तानी संसद का जॉइंट सेशन शुरू हुआ. इस से पहले कैबिनेट मीटिंग हुई थी. उसके बाद उन्होंने काला दिवस भी मनाया था. उन्होंने अधिकारिक तौर पर बुरहान को शहीद का दर्जा दिया था. उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने कश्मीर का मसला उठाया. दरअसल उन्होंने इसके अंतरराष्ट्रीयकरण की कोशिश की. ज़ाहिर है, पाकिस्तान स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है.

पाकिस्तान में हाफिज सईद है, जो एक दुनियाभर में जाना पहचाना आतंकवादी है. वह भी अपनी अहमियत जताने के लिए कश्मीर के साथ खुद को जोड़ रहा है. बल्कि उसने इस हद तक झूठ बोला कि वह बुरहान के सम्पर्क में था. खुद पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां लोग मस्जिदों में विस्फोट करते हैं, इमामबाड़ों में विस्फोट करते हैं, ईदगाहों में विस्फोट करते हैं, सड़कों पर, बाजार में विस्फोट करते हैं. तो जो लोग अपनी मस्जिदों को नहीं देखते है, वह मंदिरों को क्या देखेंगे. कश्मीर पुलिस कह रही है कि बुरहान कभी पाकिस्तान नहीं गया था, बल्कि उसने औपचारिक रूप से कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली. वह तो हीरो टाइप का मिलिटेंट था, जिसने मिलिटेंसी को ग्लैमराइज किया था. दिन भर फेसबुक पर रहता था. राज्यसभा सांसद मुज़फ्फर बेग ने संसद में अपने भाषण में कहा भी कि बुरहान कोई ओसामा बिन लादेन नहीं था, उसको जिंदा भी पकड़ा जा सकता था. उसे पकड़ा क्यों नहीं गया. उसके सिर पर दस लाख रुपये का इनाम भी किसी की समझ में नहीं आया.

अभी जो हालत हैं, इसको बहुत सारे सियासतदां हवा भी देते हैं. मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को शक है कि अगर 20 से 25 दिन तक यह स्थिति बनी रही तो गवर्नर रूल आ जाएगा और उसके बाद मध्यावधि चुनाव होंगे. जब दुबारा चुनाव होंगे तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि पीडीपी की हालत ख़राब हो गई है. पीडीपी का मजबूत गढ़ साउथ कश्मीर था, वहां इतने लोग मारे गए, इतनी तबाही हुई. ज़ाहिर है दक्षिण कश्मीर के लोग अब पीडीपी को वोट नहीं देंगे. तो कयास लगाए जा रहे हैं कि अब तो उमर अब्दुल्ला की सरकार बनेगी. अब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी सक्रिय हो गए हैं. वह भी अपनी तरफ से चाहते हैं कि प्रदर्शन को और लम्बा खींच दें, जितनी तबाही हो जाए. कुल मिला कर देखें तो कनफ्लिक्ट जोन में कुछ खास लोगों का खास इंटरेस्ट होता है इसमें. आमलोग तो बस कच्चा माल होते हैं, जो इस्तेमाल होने के लिए ही पैदा होते हैं. अब देखिए कि मणिपुर में भी अफस्पा (आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पॉवर एक्ट) लागू है, लेकिन वहां की कोई बात नहीं करता. क्योंकि वहां की ख़बरें नहीं आतीं, वहां कोई सपोर्ट नहीं है. पंजाब में मिलिटेंसी को समाप्त किया गया. लेकिन कश्मीर में ऐसा हो नहीं सकता, उसकी वजह है इसके पीछे लगा हुआ पाकिस्तान, जो इसे भुनाने की हर पल कोशिश करता है. पचास लोग मरे तो पूरी दुनिया में कोहराम मच गया. अमेरिका और चीन के बयान आ चुके. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दो बयान दिए, ईरान के संसद में इस मसले को उठाया गया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने इस पर स्टेटमेंट दिया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा कि जांच होनी चाहिए कि पैलेट गन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है. यानि आप कश्मीर को मणिपुर के साथ लिंक नहीं कर सकते.

कश्मीर के लोग मानते हैं कि भाजपा का तो एजेंडा है कि आर्टिकल 370 खत्म कर दिया जाए. कश्मीर में शांति कैसे आएगी, जब आर्टिकल 370 ख़त्म करने की बात होगी. कश्मीरी चाहते हैं कि पुराना वाला तंत्र पुनः स्थापित हो जो 1953 में लागू था. ये बातें यहां के बुद्धिजीवियों की है. एक संपादक हैं, कश्मीर में एक अख़बार चलाते हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं. वह कहते हैं कि भारत सरकार के लिए यही मौक़ा है कि अगर वह कोई सियासी पहल करती है, नरमी का बर्ताव करती है तो हालात सुधर सकते है. हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तीन बड़े लीडर हैं, सैयद अली शाह गिलानी, मीर वायेज उमर फारूक और यासीन मालिक. उन तीनों लीडरों को महीनों से नजरबंद रखा गया है. उनके फोन नहीं चल रहे हैं, उनके पास इन्टरनेट सुविधा नहीं है.

ज़ाहिर है, उनके यहां सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, वो तो हंगामे करेंगे ही. दबाने की जितनी कोशिश होगी, वह उतना ही उभर कर सामने आएगा. यह सब कुछ केवल पाकिस्तान का किया धरा नहीं है. भारत सरकार भी पाकिस्तान के लिए जमीन तैयार करती है.

देश ऐसे भी लोग हैं, जिनको ज़मीनी हकीक़त पता है. वजाहत हबीबुल्ला के हालिया बयान का लोग हवाला देते हैं कि कश्मीरियों को मजबूर किया गया. यासीन मालिक ने तो हथियार डाल दिया था. जेकेएलएफ पहले मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था. यासीन मालिक उसके चीफ थे. फिर कुलदीप नय्यर, अरुंधती राय, गौतम नौलखा, राम जेठमलानी और वजाहत हबीबुल्ला जैसे बहुत सारे लोग उससे मिलने रहे. यह विश्वास दिलाया कि हमने भारत सरकार से बात की है, आप हथियार डाल दो, मिलिटेंट आर्गेनाईजेशन को पॉलिटिकल आर्गेनाईजेशन में बदलो. यासीन मालिक ने ऐसा ही किया. उसने दोबारा बंदूक नहीं उठाई. लोग पूछते हैं कि उसके बाद केंद्र सरकार ने क्या किया? सरेंडर करने के बाद भी उसके कई लोग मार दिए गए. एक लीडर हाथ में आ गया था, उसे भी खो दिया. केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 23 जुलाई को श्रीनगर आए थे तो उन्होंने यहां बहुत सारे लोगों से बात की. व्यापारियों को बुलाया गया था. वो आए नहीं उनसे मिलने. लेकिन उमर अब्दुल्ला अपनी पार्टी के दस नेताओं के साथ राजनाथ से मिले. उमर अब्दुल्ला ने उन्हें एक मेमोरेंडम दिया. वह मेमोरेंडम दूसरे दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्थानीय अखबारों में प्रकाशित भी करवाया. उसमें मांग की गई थी, अफस्पा हटाओ, सुरक्षा बलों को नियंत्रण में रखो, राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करो, हुर्रियत नेताओं को रिहा करो, उनके साथ बातचीत करो और राजनीतिक बंदियों को रिहा करो. उसी तरह सरताज मदनी के नेतृत्व में पीडीपी का एक प्रतिनिधिमंडल

पृष्ठ 4 का शेष

लूटा जा रहा है. पहली स्नो फॉल की खबर आते ही टेलीविजन पर हर जगह हिमाचल की बर्फबारी छा जाती है, लेकिन कश्मीर की कोई खबर नहीं आती. गुलमर्ग में स्पोर्ट्स होने पर शायद ही कोई चैनल वहां की कवरेज देता है. हिमाचल में एक सेंटीमीटर बर्फ हो जाए, तो चैनल वहां की कवरेज इसलिए दिखाने में लग जाते हैं, ताकि टूरिस्ट हिमाचल जाएं, यहां न आएं. कश्मीरियों के साथ यह भेदभाव पहले से होता रहा है.

कश्मीर की जनता त्रिपक्षीय बातचीत चाहती है, क्योंकि आधा कश्मीर भारत में है तो आधा पाकिस्तान में. केंद्र सरकार को एक टेबल पर बैठकर बात करनी होगी और इसमें कश्मीरियों की राय बहुत जरूरी है. अगर यहां के बारे में फैसला हो रहा है, तो यहां के लोगों से पूछा जाना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं? कश्मीर के लोग खुलकर कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों ने भी हमें कुछ नहीं दिया है. उनको जो भी मिला दिल्ली से ही मिला. जब महबूबा विपक्ष में होती हैं, जब उमर साहब विपक्ष में आते हैं तो खूब बोलते हैं, लेकिन ये जैसे ही सत्ता पर आ जाते हैं, वैसे ही दिल्ली की बोली बोलने लगते हैं. कश्मीर की जनता हमेशा सांसत में ही रहती है, उसे अगर थोड़ी सी राहत मिलती है, तो हुर्रियत टाइट हो जाती है और अगर हुर्रियत से छूट मिलती है तो पुलिस वाले टाइट हो जाते हैं यानी यह एक तरह से दोतरफा युद्ध की स्थिति है. यानी अगर ये छूट दे रहा है तो वो सख्ती कर रहा है और ये छूट दे रहा है तो वो सख्ती कर रहा है. ये दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन बीच में आम आदमी पिस रहा है.

बुरहान वानी की मौत के अगले दिन नौ जुलाई की सुबह से ही घाटी में टेलीफोन सेवा ठप्प कर दी गई. क्या आज लोग टेलीफोन के बिना रह सकते हैं? बच्चे, रिश्तेदार, मरना-जीना, त्यौहार, कौन जिंदा है, किस इलाके में कौन मर गया, यहां के लोगों को कुछ पता नहीं है. यहां के लोग अपने रिश्तेदारों से, बाहर पढ़ रहे अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते या उनके बच्चे व रिश्तेदार फोन कर उनसे हालचाल नहीं ले सकते. ऐसे हालत हैं यहां पर. सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही है. आतंकवादियों को, चाहे उनकी गलती रही हो या नहीं, मार दिया गया, लेकिन यहां के लोग तो रोज मर रहे हैं. यहां के लोग काफी सख्ती में रह रहे हैं, काफी मुश्किलों में जी रहे हैं. गिलानी साहब को तो घर में बंद कर रखा गया, यासिन मलिक नजरबंद हैं, मीर वाइज नजरबंद हैं, लेकिन मीडिया ये नहीं कहता कि डेढ़ करोड़ कश्मीरी भी तो नजरबंद हैं. मीडिया यह नहीं कहता कि डेढ़ करोड़ गरीब, जिनमें कितने दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको भी नजरबंद कर रखा गया है. दिहाड़ी मजदूर और उनके परिवार ने शाम को अपने पेट में अन्न डाला या नहीं, इसकी चिंता किसे है? ये लोग कौन से टेररिस्ट हैं, कौन से मिलिटेंट हैं? इनको तो पता भी नहीं है कि हिंदुस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है? ये लोग कितनी सजा झेल रहे हैं पिछले पच्चीस सालों से. इन दिनों कम से कम एक हजार शादियां कैंसिल हुईं. हुईं भी तो बड़ी सादगी से. मतलब जो बीस-पच्चीस साल की लड़की या तीस साल के लड़के की शादी होनी थी, उनके सपने, उनकी भावनाएं सब कुछ पर पानी फिर गया. जब यहां के हालात ठीक हो जाएंगे, तब क्या वे नई शादी करेंगे? ये जो ख्वाब टूटते हैं, यही लोग मिलिटेंट बनते हैं. ये जब ख्वाब टूटते हैं, तो यही आक्रोश जमा हो जाता है, जो वक्त आने पर फूटता है. चाहे वो मर्द हो या औरत, अनपढ़ हो या पढ़ा-लिखा. तभी हर कश्मीरी की जुबान से गुस्से वाली बात निकलती है. हर कश्मीरी मिलिटेंट नहीं है, लेकिन हर कश्मीरी यह सख्ती देखते-देखते, बर्दाश्त करते-करते पक गया है.

पिछले दिनों रविवार को यहां कॉमन ट्रेंट्स टेस्ट, नीट था. छात्रों के लिए स्थानीय प्रशासन ने गाड़ियां मुहैया करा दीं. पांच बजे सुबह बच्चे जमा हो गए और सरकार ने अलग-अलग सेंटर्स पर ले जाकर उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण एक्जाम दिला दिया. एक्जाम बेहतर तरीके से हो भी गया. लेकिन आजकल कौन ऐसा बच्चा है जो इंटरनेट से पढ़ाई नहीं करता है. इंटरनेट फ्री है, एक्सेसबल है, मोबाइल है. एक बच्चा दो हजार रुपये की किताब न लाकर बीस रुपए का नेट पैक डालकर पढ़ाई कर सकता है. इतने दिनों से नेट बंद पड़ा है और दुनिया को दिखाने के लिए बच्चों को परीक्षा केंद्र पर भेज दिया गया. क्या लिखेंगे बच्चे वहां पर? उसने तो नेट खोला ही नहीं है इतने दिनों से, तो वो क्या लिखेगा? बच्चों का एडमिशन कार्ड डाउनलोड करके दे दिया गया, आने-जाने के लिए गाड़ी दे दी, सेंटर पर पहुंचा दिया, प्रशासन की ड्यूटी खत्म हो गई. दुनिया को सरकार ने दिखा दिया कि वे लोग बहुत केयरिंग हैं. लेकिन ये कहीं पर बात नहीं आई कि उस बच्चे ने तो सोलह-सत्रह दिनों से नेट ही नहीं खोला तो ये लिखेगा क्या? एक मोबाइल ऐसे बच्चों के लिए लाइफलाइन है.

हर पॉलिटिकल पार्टी, हर चैनल से यही कहा जाता है कि कश्मीर के युवाओं की भावनाओं को समझिए, उनको एड्रेस करिए. उनको समझने की कोशिश करिए. कश्मीर के लोग मानते हैं कि ये रातो रात नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा.

इसके लिए केंद्र सरकार को विश्वास बहाल करने के जितने प्रयास करने थे, वे किए जाने चाहिए थे. कश्मीरी युवकों के साथ जुड़कर, पॉलिसीज के साथ कनेक्ट होकर, आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सरकार कश्मीरियों की भावनाएं जीत सकती थी. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा. 1988 में जो लोग मिलिटेंट्स थे, वही लोग आज हुर्रियत के लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी हताशा को खत्म करने के लिए मफ के नाम से चुनाव लड़ा था. मफ यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, एमयूएफ. खबर थी कि पार्टी के सभी उम्मीदवार जीत रहे हैं, मिठाइयां भी बंट गईं. तब शाम को दूरदर्शन पर आने वाली खबर में सब को हारा हुआ बता दिया गया. 1988 में हुर्रियत हार गया और 1989 में कश्मीर में मिलिटेन्सी शुरू हो गई. सिर्फ और सिर्फ यह हुर्रियत से प्रेरित था और सरकार से बदला था जो आजतक चल रहा है. चुनाव में धपला किया गया. अगर यह नहीं होता तो वही नेता राजनीति की मुख्य धारा में होते. जिनसे आज चुनाव लड़ने की मिन्नतें की जा रही हैं. जिस तरह से आज शर्मिला इरोम ने मणिपुर में कहा है कि अफ्सपा नहीं हट सकता है, अब मैं अपनी भूख हड़ताल खत्म कर चुनाव लड़ूंगी और राजनीति की मुख्य धारा में आकर लड़ूंगी. यही बात हुर्रियत के नेताओं ने तब कही थी. उन्होंने कहा था कि हम लोग राजनीति की मुख्य धारा में आकर अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए चुनाव लड़ सकते हैं. तब उनके साथ क्या किया गया था, इतिहास गवाह है. आज उन्हीं हुर्रियत के नेताओं के हाथ में कश्मीर की लगाम है. ■

उनसे मिला था. सरताज मदनी ने भी राजनाथ सिंह को कहा कि ये मसला सियासी है, इसको सियासी तौर पर हल किया जाए. पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हाकिम यासीन ने भी गृहमंत्री से कहा कि कश्मीर का सियासी हल निकालना होगा. उसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के मोहम्मद युसूफ तारीगामी भी उनसे मिले थे. तारीगामी ने इस संवादाता को बताया कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ बिना शर्त बातचीत शुरू करने की बात कही है. बाक़ी के जो लोग मिले थे, उन्होंने भी यही कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल बंद कर राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए. राजनाथ सिंह का यह महत्वपूर्ण दौरा था. अब देखना ये है कि वे क्या करते हैं.

लब्बोलुबाव यह है कि केंद्र सरकार कश्मीरी लीडरों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए. उमर अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी केंद्र से आग्रह किया था कि अफस्पा हटाया जाए. कम से कम श्रीनगर से अफस्पा हट जाए. लेकिन केंद्र ने उस पर कोई जवाब ही नहीं दिया. महबूबा मुफ्ती भी लगातार यह कह रही हैं कि अफस्पा हटाया जाए, गठबंधन में शामिल होने के बावजूद भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार कश्मीर के चुने हुए मुख्यमंत्रियों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है. मुफ्ती मोहम्मद सईद ने भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, हुर्रियत लीडर्स के साथ बात होनी चाहिए, इससे ही समाधान का रास्ता निकलेगा, लेकिन सारी बातें अनसुनी ही रह जा रही हैं. ■

सियासी ज़मीन को उर्वरा बनाते हैं दंगे

चंदन राय

दंगे सांप्रदायिक पार्टियां नहीं रोक सकतीं, क्योंकि वे तो दंगों पर ही जीवित हैं. दंगों को अगर रोक सकते हैं, तो लोग रोक सकते हैं. असगर वज़ाहत की कहानी जख़्म का नायक आज भी देश के राजनेताओं को मुंह चिढ़ा रहा है. देश के मिजाज को समझने का दावा करने वाले राजनेताओं की सोच है कि दंगों की उर्वर जमीन पर ही राजनीति की फसल लहलहाती है, लेकिन अब जनता भी दंगों के सियासी खेल को बखूबी समझने लगी है. आइए एक नजर डालते हैं देश के सियासी माहौल पर. देश में बढ़ते सांप्रदायिक दंगों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष इसे आंकड़ों की बाजीगरी बता खारिज करता रहा है. अब गृह मंत्रालय के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं...

गृह मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले संसद में जानकारी दी कि 2016 में शुरू के पांच महीनों में देश में 278 सांप्रदायिक तनाव व दंगों के मामले दर्ज हुए. इन दंगों में 38 लोगों की मौत हुई, जबकि 903 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. वहीं 2015 में जनवरी से मई के बीच कुल 287 सांप्रदायिक हिंसा के मामले सामने आए थे, जो 2014 के मुकाबले 24 फीसद ज्यादा थे. 2015 में मई महीने तक दंगों में जान गंवाने वालों की संख्या 43 थी, जो 2014 में केवल 26 थी. 2014 के पांच महीनों का तुलनात्मक अध्ययन इसलिए जरूरी है क्योंकि इस दौरान देश में यूपीए की सरकार थी. आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 2014 के शुरू के पांच महीनों की तुलना में 2015 और 2016 में सांप्रदायिक दंगों की संख्या में वृद्धि हुई है.

अब राज्यों की बात करें तो मई 2016 तक उत्तरप्रदेश में सांप्रदायिक तनाव/ दंगों के सबसे अधिक 61 मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र में 40-40 सांप्रदायिक दंगे हुए. वहीं साल 2015 में देशभर में 751 सांप्रदायिक तनाव/दंगे हुए, जबकि साल 2014 में केवल 644 मामले दर्ज हुए थे.

मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट (2015) में भी देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि को लेकर एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था. रिपोर्ट में कहा गया कि देश की राष्ट्रवादी सरकार, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगों को रोकने में असफल रही है. इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के विधि नियंताओं व राजनेताओं ने उकसावे वाले भाषण देकर माहौल को तनाव-पूर्ण बनाया और सांप्रदायिक हिंसा को जायज ठहराने के लिए प्रतिहिंसा जैसे अनूठे तर्क दिए.

एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव पर्व के दौरान वोटिंग से जनता अपने मनोनुकूल सरकार का चयन करती है. लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? किसी राज्य में चुनाव की घोषणा होते ही जनता को सांप्रदायिक दंगा भड़कने की चिंता सताने लगती है. 2014 में उत्तरप्रदेश पुलिस ने रिकॉर्ड किया कि उन इलाकों में या उसके आस-पास सांप्रदायिक तनाव के मामलों में अचानक इजाफा हो गया था, जहां 11 विधानसभा व 1 लोकसभा के उपचुनाव होने थे. उस दौरान राज्य में सांप्रदायिक तनाव के 605 छोटे-बड़े मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें दो-तिहाई मामले उन क्षेत्रों से जुड़े थे. सवाल है कि आखिर चुनाव आते ही सांप्रदायिक दंगों में इजाफा क्यों होने लगता है? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से किन राजनीतिक दलों को फायदा होता है?

जद (यू) सांसद अली अनवर कहते हैं कि कुछ पार्टियां जान-बूझकर वोटों के ध्रुवीकरण के लिए चुनाव के समय माहौल बिगाड़ने का काम करती हैं. ऐसे में विकास की बात कहीं पीछे छूट जाती है और उनका एकमात्र सहारा यही होता है कि किसी तरह जनता में धार्मिक उन्माद पैदा हो और लोग गोलबंद होकर पार्टी को वोट दें. हाल में कुछ पार्टियों का प्रयास था कि दलितों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया जाए, लेकिन उनका यह प्रयास असफल रहा. गुजरात में पाटीदार आंदोलन को दबाने के लिए भी कुछ इसी तरह का सियासी कुचक्र रचा गया. उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टियां ही नहीं, बल्कि कुछ अल्पसंख्यक प्रेमी पार्टियां भी दंगों की आड़ में वोट बैंक का खेल खेलती हैं. असदुद्दीन ओवैसी जितना मुस्लिमों को अपने उग्र भाषणों से गोलबंद करते हैं, बहुसंख्यक उतने ही हिंदूवादी पार्टियों के साथ खड़े नजर आते हैं. वहीं, जब साक्षी महाराज, साध्वी प्राची जैसे लोग अपने उग्र भाषणों से हिंदुओं को संगठित करने का प्रयास करते हैं, तो अल्पसंख्यक किसी जिताऊ सेक्यूलर पार्टी का हाथ थाम लेते हैं. जनता को सतत् सजग व सतर्क रहने की जरूरत है तभी ऐसी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है. राजनीति का धर्मयुद्ध अब लव जिहाद, घर वापसी, गौ रक्षा में सुरक्षित आसरा ढूंढने लगा है. इन नेताओं से मोह भंग होने पर देश का बहुसंख्यक सेक्युलर तबका चुनाव से किनारा कर लेता है और ऐसे में फायदा होता है कट्टरपंथी ताकतों के रहनुमा बने तथाकथित नेताओं को.

अगर देश में सांप्रदायिक दंगे होने की वजहों पर गौर करें तो आश्चर्य होगा. जुलाई 2013 में मेरठ में दंगों का कारण एक धर्मस्थल पर लाउडस्पीकर का बजाया जाना था. म्यूजिक, धार्मिक जुलूस, गौ हत्या की अफवाह और किसी पवित्र ग्रंथ व मूर्तियों को विखंडित करने पर ही देश में दंगे भड़क उठते हैं. यहां दो परिवारों के बीच तनाव ही दंगा भड़काने के लिए काफी होता है. और अगर भूल से ये परिवार दो अलग धर्मों से हुए तो दंगे की भीषणता का अंदाजा लगाना मुश्किल है.

सांप्रदायिक दंगा विरोधी कानून पर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेंकने में लगे हैं. सांप्रदायिक दंगों और उनकी आक्रामकता में वृद्धि को देखते हुए देश में ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए, जिससे लोगों में दंगों में शामिल होने को लेकर खौफ पैदा हो. किसी इलाके में दंगा फैलता है, तो उस क्षेत्र के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार मान उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.

उम्मीद की एक किरण देश की युवा पीढ़ी से है, जिसकी ओर असगर वज़ाहत का नायक शुरू में इशारा करता है. अगर देश के जागरूक लोग इन दंगों के खिलाफ उठ खड़े हों, तो एक दंगा-मुक्त, स्वस्थ लोकतांत्रिक माहौल का निर्माण संभव है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कौशल विकास से कैसे मिलेगा रोज़गार

संगठित क्षेत्र की नौकरियों में बड़ी गिरावट

धर्मेंद्र सिंह

केंद्र में एनडीए की सरकार बने दो साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन बेरोजगारी में कोई कमी नहीं आई. 2013-2014 के मुकाबले संगठित क्षेत्र में 68 प्रतिशत रोजगार की कमी हुई है. सरकार कई तरह के दावे कर रही है, लेकिन नौजवान नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. नौकरी के लिए देश की जनता एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर रही है और सरकार पलायन रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है. नरेंद्र मोदी को युवाओं ने इस आशा के साथ चुना था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उनके अच्छे दिन आएंगे और उनको रोजगार मिलेगा. लेकिन अच्छे दिनों की बाट जोह रहे युवाओं को निराशा हाथ लगी है. साथ ही रोजगार का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह अच्छी खबर नहीं है. एक साल पहले सरकार ने बेरोजगारों खासकर युवाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की थी जिसके तहत युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो नौकरी पा सकें. केंद्र सरकार ने स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी बनाया है और बिहार के छपरा से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी स्किल डेवलपमेंट मंत्री हैं. मोदी सरकार और उसके मंत्री रोजगार को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. लोकसभा में पेश किए सरकारी आंकड़े मोदी सरकार और उसके मंत्रियों के दावों की पोल खोल रहे हैं. आंकड़े बताते हैं कि देश के युवाओं को राष्ट्रीय कौशल विकास योजना से कितना फायदा होगा? लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2013-2014 के मुकाबले 2015 में संगठित क्षेत्र में मिलने

वाली नौकरियों में 68 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो चिंता की बात है. मोदी सरकार द्वारा पेश किए आंकड़ों के मुताबिक 2015 के दौरान भारत में एक लाख तीस हजार नौकरियां सृजित हो पाईं, जबकि 2013 में चार लाख नौकरियां सृजित हुई थीं और 2014 में भी यही स्थिति रही. यह आंकड़ा मानसून सत्र के दौरान 20 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया था. भारत में औपचारिक सेक्टर से 10 प्रतिशत लोग जुड़े हैं. भारत में हर महीने एक लाख नौकरी की आवश्यकता है और साल में 12 लाख. सरकार ने जो आंकड़ा पेश किया है, उसमें कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी शामिल है.

कपड़ा उद्योग पिछले तीन वर्षों से लगातार सबसे अधिक नौकरी देने वाला क्षेत्र रहा है. कपड़ा उद्योग में तीन साल में देखें, तो 4,99,000 नौकरियां सृजित हुई हैं. हालांकि रोजगार की गति इन वर्षों में 75 प्रतिशत धीमी रही है. वहीं सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ रोजगार सृजित करने वाला भारत में दूसरा बड़ा क्षेत्र है. इस क्षेत्र में तीन साल के दौरान 3,78,000 लोगों को नौकरी मिली. ट्रांसपोर्ट और हैंडलूम एवं पावरलूम में क्रमशः 28000 और 18000 नौकरियां सृजित हुईं. आधिकारिक तौर पर भारत में 5 प्रतिशत बेरोजगारी है जिसकी आड़ में बड़े पैमाने पर आंशिक बेरोजगारी को छुपाया जा रहा है. 2050 तक भारत में 28 करोड़ नौकरियों की जरूरत होगी. संयुक्त विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट के मुताबिक 1991 से लेकर 2013 तक 22 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व विकास हुआ. इस दौरान 30 करोड़ लोगों को नौकरी की जरूरत थी, लेकिन इनमें से केवल आधे लोगों को ही नौकरी मिली. 2015 में बीपीओ, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, मेटल के क्षेत्र में सबसे अधिक नौकरियां सृजित हुईं, वहीं इन क्षेत्रों के मुकाबले लेदर उद्योग, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, ट्रांसपोर्ट और हैंडलूम/पावरलूम में नौकरियों में कमी देखने को मिली. साल 2015 के दौरान संगठित क्षेत्र में नौकरियों में इतनी गिरावट चिंता का विषय है. यह आंकड़ा औद्योगिक विकास की स्थिति को भी दर्शाता है. इससे यह पता चलता है कि इन क्षेत्रों की हालत पहले से ज्यादा खराब हुई है जिसकी वजह से इस क्षेत्र की नौकरियों में बड़ी संख्या में गिरावट आई है. सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि क्यों इतने बड़े क्षेत्र में नौकरियों में कमी आई है. अगर यही हाल रहा तो पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए रोजगार का और संकट पैदा होगा.

सरकार का स्किल इंडिया के तहत 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को कुशल कामगार बनाने का लक्ष्य है. सरकार ने एक साल में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 1,141 नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईटीआई) खोले हैं. इनमें 1.73 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने विभिन्न कंपनियों को कुशल श्रमिकों को प्रशिक्षु (एप्रेंटिस) रखने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है. कुछ दिनों पहले स्किल इंडिया की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के लिए केंद्र सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. इसके तहत अगले चार वर्षों में एक करोड़ लोग लाभान्वित होंगे. इसके तहत करीब 60 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा. इनके अलावा 40 लाख दूसरे कामगार जिन्हें औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला है उन्हें रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (आरपीएल) का प्रमाणपत्र दिया जाएगा. अगर नौकरियां सृजित नहीं होंगी, तो बेरोजगारों को रोजगार कहां मिलेगा? सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से स्किल इंडिया की शुरुआत की थी, लेकिन अगर यही हालात रहे, तो युवा स्किल्ड होकर भी बेरोजगार ही रहेगा, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी. कौशल विकास योजना के साथ सरकार को नौकरियां भी सृजित करनी होंगी, नहीं तो स्किल इंडिया केवल नारा बनकर ही रह जाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

नक्सलियों से मुठभेड़

अर्द्धसैनिक बल के जवान ही क्यों मरते हैं?

सुनील सौरभ

बिहार के गया-औरंगाबाद जिले की सीमा से लगे नक्सल प्रभावित डुमरी नाला में 18 जुलाई 2016 को पुलिस-नक्सलियों की मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के 10 जवानों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं. पिछले एक दशक में नक्सली हमले और नक्सली-पुलिस मुठभेड़ में मगध में 50 से अधिक सुरक्षाबलों के जवानों की मौत हो चुकी है. इनमें अधिकतर अर्द्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं. कुख्यात नक्सली संदीप यादव के डुमरी नाला जंगल में होने की खबर मिलने पर औरंगाबाद के एसपी बाबू राम जंगल में कोबरा बटालियन को साथ लेकर घुसे. बरसात व घने जंगल होने के कारण पुलिस व कोबरा के जवानों को नक्सलियों पर कार्रवाई करने में काफी परेशानी हो रही थी. इतना ही नहीं, नक्सली पहाड़ी की चोटी पर थे और कोबरा बटालियन के जवानों को चढ़ाई करते हुए नक्सलियों पर कार्रवाई करनी थी. बरसात के मौसम में भी नक्सलियों ने डुमरी नाला की ओर आने वाले विभिन्न रास्तों पर सुनियोजित तरीके से लैंड माइन्स बिछा रखा था. जैसे ही सुरक्षाबलों ने कार्रवाई शुरू की, नक्सलियों ने कोबरा बटालियन के जवानों को नजदीक आते देख रिमोट से लैंड माइन्स को ब्लास्ट कर दिया. इस हादसे में कोबरा के दस जवानों की मौत हो गई और आधा दर्जन से अधिक घायल हो गए. हालांकि इस मुठभेड़ में कोबरा के जवानों ने आधा दर्जन से अधिक नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें तीन लाशें पुलिस के हाथ लगीं. मारे गए लोगों में ईनामी नक्सली प्रिंस भी शामिल था. लेकिन सवाल ये है कि नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में अधिकतर अर्द्धसैनिक बलों के जवान ही क्यों मारे जाते हैं? जबकि गया जिले के नक्सल प्रभावित शेरघाटी अनुमंडल में इन जंगली क्षेत्रों में कई पुलिस थाने बनाये गए हैं. थाने में हर पंचायत तथा गांव की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए चौकीदार नियुक्त हैं. इन सरकारी सेवकों को अच्छी-खासी वेतन राशि भी दी जाती है. चौकीदार के अलावा गांव-पंचायत स्तर पर स्पेशल पुलिस अफसर को भी मानदेय देकर थाने द्वारा गांव की गतिविधियों की जानकारी ली जाती है. इसके अलावा पुलिस पदाधिकारियों द्वारा कई सूत्र भी रखे जाते हैं, जो आतंकी-नक्सली व आपराधिक कार्यों में लिप्त लोगों के बारे में जानकारी देते हैं. इसके एवज में सूत्रों को पुलिस-पदाधिकारियों द्वारा स्पेशल फंड से राशि भी दी जाती है. इतने जासूस होने के बावजूद करीब तीन किलोमीटर क्षेत्र में लैंड माइन्स बिछाए जाने की सूचना

पुलिस को नहीं मिलना आश्चर्य की बात है. इस लैंड माइन्स को बिछाने में भी कई घंटे का समय लगा होगा. इस दौरान आस-पास के गांवों में किसी को पता नहीं चलना तमाम खुफिया तंत्र को संदेह के घेरे में डालता है. सवाल ये है कि जंगली इलाकों में स्थित पुलिस-थानों में पुलिसकर्मी आराम से अपनी ड्यूटी निभाते नजर आते हैं. आसान टारगेट होने के बावजूद उन पर नक्सलियों का हमला नहीं होता है. कुछ ऐसे पुलिस थानों पर नक्सलियों के हमले हुए तो उसके कुछ विशेष कारण रहे हैं. लेकिन अर्द्धसैनिक बलों के जवान जब नक्सलियों पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत सफलता नहीं मिल पाती है. पुख्ता जानकारी होने के बावजूद अर्द्धसैनिक बलों की कार्रवाई से नक्सली बच निकलते हैं. स्पष्ट है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित थानों की पुलिस और नक्सलियों के सफाए के लिए तैनात अर्द्धसैनिक बलों में समन्वय का अभाव है. यह बात हमेशा से उठती आई है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डुमरीनाला जंगल में नक्सली दस्ते के होने की सूचना औरंगाबाद एसपी की सुरक्षा में लगे एक जवान को थी. उसने एसपी को पूरी जानकारी दी. बताया जाता है कि उस जवान ने दूसरी ओर नक्सली कमांडर को भी यह सूचना दे दी कि कोबरा के जवान जंगल में घुस गये हैं. इस सूचना के बाद नक्सलियों ने अपनी रणनीति बदल ली. वे फायरिंग कर पीछे हटते गए और बिछाये गए लैंड माइन्स का विस्फोट कर दिया, जिसमें कोबरा के दस जवानों की मौत हो गयी. वहीं घायल जवानों के इलाज में लापरवाही बरते जाने का मामला भी सामने आया. यदि हेलिकॉप्टर समय पर घटनास्थल पर पहुंच जाता तो कम से कम पांच जवानों को मौत से बचाया जा सकता था. लापरवाही का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घटनास्थल पर 25 घंटे तक शहीद जवानों की लाश पड़ी रही. जब बिहार पुलिस के आईजी ऑपरेशन कुन्दन कृष्णन हेलिकॉप्टर लेकर शहीद जवानों की लाश लाने पहुंचे, तो कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेट चंदन कुमार भड़क उठे. उन्होंने कहा कि जब जवानों की जान बचाने के लिए हेलिकॉप्टर की जरूरत थी, तब तो नहीं आया, अब क्या जरूरत है हेलिकॉप्टर की. इन सवालों ने बिहार पुलिस की कार्यशैली, थाने में पदस्थापित पुलिसकर्मियों व चौकीदारों को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया है. कोबरा के एक डिप्टी कमांडेट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन ग्रीन हंट और यूनिफाइड कमांड पर भी सवाल उठाये. एक पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि बिहार में ऑपरेशन ग्रीन हंट नहीं चलने के कारण भी दूसरे राज्यों से खदेड़े गए नक्सली यहां शरण ले रहे हैं. एक पुलिस पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बिहार में नक्सलियों के खिलाफ चलने वाले ऑपरेशन में लगी जिला पुलिस, एसटीएफ, बीएमपी, सैफ, एसएसबी, सीआरपी और कोबरा के बीच बेहतर समन्वय के लिए कोई यूनिफाइड कमान नहीं बनाई गई है. इसी का नतीजा है कि नक्सल उन्मूलन अभियान को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका है. जबकि हाल के वर्षों में घटना स्थल के आस-पास छकरबंधा, भदवर, मैगरा, लुटुआ और सुहेल में नया थाना खोला गया है. इसके बावजूद इन इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ कोई कार्रवाई सफल नहीं हो पाती. एक-दो निचले स्तर के नक्सलियों को पकड़कर ही पुलिस अपनी वाहवाही लूटने में लगी रहती है. गिरफ्तारी के बाद भी लेवी वसूलने वाले नक्सलियों की संपत्ति जब्ती का इस वर्ष एक भी प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सका है. वहीं राजनीतिक कारणों से भी नक्सली कांडों में मुख्यधारा के लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को फंसाने-छुड़ाने का खेल चलता रहता है. पिछले एक दशक में मगध के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों पर कार्रवाई के नाम पर पानी की तरह पैसे बहाये गए, लेकिन नक्सल उन्मूलन की कार्रवाई सिर्फ छापेमारी और गिरफ्तारी तक ही सीमित रही. जेल भेजे गए नक्सलियों के खिलाफ पुख्ता और मान्य साक्ष्य जुटाने और उन्हें सजा दिलाने और लेवी के नाम पर उगाही की गई संपति को जब्त करने के मामले में पुलिस के हाथ अक्सर खाली ही रहे हैं. यही वजह है कि नक्सलियों की ओर से लेवी के रूप में वसूली जाने वाली धन उगाही पर रोक नहीं लगाई जा सकी है. निर्माण योजनाओं की राशि का एक अंश नक्सलियों की हथियार खरीद पर खर्च हो रहा है. पत्थर उत्खनन, वन कटाई, विकास पर खर्च होने वाली राशि का एक अंश, अफीम-गांजे की खेती, ईंट-भट्ठा और दूसरे व्यवसायों से भी नक्सलियों को नियमित रूप से लेवी मिल रही है. नक्सलियों को मदद पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, अभी तक थानों में ऐसी सूची भी तैयार नहीं हुई है. वहीं कई नक्सली घटनाओं के एक दशक गुजर जाने के बाद भी सरगनाओं के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है.

> **एक-दो निचले स्तर के नक्सलियों को पकड़कर ही पुलिस अपनी वाहवाही लूटने में लगी रहती है. गिरफ्तारी के बाद भी लेवी वसूलने वाले नक्सलियों की संपत्ति जब्ती का इस वर्ष एक भी प्रस्ताव तैयार नहीं किया जा सका है. वहीं राजनीतिक कारणों से भी नक्सली कांडों में मुख्यधारा के लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को फंसाने-छुड़ाने का खेल चलता रहता है. पिछले एक दशक में मगध के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों पर कार्रवाई के नाम पर पानी की तरह पैसे बहाये गए, लेकिन नक्सल उन्मूलन की कार्रवाई सिर्फ छापेमारी और गिरफ्तारी तक ही सीमित रही.**

सवाल आईएपी योजना के पैसे पर भी उठाये जा रहे हैं. देश में नक्सलियों के खतरे बढ़ने पर केन्द्र सरकार ने 2009 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए इंटीग्रेटेड एक्सल प्लान शुरू किया था. मगध के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इसका असर कहीं नहीं दिख रहा है. इस योजना के तहत कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को शामिल किया गया था. 2010 में कर्नाटक को इस योजना से अलग कर दिया गया. 2011 में नौ राज्यों के 83 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया. गया शुरू से ही इस योजना में शामिल है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट को कार्यान्वित करना और पुलिस संगठन को सुदृढ़ करना था. लेकिन सात साल बीत जाने के बाद भी गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आईएपी योजना का कोई असर दिखाई नहीं देता है.

मुठभेड़ में कोबरा जवानों की मौत से बिहार पुलिस के साथ-साथ बिहार के शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं. नक्सलियों को अपरोक्ष रूप से मदद करने वाले राजनीतिज्ञ भी इस घटना के बाद मौन साधे हैं. अर्द्धसैनिक बलों के जवानों में बिहार पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है. स्थानीय स्तर पर पूरी जानकारी होने के बावजूद पुलिस अर्द्धसैनिक बलों को पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराती है, जिसकी कीमत अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को जान देकर चुकानी पड़ रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

बंदूक़ और बात साथ नहीं चल सकती

पाकिस्तान एक निरंतर समस्या रहा है और आगे भी रहेगा. पाकिस्तान जिस मुद्दे पर भी भारत से बात करना चाहता है, भारत उसपर बात करने के लिए तैयार है. लेकिन, बातचीत उस वक्त होगी, जब बंदूकें ख़ामोश हो जाएंगी. जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़ुद कहा कि जब बम धमाकों की आवाज़ें इतनी तेज़ होंगी तो हम बात कैसे कर पाएंगे, आप मेरी आवाज़ कैसे सुन पाएंगे? पहले ज़मीनी स्तर पर शांति लाइए, फिर बात कीजिए. मैं यशवंत सिन्हा की इस राय से इत्तेफ़ाक़ रखता हूं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिए. अगर दूसरा पक्ष बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है तो फिर आप बात करने के लिए क्यों जाते हैं. हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते. कुछ बुनियादी बातों पर सहमति होनी चाहिए जिसके आधार पर आगे की बातचीत हो. लिहाज़ा, बात करने के लिए उत्सुकता दिखाना केवल भारत की ही ज़िम्मेदारी नहीं है.

संसद परिसर में भगवंत मान का वीडियो बनाना सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर चूक हो सकती है और इस मामले में कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है. हालांकि, पूरे मुद्दे पर विचार करें, तो चेंबर के भीतर संबंधित सदस्य के लिए लोकसभाध्यक्ष की एक छोटी सी टिप्पणी ही काफी होती. इसकी जगह 9 सदस्यीय कमेटी बनाना जरूरी नहीं था. ज़ाहिर है, इसकी शुरुआत सत्ताधारी दल की तरफ से हुई होगी, जो इस मसले को पेचीदा बनाना चाहती है. यह लोकसभा के काम करने का तरीका नहीं है. असल में, यह कुछ मायनों में लोकसभा की अवमानना ही है. इस मसले के लिए कई बेहतरीन नियम हैं. लोकसभाध्यक्ष को पूरा अधिकार है कि वो इन नियमों का खुद इस्तेमाल करें. चूंकि, लोकसभाध्यक्ष सत्ताधारी दल से हैं, लेकिन उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, फ्री और फेयर तरीके से काम करते हुए दिखना चाहिए. अब इस कमेटी को चाहिए कि वो मान को चेतावनी दे कि पहली बार उनसे इस तरह की ग़लती हुई है, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए. और, बस यहीं मामले को ख़त्म कर देना चाहिए.

दूसरा मामला है महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना गठबंधन का, जहां वे सत्ता में भी हैं. महाराष्ट्र में यह गठबंधन कुछ बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है. जब बाला साहब ठाकरे जीवित थे तब भाजपा व शिवसेना के बीच गठबंधन बहुत सही तरीके से चल रहा था. उस दौरान प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे भी थे. उन दिनों दोनों पार्टियों के बीच बेहतर आपसी समझ थी. अभी जनता के बीच ये लोग जिस तरह से बयानबाज़ी कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है. इससे सरकार की प्रतिष्ठा को ही नुकसान हो रहा है. अब या तो भाजपा एक स्टैंड लेकर गठबंधन को ख़त्म कर दे. अगर भाजपा को ऐसा लगता है कि वो बहुत अधिक लोकप्रिय है तो फिर क्यों नहीं एक चुनाव करा लेती है. इस तरह की बयानबाज़ी का कोई मतलब नहीं है. वास्तविक राजनीति की बात करें तो कांग्रेस और एनसीपी को एक साथ और भाजपा और शिव सेना को एक साथ होना चाहिए. यह ठीक राजनीति होगी. लेकिन, कोई पार्टी अपनी तरफ से बयानबाज़ी करने लगे तब तो फिर अंतिम निर्णय जनता की अदालत में ही होगा. मुंबई के निगम चुनाव आ रहे हैं. वे चुनाव शिव सेना के लिए महत्वपूर्ण हैं. भाजपा चाहे तो यह चुनाव अकेले लड़ सकती है. अच्छा यह होगा कि दोनों पार्टियों के नेता मिल कर बैठें, बात करें और समस्या का समाधान निकालें. मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे को लगातार एक-दूसरे के संपर्क में रहना चाहिए, यही एकमात्र समाधान है.

इसके बाद एक अहम मुद्दा आता है, पड़ोसी के साथ रिश्ता. पाकिस्तान एक निरंतर समस्या रहा है और आगे भी रहेगा. पाकिस्तान जिस मुद्दे पर भी भारत से बात करना चाहता है, भारत उसपर बात करने के लिए तैयार है. लेकिन, बातचीत उस वक्त होगी, जब बंदूकें ख़ामोश हो जाएंगी. जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़ुद कहा कि जब बम धमाकों की आवाज़ें इतनी तेज़ होंगी तो हम बात कैसे कर पाएंगे, आप मेरी आवाज़ कैसे सुन पाएंगे? पहले ज़मीनी स्तर पर शांति लाइए, फिर बात कीजिए. मैं यशवंत सिन्हा की इस राय से इत्तेफ़ाक़ रखता हूं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिए. अगर दूसरा पक्ष बातचीत में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है तो फिर आप बात करने के लिए क्यों जाते हैं. हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते. कुछ बुनियादी बातों पर सहमति होनी चाहिए जिसके आधार पर आगे की बातचीत हो. लिहाज़ा, बात करने के लिए उत्सुकता दिखाना केवल भारत की ही ज़िम्मेदारी नहीं है.

दूसरी बात ये कि नेपाल के साथ अपने संबंधों में इस बात का ख्याल रखिए कि वह दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है. लेकिन, आप उसके साथ संबंधों को संभाल नहीं पा रहे हैं. आपने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वहां के प्रधानमंत्री भारत से अधिक चीन के साथ खुश दिख रहे हैं. यह एक कमज़ोर कूटनीति, कमज़ोर राजनीति और कमज़ोर विदेश नीति का परिणाम है. बहरहाल, नेपाल में हालात ठीक हो रहे हैं और वहां नए प्रधानमंत्री का चुनाव होना है. ऐसे में हमें पुरानी ग़लतियां फिर से नहीं दुहरानी चाहिए. हमें बिग ब्रदर का व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए. हम उन्हें डरा या धमका नहीं सकते हैं. इससे हालात और ख़राब होंगे. नेपाल के साथ हमारे संबंध सैकड़ों साल पुराने हैं. अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखें, तो सीता और जनक का संबंध नेपाल से ही था. हमें अपना दिल बड़ा करना चाहिए. उदारता दिखानी चाहिए. आख़िरकार, नेपाल के लाखों नागरिक भारत में काम कर रहे हैं. कभी भी आप उनके इंधन की आपूर्ति रोक देते हैं. ठीक है कि मधेसी, पहाड़ी लोगों से नाराज हैं. हम खुले तौर पर मधेसियों का पक्ष लेकर यहां के प्रधानमंत्री की मुश्किलें नहीं बढ़ा सकते. नेपाल को संभालना आसान है, लेकिन उसके लिए सही राजनयिक की नियुक्ति करनी होगी जो सही तरीके से काम कर सके, जिसे पीएमओ और विदेश मंत्रालय से सही निर्देश मिले, ताकि समस्या का समाधान हो सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

काम करने की ज़रूरत है

कवर स्टोरी-मोदी जी! लोगों के विश्वास के साथ शासन करिए...,नीयत सही नीति बदलिए(25 जुलाई- 31 जुलाई 2016) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. इस कवर स्टोरी में कुछ ऐसी जानकारियां हैं, जिससे लोग अनभिज्ञ हैं. मैं कमल मोरारका से सहमत हूं कि लोकतंत्र में अगर फ्री एंड फेयर (भयमुक्त और निष्पक्ष) चुनाव होते हैं, तो जो भी सत्ता में आता है, उसे आपको स्वीकार करना होता है. भले ही आपने उसे वोट दिया हो या नहीं दिया हो. प्रधानमंत्री केवल पार्टी का ही नहीं होता है, वह पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है. केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बने दो साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है. प्रधानमंत्री का एजेंडा है कि विकास हो, किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हो, नौजवानों को रोजगार मिले, प्रधानमंत्री अक्सर अपने भाषणों में भी इसका जिक्र करते रहे हैं. लेकिन ये केवल बोलने से नहीं होगा, इसके लिए काम करना होगा. यह सही है कि सरकार की नीयत सही है, लेकिन उसे अपनी नीति बदलने की जरूरत है.

-आभा कुमारी, *गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश.*

कश्मीर की समस्या

जब तोप मुकाबिल हो-कश्मीरियों को भी अपना समझिए (25 जुलाई- 31 जुलाई 2016) पढ़ा. बहुत अच्छा लगा. संतोष भारतीय ने अपने संपादकीय में सही कहा है कि अगर हम कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, तब हमें कश्मीर के लोगों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा हम पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से करते हैं. कश्मीर में बुरहान वानी की मौत के बाद जो तूफान उठा, वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है. कश्मीर में पेलेट गन के इस्तेमाल पर लोग अब सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि हरियाणा और गुजरात में आरक्षण को लेकर आंदोलनों के दौरान जब भीड़ पर पेलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो फिर कश्मीर में ही क्यों? यह सवाल बिलकुल वाजिब है. क्योंकि पेलेट गन बहुत खतरनाक साबित हो रही है. जब हम कश्मीर को अपना मानते हैं, तो हमें वहां लोगों को भी स्वीकार करना होगा और उन्हें अपना मानना होगा.

-अभिजीत दास, *मुखर्जी नगर, दिल्ली.*

जजों के रिश्तेदारों का बोलबाला

केंद्र ने रोकी जजों की नियुक्ति की विवादास्पद लिस्ट, पक्षपात पर बज़पात (25 जुलाई- 31 जुलाई 2016) शीर्षक लेख में प्रभात रंजन दीन ने सही कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जिन लोगों के नाम जज बनाने के लिए भेजे गए थे, उन पर कॉलेजियम की सहमति थी. यह मामला उजागर हुआ तो देश के आम लोगों को न्यायाधीशों और उनके कॉलेजियम की न्यायप्रियता का पता चला. चौथी दुनिया राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र और प्रभात रंजन दीन जिन्होंने इतने बड़े मामले को उजागर किया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं. अगर ये मामला उजागर नहीं होता, तो सभी लोग जज बन जाते और ये विभिन्न न्यायालयों में न्याय तौलते नजर आते. न्यायपालिका में नाते-रिश्तेदारों के नाम पर भ्रष्टाचार चिंता की बात है. अगर न्यायालयों में ऐसा होता रहा, तो जनता न्याय से वंचित रह जाएगी.

-दीपक जायसवाल, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

कांग्रेस के रास्ते पर भाजपा

संविधान और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहनी चाहिए (25 जुलाई- 31 जुलाई 2016) शीर्षक लेख में कमल मोरारका ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन खारिज किए जाने को रेखांकित किया है. अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया था. दरअसल भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के चक्कर में बिना सोचे-समझे फैसले ले रही है. उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों जगहों पर राष्ट्रपति शासन मोदी सरकार की सबसे बड़ी भूल थी और इसे लेकर उसकी किरकिरी भी हुई. कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष पार्टियां केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही हैं कि वह राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए आर्टिकल 356 और राज्यपाल का दुरुपयोग कर रही हैं. ऐसा लग रहा है कि भाजपा भी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है. केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर जनता के हितों के लिए कार्य करना चाहिए.

-नवल किशोर उपाध्याय, *आरा, बिहार.*

अपनी चिंता करे पाकिस्तान

कश्मीर और बुरहान वानी के मसले पर पाकिस्तान की बयानबाजी दर्शाती है कि वह आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जमात-उद-दावा के प्रमुख आतंकी सरगना हाफिज सईद की भाषा बोलने लगे हैं. नवाज शरीफ हिजबुल मुजाहिद्दीन के पोस्टर ब्वॉय और कमांडर बुरहान वानी को शहीद और क्रांतिकारी बता रहे हैं. यह आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के दोहरे रवैये को दिखाता है. पाकिस्तान में लोग गरीबी से मर रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हैं और वहां के लोग आतंकी घटनाओं से परेशान हैं. बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं और पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें देशी-विदेशी अखबारों और चैनलों में दिखाई देती हैं. नवाज शरीफ को कश्मीर की चिंता छोड़कर उन लोगों की चिंता करनी चाहिए जो पाकिस्तान की जिल्लत भरी जिंदगी से आजादी चाहते हैं. भारत को नसीहत देना बंद कर पाकिस्तान को अपनी चिंता करनी चाहिए.

-फिरोज आलम, *अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.*

नक्सलियों का खौफ

आलेख- नक्सली अब ग्रामीणों से मांग रहे हैं बच्चे (25 जुलाई- 31 जुलाई 2016) पढ़ा. काफी विचारोत्तेजक लेख है. प्रशांत शरण ने सही कहा है कि पहले जहां एमसीसी का एकछत्र राज था, वहीं इस संगठन से टूटकर उग्रवादियों ने अब अपना-अपना संगठन खड़ा कर लिया है. नक्सली उद्योगपतियों से लेवी तो ले ही रहे हैं, अब वे ग्रामीणों से उनके बच्चे भी मांग रहे हैं. उनका मकसद साफ नजर आ रहा है कि वह अब इलाके में अपने संगठन का विस्तार करना चाहते हैं. नक्सलियों द्वारा ग्रामीणों से उनके बच्चे मांगना काफी चिंताजनक है. ग्रामीण उनके डर से गांव छोड़कर भाग रहे हैं. नक्सलियों के खौफ से इलाके में विकास कार्य ठप पड़े हैं. उनके डर से अध्यापक स्कूल नहीं आते हैं जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है. प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी ग्रामीणों को समय पर मदद नहीं मिल रही है जिसकी वजह से ग्रामीण खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं.

-रास बिहारी, *कोडरमा, झारखंड.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

हमें कश्मीरियों की बात ध्यान से सुननी चाहिए

हमारे देश का राजनीतिक जगत या तो भ्रमित हो गया है या फिर असंवेदनशील हो गया है. कश्मीर में लोग असंतुष्ट हैं, सड़कों पर हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है. सामान्य जनता के घरों में राशन, दूध व पानी की किल्लत हो गई है, लेकिन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य का कोई भी व्यक्ति कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है या कश्मीर नहीं जाना चाह रहा है. कश्मीर के अलावा सारे देश में ऐसा मानस विकसित हो गया है, मानो श्रीनगर में रहने वाले सारे लोग, दूसरे अर्थ में कश्मीर में रहने वाले लोग भारत विरोधी हैं और उनसे कोई बात नहीं करनी चाहिए. उनसे बात सिर्फ सेना के ज़रिए करनी चाहिए. सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है जिसमें सेना के नाम से पोस्ट डाली जा रही है. नौजवान लड़कों के फोटो दिखाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये सब आतंकवादी हैं और सेना ने उन सबको मारने की क़सम खाई है. सारे देश में कश्मीर के ख़िलाफ़ अभियान चल रहा है और अफ़सोस की बात है कि भारत की सरकार इस अभियान को चलने दे रही है. उसके पास कोई जानकारी नहीं है कि कौन इस घृणा के अभियान को चला रहा है. उसके पास इस बात के लिए भी पहल करने का समय नहीं है कि भारत के राजनीतिक दलों के लोग कश्मीर जाएं, ठीक वैसे ही जैसे वो हैदराबाद जाते हैं, जैसे वो उत्तर प्रदेश जाते हैं, जैसे वो भारत के किसी भी प्रदेश में जाकर वहां के लोगों से बातचीत करते हैं.

क्या राजनीतिज्ञों से एक बड़ी चूक नहीं हो रही है कि वो कश्मीर की आवाज़ को नहीं सुनना चाहते जो आवाज़ किन्हीं परिस्थितियों के वशीभूत होकर सड़कों पर पत्थर चला रही है. क्या वो कश्मीर के हालात नहीं समझना चाहते? क्या वो कश्मीर के लोगों को ये भी नहीं बताना चाहते कि हम तुम्हारी तकलीफ़ों को कम करने की कोशिश करेंगे? संसद भी ख़ामोश है, सरकार भी ख़ामोश है और राजनीतिक दल भी ख़ामोश हैं.

ये स्थिति कश्मीर के सवाल को उलझा रही है. सालों से कश्मीरी जनता के मन में ये भावना भर गई है कि दिल्ली या भारत या इंडिया उनकी बात सुनना ही नहीं चाहता और तब कोई घटना हो जाती है, बुरहान वानी नाम का लड़का पुलिस की गोली से मर जाता है और उसकी शवयात्रा में 5 लाख लोग शामिल हो जाते हैं. बुरहान वानी को भारत के सोशल मीडिया ने एक बड़े मिलिटेंट के रूप में पेंट किया, कुछ टीवी चैनलों ने भी इस काम में हाथ बंटाया, कुछ नासमझ प्रिंट के पत्रकार भी इस शोर को बढ़ाने में शामिल हो गए, जबकि 15 साल की उम्र में बुरहान वानी ने फेसबुक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. वह देखने में ख़ूबसूरत लड़का था. कश्मीर के नौजवानों में उसकी पोस्ट को लेकर आकर्षण पैदा हुआ और वो पोस्टर ब्वॉय माना गया. उसकी भाषा बड़ी आसानी से अलगाववाद की भाषा मान ली गई. कश्मीर में फेसबुक पर जो भी नौजवान हैं, उनकी पहचान बड़ी आसानी से की जा सकती है. प्रशासन चाहता तो उसे पकड़ कर जेल में डाल देता. लेकिन, कश्मीरियों का कहना है कि उसे गिरफ्तार कर गोली मारी गई. दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि उसके हाथ में हथियार थे और वो आमने-सामने की लड़ाई में मारा गया. प्रशासन की इस बात पर कश्मीरियों को विश्वास नहीं है, शायद इसलिए उसकी शवयात्रा में 5 लाख लोग शामिल हुए.

और, यहीं पर हाफ़िज़ सईद कूद पड़ता है, पाकिस्तान सरकार कूद पड़ती है और कश्मीर के सवाल को हाइजैक करने की कोशिश करती है. हाफ़िज़ सईद कश्मीर के सवाल पर पूरी दुनिया से करोड़ों-अरबों रुपए इकट्ठा करता है. वो अपनी संस्था जमात-उद-दावा भी चलाता है और भारत में भेजे जाने वाले दहशतगर्दों को रसद भी मुहैया कराता है. पाकिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि हाफ़िज़ सईद आतंकवादी कैंप भी चलाता है. पर मज़े की बात है कि जब कश्मीर में शांति रहती है, तब हाफ़िज़ सईद कुछ नहीं बोलता और जहां थोड़ी अशांति नज़र आती है, वहां वह दुनिया के मुसलमानों को बताने की कोशिश करता है कि वह सब उसी की वजह से हुआ. जबकि, सच्चाई यह नहीं है. नवाज़ शरीफ़ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, अस्थिर हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सेना का सत्ता में दोबारा आने का डर है और इनसे लड़ने के लिए नवाज़ शरीफ़ ने कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का राग छेड़ दिया है. इससे वे अपनी घरेलू समस्याओं का रुख़ मोड़ने में कामयाब होना चाहते हैं.

पर, इस सारी स्थिति से कश्मीर का सवाल एक भूल-भुलैया में फंसता जा रहा है. सारे देश को लगता है कि कश्मीर में चल रहा असंतोष पाकिस्तान और हाफ़िज़ सईद की देन है. कश्मीर में हो रही पत्थरबाज़ी हाफ़िज़ सईद की मदद से हो रही है, जो बिल्कुल ग़लत है. पाकिस्तान कुछ पैसे भेज सकता है. हाफ़िज़ सईद सिर्फ बयानबाज़ी के और कुछ नहीं कर सकता. कहीं भी कुछ हो और कोई खड़ा हो कर ये कह दे कि मैंने ये कराया है, वो सच नहीं माना जा सकता है. लेकिन, इन्हीं बातों से उनलोगों के हाथ में एक हथियार आ जाता है जो इस देश को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं. कश्मीर के बहाने हर मुसलमान को शक की नज़र से देखने का एक दौर सोशल मीडिया पर ऐसी ताक़तों ने शुरू कर दिया है.

क्या हमारे देश के राजनीतिज्ञ, हमारे देश का मीडिया, हमारे देश की संसद इतने नासमझ हैं कि हाफ़िज़ सईद के बयान के आधार पर देश में अपनी रणनीति तय करते हैं. क्या हम इतने ग़ैर जानकार हैं कि जो ये नहीं जानते कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं या हाफ़िज़ सईद जो बात बनावटी तौर पर बोलता है, उसे हम कश्मीर की आवाज़ समझ लेते हैं. यहीं पर हिंदुस्तान की नासमझी समझ में आती है. हमारी विदेश नीति, हमारी रक्षा नीति को कोई तीन आतंकी या कोई हाफ़िज़ सईद जैसा आदमी इतना ज़्यादा प्रभावित कर लेगा, इससे बड़ा दिमाग़ी दिवालियापन का सबूत और क्या हो सकता है?

> कश्मीर में आज हुर्रियत भी बेबस है, सरकार भी बेबस है. वहां के आम आदमी भी बेबस हैं. बस, अगर कोई खुश है, तो वो लोग जो कश्मीर के इस असंतोष में अपनी राजनीति को सफल होता हुआ देख रहे हैं या फिर वो ताक़तें जो कश्मीर की इस स्थिति से सारी दुनिया से पैसा कमाने का एक ज़बरदस्त मौक़ा हासिल कर चुकी हैं. मैं भारत के राजनेताओं से, संसद सदस्यों से, राजनीतिक पार्टियों से, और ख़ास कर हिंदुस्तान की सिविल सोसायटी से ये अपील करना चाहूंगा कि बिना समय गंवाए उन्हें कश्मीर जाना चाहिए और कश्मीर के आम जन से बात करनी चाहिए और वो क्या कहते हैं, उसे ध्यान से सुनना चाहिए. ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान में कोई नहीं मानता कि कश्मीर युद्ध के बल पर जीता जा सकता है. कश्मीर में भी ये कोई नहीं मानता कि कश्मीर पाकिस्तान में जा सकता है.

होना ये चाहिए कि हम हाफ़िज़ सईद को पूरी तौर पर एक ऐसे जोकर के रूप में दुनिया के सामने रखें, जो कश्मीर के लोगों के दर्द और आंसू के एवज़ में सारी दुनिया से पैसा जुटाता है. कश्मीर में पिछले 20 दिनों के तनाव में भी अरबों रुपए हाफ़िज़ सईद के खाते में आए हैं, ऐसा मुझे हाफ़िज़ सईद को जानने वाले एक दोस्त ने बताया. कश्मीर के लोगों के आंसू, दर्द और तकलीफ़, जिसके लिए वे सड़कों पर पत्थर चला रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, उसका कोई मोल हाफ़िज़ सईद के लिए नहीं है. उसके लिए कश्मीर में होने वाली हर घटना, उसके लिए पैसा कमाने का एक बड़ा साधन है. और, नवाज़ शरीफ़ जब बुरहान वानी की मौत को शहीद दिवस मनाने या काला दिवस मनाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो वो कश्मीर की लड़ाई को बर्बाद करते हैं. कश्मीर के लोगों की लड़ाई वही है, जो बंगाल, बिहार, ओडीशा के लोगों की लड़ाई है. भूख और बेरोजगारी के खिलाफ रास्ता तलाशने की लड़ाई है. कश्मीर की लड़ाई इससे अलग नहीं है. नवाज़ शरीफ़ इस लड़ाई को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं और इसे सांप्रदायिक तनाव के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं.

लेकिन, जब हमारे देश के राजनेता इस जाल में फंसते हैं, तब लगता है कि हाफ़िज़ सईद और नवाज़ शरीफ़ ज़्यादा समझदार हैं, हमारे देश के नेता कम समझदार हैं. हम लोकतांत्रिक देश हैं, ताक़तवर देश हैं, तकनीकी रूप से आगे हैं, हमें पाकिस्तान और हाफ़िज़ सईद जैसे लोगों की जालसाज़ी में फंस कर उनके जाल में नहीं उलझा जाना चाहिए.

अब कश्मीर का हाल ये है कि कश्मीर में हुर्रियत का भी नियंत्रण ख़त्म हो रहा है. 27 जुलाई को हुर्रियत ने बयान दिया था कि दोपहर के बाद बंद वापस हो जाएगा और लोग अपने घरों के लिए सामान ख़रीद सकेंगे. सरकार ने भी कर्फ्यू में ढील दी. लेकिन, 18 से 20 साल के कुछ लड़के निकल आए, उन्होंने मोटरसाइकिल को चलने से रोक दिया. खुली दुकानों को बंद करा दिया और दोबारा कर्फ्यू लगवा दिया. प्रशासन को जितना समझदार होना चाहिए, उतनी समझदारी दिखाने में कमी कर रहा है. एक घटना कश्मीर में होती है तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्ख़ियां बनती है. और, कश्मीर में ये छोटी घटनाएं घटती रहें, इसके पीछे वहां की आंतरिक राजनीति भी है. कश्मीर की दो बड़ी पार्टियों में से एक बड़ी पार्टी के गढ़ में ज़्यादा स्थिति ख़राब रही और एक पार्टी के गढ़ में स्थिति कम ख़राब रही. इस असंतोष को कश्मीर के लोग राजनेताओं के उस रणनीति के रूप में भी देखते हैं कि कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग जाए. वास्तविकता ये है कि कश्मीर का नौजवान असंतुष्ट है, लेकिन किसी एकीकृत कमांड के तहत काम नहीं कर रहा है. कश्मीर में आज हुर्रियत भी बेबस है, सरकार भी बेबस है. वहां के आम आदमी भी बेबस हैं. बस, अगर कोई खुश है, तो वो लोग जो कश्मीर के इस असंतोष में अपनी राजनीति को सफल होता हुआ देख रहे हैं या फिर वो ताक़तें जो कश्मीर की इस स्थिति से सारी दुनिया से पैसा कमाने का एक ज़बरदस्त मौक़ा हासिल कर चुकी हैं. मैं भारत के राजनेताओं से, संसद सदस्यों से, राजनीतिक पार्टियों से, और ख़ास कर हिंदुस्तान की सिविल सोसायटी से ये अपील करना चाहूंगा कि बिना समय गंवाए उन्हें कश्मीर जाना चाहिए और कश्मीर के आम जन से बात करनी चाहिए और वो क्या कहते हैं, उसे ध्यान से सुनना चाहिए. ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि पाकिस्तान में कोई नहीं मानता कि कश्मीर युद्ध के बल पर जीता जा सकता है. कश्मीर में भी ये कोई नहीं मानता कि कश्मीर पाकिस्तान में जा सकता है. बोलना एक बात है, वास्तविकता दूसरी बात है. इसीलिए, कश्मीर एक प्रयोगशाला है जहां के लोगों को मानसिक तौर पर देश के साथ कैसे खड़ा करें, इसका प्रयोग होना आवश्यक है. और उसका एक ही तरीक़ा मेरी समझ से ये है कि कश्मीर के लोगों से खुली बातचीत संसद को, राजनीतिज्ञों को करनी चाहिए और उन ताक़तों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग मानसिकता वाला राज्य दिखाने की कोशिश सोशल मीडिया पर कर रहे हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

मैघनाद देसाई

भाजपा के सेल्फ गोल

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सरकार अरुणाचल प्रदेश पर आये अदालत के फैसले और फिर सदन में हुए निर्णायक शक्ति परीक्षण से बच सकती थी. क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर अचानक नेता बदलने की एक शानदार चाल कांग्रेस कैसे चल पाती? क्या भाजपा में किसी को पहले से इसका एहसास नहीं था?

लेकिन कहते हैं दुर्भाग्य अकेले नहीं आता. अरुणाचल के कुछ ही दिनों के बाद, नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा में अपने छोटे कार्यकाल को समाप्त कर दिया. यह राज्यसभा के सबसे छोटे कार्यकालों में से एक था. एक बार फिर ऐसा लगता है कि भाजपा के अंदर किसी ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी. पार्टी अब यह सोच रही होगी कि अच्छा होता कि सिद्धू को पहले ही नज़र अंदाज़ कर दिया गया होता. लेकिन ऐसी चीज़ें राजनीति में ब्रेकिंग न्यूज की तरह होती हैं, जिन्हें मीडिया पसंद करता है क्योंकि यह टीआरपी जमा करने का बेहतरीन साधन है.

फिर सामने आई उना (गुजरात) की त्रासदी, जिसमें सरकार अदृश्य रही और उसे इस घटना का कोई पछतावा भी नहीं हुआ. मानसून सत्र को एक बार फिर व्यर्थ होने से बचाने के लिए भाजपा के पास जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी उसे उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने बिगाड़ दिया. सरकार के लिए एकमात्र सांत्वना राहुल गांधी का संसद में सोना (या शायद योग करना) था. यदि फुटबॉल की भाषा में बात करें तो इस स्तंभ के लिखे जाने तक कांग्रेस के एक के मुकाबले में भाजपा के तीन गोल थे, लेकिन तीनों सेल्फ गोल थे.

यह स्पष्ट है कि भाजपा तेजी से चीज़ें सीख़ रही है. बहरहाल एक के बाद एक लगातार कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों द्वारा आर्टिकल 356 का इस्तेमाल कितना आसान था. लेकिन तब समय और था. अब समय बदल गया है. सरकार को उत्तराखंड और अरुणाचल की गलतियों से सबक सीखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि राज्य के राजनीतिक प्रभारियों में उत्साह के साथ-साथ दिमाग़ की भी अवश्यकता है. कुटिलता बिल्कुल अलग चीज़ है. भले ही लोग आपके काम का अनुमोदन न करें, लेकिन अगर आप जीत जाते हैं तो उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा. लेकिन वे अक्षमता का मजाक ज़रूर उड़ाएंगे. भाजपा को आर्टिकल 356 का उपयोग उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक उसके पास संघीय राजनीति की समझ रखने वाले लोग न आ जाएं.

जहां तक सिद्धू के इस्तीफे का सवाल है तो उनके प्रकरण से यही ज़ाहिर होता है कि भारतीय राजनीति प्रणाली बहुत हद तक भारतीय सामंतवाद की तरह है. एक स्थानीय सामंत एक राजा के साथ खड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरा राजा बेहतर पेशकश करता है, सामंत पाला बदल लेता है. अब ऐसे स्थानीय नेता हैं जिनका अपना समर्पित वोट बैंक है, वे अपनी सेवाएं उस पार्टी को ख़ुशी-ख़ुशी पेश कर देंगे जो उन सेवाओं के बदले अधिक की पेशकश करेगा. यह प्रक्रिया चुनाव के समय काफी तेज़ हो जाती है. इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव नज़दीक आते ही और लोग भी एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जायेंगे. सिद्धू को शायद केजरीवाल से या फिर शायद कांग्रेस से भी एक बेहतर प्रस्ताव मिला हो.

मौजूदा सरकार के दो साल के कार्यकाल के बाद यह स्पष्ट है कि सरकार अपने रिकॉर्ड के लिए प्रधानमंत्री पर अत्यधिक निर्भर है. ऐसा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तित्व के मालिक हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा के पास आधा दर्जन से भी अधिक कैबिनेट सदस्य नहीं हैं, जिनपर बेहतर नतीजों के लिए भरोसा किया जा सकता है. पार्टी में ऐसे सांसदों की कमी है जो मंत्री पद संभाल सकें या अपनी ज़ुबान पर क़ाबू रख सकें. प्रधानमंत्री को एक सख्त स्कूल टीचर की तरह उनसे काम लेना पड़ता है.

जहां तक पार्टी का सवाल है तो वह पूरी तरह अमित शाह पर निर्भर है. लेकिन अमित शाह केवल चुनाव जीतने में माहिर हैं, पार्टी को अनुशासित करने में नहीं. चुनाव जीतने के लिए आरएसएस पैदल सेना उपलब्ध करा सकती है, लेकिन पार्टी को यह भी समझना होगा कि मायावती को अपमानित करना किसी तरह भी लाभकर नहीं है. भाजपा शायद पंजाब हार जाए और उत्तर प्रदेश जीत न सके, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह गुजरात बचा पायेगी?

कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व को लेकर समस्या हो सकती है (भले ही इसके नेता संसद में ऊंघ रहे हों), लेकिन पार्टी में कुछ बहुत ही चतुर नेता हैं जो समझते हैं कि राजनीति में चीजें कैसे काम करती हैं. ऐसा केवल अरुणाचल में ही देखने को नहीं मिला बल्कि पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित को आगे करके भाजपा के लिए एक चेतावनी पेश कर दी है. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड, यूपी, एमपी नहीं दे रहे हैं पानी

नहरें प्यासी हैं और किसान परेशान

बिहार की राजनीति एवं कृषि उत्पादन के मामले में महत्वपूर्ण माने जाने वाले मगध और भोजपुर के किसानों की राज्य सरकार की ओर से अनेदखी निर्माण की जा रही है. सरकार की अनदेखी पर लोगों को आश्चर्य हो रहा है. बिहार के रोहतास जिले में इन्द्रपुरी के पास सोन नदी पर स्थापित बैराज के आधुनिकीकरण तथा स्वीकृत जलाशय के निर्माण का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है.

सुनील सौरभ

राज्य के सिंचाई विभाग के अधिकारियों तथा राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से दक्षिण बिहार के मगध एवं भोजपुर की लाखों हेक्टेयर भूमि को समुचित सिंचाई की सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है. इस क्षेत्र की नहरें बरसात के दिनों में भी प्यासी हैं. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समझौते के बाद भी सोन नदी का पानी बिहार को नहीं दे रहे हैं. जिसकी वजह से दक्षिण बिहार में स्थित पूर्वी और पश्चिमी सोन नहर में बरसात के दिनों में भी पानी उचित मात्रा में नहीं आ पा रहा है. झारखंड के द्वारा भी डैम से पानी नहीं दिए जाने की वजह से उत्तर कोयल नहर में भी पानी का पूरी तरह अभाव है. बिहार की राजनीति एवं कृषि उत्पादन के मामले में महत्वपूर्ण माने जाने वाले मगध और भोजपुर के किसानों की राज्य सरकार की तरफ से अनदेखी की जा रही है. सरकार की अनदेखी पर लोगों को आश्चर्य हो रहा है. बिहार के रोहतास जिले में इन्द्रपुरी के पास सोन नदी पर स्थापित बैराज के आधुनिकीकरण करने तथा स्वीकृत जलाशय के निर्माण का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है. डिहरी ऑन-सोन के पास सोन नदी पर बने इन्द्रपुरी बैराज से पूर्वी तथा पश्चिमी सोन नहर सिंचाई परियोजना से दक्षिण बिहार के रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, गया, अरवल तथा पटना जिले की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है. सोन नदी पर मध्यप्रदेश में वाण सागर डैम तथा उत्तर प्रदेश में रिहन्द जलाशय बना हुआ है. बिहार सरकार का सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से रिहन्द जलाशय तथा मध्यप्रदेश के वाण सागर जलाशय से इन्द्रपुरी बैराज नहर सिंचाई प्रणाली को जलापूर्ति करने के लिए वर्षों पूर्व समझौता हुआ था. लेकिन उक्त राज्यों द्वारा समझौते का अनुपालन नहीं किया जा रहा है. बिहार के इन्द्रपुरी बैराज को कभी आवश्यकता से कम तो कई बार समय से जलापूर्ति नहीं की जाती है. जिसकी वजह से बिहार के सोन नहर सिंचाई प्रणाली को भारी जल संकट का सामना करना पड़ता है. इस समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश सरकार से बिहार सरकार से आधिकारिक वार्ता होने के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकल रहा है. सोन नदी में इन्द्रपुरी बैराज के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र के बड़े भू-भाग में वर्षा जल भंडारण की योजना के लिए संयुक्त बिहार में कदवन जलाशय योजना स्वीकृत की गई थी. लेकिन इस योजना का क्षेत्र बंटवारे के बाद झारखंड में चला गया. बाद में बिहार सरकार ने इस परियोजना का नाम बदल कर इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना कर दिया. लेकिन इस परियोजना पर बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है. नतीजा यह है कि प्रभावित क्षेत्र के किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिये परेशान हैं. राज्य बंटवारा के बाद मोहम्मदगंज बैराज तथा कुदकु डैम पलामू पर झारखंड सरकार का पूरा नियंत्रण है. डैम में फाटक का निमार्ण नहीं होने की वजह से जल भंडारण का कार्य नहीं हो रहा है.

डैम पर फाटक निर्माण करने के लिए झारखंड एवं बिहार सरकार के उच्च अधिकारियों की बैठक की हुई थी, जिसमें डैम पर फाटक निर्माण का जिम्मा झारखंड सरकार ने लिया था. फाटक का निर्माण न होने की वजह से बिहार में स्थित उत्तर कोयल सिंचाई नहर परियोजना तथा इन्द्रपुरी बैराज के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र की सहायक नदियों से पानी नहीं मिल पा रहा है. वहीं दूसरी ओर इन्द्रपुरी बैराज के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में मिट्टी तथा बालू का जमाव बना हुआ है. जिससे जल भंडारण की क्षमता कम हो गई है. जिसकी वजह से पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर सिंचाई प्रणाली के वितरणियों के अंतिम छोर पर हजारों गांवों के खेतों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पा रहा है. जानकार बताते हैं कि इन्द्रपुरी बैराज के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में जल की कमी होने की वजह से सोन नदी के प्राकृतिक संरचनाओं पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा इसके जल प्रवाह में भारी कमी हो रही है. इन्द्रपुरी बैराज के नीचे उत्तर पूर्व की ओर औरंगाबाद एवं अरवल जिला स्थित सोन नदी भू-भाग में काश के जंगल तथा घास उग गए हैं जिसकी वजह से नदी का विशाल भू-भाग तथा प्राकृतिक संरचना रेगिस्तान में बदलती जा रही है. लोग सोन नदी को इन समस्याओं से बचाने के लिए भी पर्यावरणविदों की एक कमिटी बनाकर विचार-विमर्श करने की बात कह रहे हैं. ज्ञात हो कि बिहार के रोहतास जिले में डिहरी ऑन-सोन के पास सोन नदी पर बना इन्द्रपुरी बैराज दुनिया का चौथा लम्बा बैराज है. इसकी कुल लंबाई 1407 मीटर है. इस बैराज की दोनों नहरों से 6,99,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने का दावा था, लेकिन अभी पूरे क्षेत्र की सिंचाई नहीं हो पा रही है. बताया जाता है कि सोन नदी प्रोजेक्ट का काम आजादी के पूर्व 1874 में एक प्रसिद्ध अंग्रेज इंजीनियर ने शुरू किया था. तब यह योजना किसानों के हितों को देखते हुए बनाई गई थी. लेकिन आजादी के बाद इस परियोजना को राजनीतिक चश्में से देखा जाने लगा, जिसकी वजह से सोन नहर सिंचाई परियोजना में बराबर बदलाव आता रहा. किसानों की हितों की अनदेखी कर सिर्फ राजनीतिक हित साधने का मुद्दा इन्द्रपुरी बैराज बन गया. आज जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें सोन नदी जल बंटवारे के अनुरूप बिहार को पानी नहीं दे पा रही हैं, तब भी कोई राजनीतिक सुगबुगाहट नहीं है. यहां तक की बिहार से बंटकर अलग हुआ झारखंड भी बिहार के हितों की अनदेखी कर रहा है. नहरों में उचित मात्रा में पानी का नहीं आना बिहार सरकार के राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और संबंधित विभागों के पदाधिकरियों की उदासीनता का परिणाम है. पता नहीं किसानों के हित के लिए बिहार सरकार कब जागेगी.■

बारूद की ढेर से निकल रहा प्रतिभाओं का ज़ख़ीरा

सुपर 30 ने आठ सालों में दर्जनों बच्चों का आईआईटी, एनआईटी के अलावा देश के अन्य चर्चित कॉलेजों में नामांकन कराकर यह जता दिया है कि प्रतिभा हो तो उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. इन बच्चों में कई ऐसे बच्चे थे जिनके सामने दसवीं के बाद आगे पढ़ने का कोई विकल्प नहीं था. अधिकांश बच्चे बिहार-झारखंड के बारूद की ढेर से घिरे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं. इन बच्चों का बचपन प्रतिबंधित संगठनों के हथियारबंद दस्तों और पुलिस के बीच दहशत में गुजरा है. 2008 में बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी अभयानंद के नेतृत्व में गया शहर के कुछ लोगों ने मगध रेंज के तत्कालीन डीआईजी प्रवीण वशिष्ठ की पहल पर मगध सुपर 30 की स्थापना की और ग्रामीण क्षेत्रों के विशेषकर दहशत में जीने वाले मेधावी बच्चों को इंजीनियरिंग की तैयारी कराने का निर्णय लिया. 2008 से लेकर अब तक सौ से अधिक बच्चे आईआईटी, एनआईटी में जा चुके हैं. इतना ही नहीं यहां के बच्चे देश के अन्य चर्चित इंजीनियरिंग कॉलेजों और मेरिल में भी जा चुके हैं. अनेक बच्चे देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थानों से बीटेक कर अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि मगध सुपर 30 प्रतिवर्ष 30 मेधावी बच्चों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता है. इस परीक्षा में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को परीक्षा देने की अनुमति होती है. दो लिखित परीक्षा के अलावा मौखिक परीक्षा भी ली जाती है. इन परीक्षाओं के मेरिट लिस्ट में आने वाले 30 बच्चों को मगध सुपर 30 में रखा जाता है. इन सभी बच्चों को रहने, खाने-पीने और पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था रहती है. मगध सुपर 30 को शुरू करने में गया शहर के प्रसिद्ध समाजसेवी स्व. शिवराम डालमिया, सेंट्रल बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष डॉ. कौशेलेंद्र प्रताप, डॉ. अनूप कुमार केडिया, चर्चित समाजिक कार्यकर्ता लालजी प्रसाद, गीता देवी एवं पत्रकार पंकज कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि मगध सुपर 30 बारूद की ढेर पर बैठे क्षेत्रों से प्रतिभाओं का जखीरा निकाल पा रहा है.■

-सुनील सौरभ

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org,
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.

DEGREE COURSES

BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.

1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT

DIPLOMA COURSES :

DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड
पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी
Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाइट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior
लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है
प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतु सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com
सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट
सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध। मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव

महिलाओं ने मारी बाज़ी

पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों में शहर से लेकर गांव की गलियों तक विकास योजनाओं की चर्चा जोर पकड़ने लगी है. जिले में सरकार प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम योगदान देने वाले जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चल रही राजनीतिक कवायदों पर भी विराम लग गया है. मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर व मुजफ्फरपुर समेत अन्य स्थानों पर अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया है. इन जिलों में अध्यक्ष पद की कमान महिलाओं को मिली है.

विकास/अमृता

घर की चारदीवारी से लेकर बाहरी दुनिया तक अब महिलाएं अपने सफलता का परचम लहरा रही हैं. महिलाएं शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस बल एवं अर्द्धसैनिक बल समेत अन्य क्षेत्रों में परचम लहरा रही हैं. महिलाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में भी धमाकेदार प्रवेश किया है. हाल ही में संपन्न पंचायत चुनाव इसका जीवंत उदाहरण है. साथ ही जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर पूरी तरह से महिलाओं ने कब्जा कर लिया है. भारत-नेपाल सीमा से लगे उत्तर बिहार के लगभग आधा दर्जन जिलों में महिलाओं ने पुरुषों को काफी पीछे छोड़ दिया है. राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ रही हिस्सेदारी कितनी महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगी, इसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है. दलगत राजनीति से अलग रहे नवनिर्वाचित पार्षदों को लगभग सभी राजनीतिक दल अपने पार्टी का सदस्य बता रहे हैं. लेकिन अधिकांश पार्षदों ने यह साफ कर दिया है कि उनके लिए पार्टी महत्व नहीं रखती है, बल्कि क्षेत्र के विकास को तरजीह देना उनकी प्राथमिकता है. अब देखना है कि नवनिर्वाचित पार्षद विकास के वादे को पूरा करते हैं या नहीं.

नीलम देवी

उमा देवी

उत्तर बिहार में बाढ़, अपराध व नक्सली समस्या की वजह से चर्चा में रहने वाले शिवहर जिले में कुल सात सीटों पर जिला परिषद का चुनाव हुआ था जिसमें केवल दो सीटों पर जीत हासिल करने वाली महिलाओं ने जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा ली है. जबकि उपाध्यक्ष के पद पर पुरुष पार्षद को मौका मिला है. इस सीट पर कई दावेदार थे, लेकिन राजनीतिक उलट फेर के बाद पिपराही की पूर्व प्रमुख सह नवनिर्वाचित पार्षद नीलम देवी को अध्यक्ष पद का ताज मिला है. इन्हें जिला पदाधिकारी राजकुमार ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई. सीतामढ़ी जिले की कुल 38 सीटों पर हुए चुनाव में 19 सीटों पर महिलाओं ने बाजी मारी है. इस जिले में अध्यक्ष पद के लिए उमा देवी निर्वाचित हुई हैं. जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जिले के कई चर्चित नेता काफी सक्रिय रहे और पर्दे के पीछे से जोड़-तोड़ की राजनीति में अपना अहम योगदान दिया. जिले की राजनीति में सक्रिय रहने वालों की माने तो जिले के दो पूर्व सांसदों के अलावा वर्तमान सांसद से लेकर पूर्व मंत्री व विधान पार्षद तक अपनी राजनीतिक पारी खेलने में लगे रहे. इस दौरान जातिवाद से लेकर पार्टी स्तर के अलावा अन्य चुनावी जरूरतों का भी ध्यान रखा.

दरभंगा जिले में संपन्न 46 सीटों पर चुनाव के बाद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर महिलाओं ने ही कब्जा जमाया है. यहां से गीता देवी अध्यक्ष, तो ललिता देवी उपाध्यक्ष बनी है. मधुबनी से जिला परिषद अध्यक्ष पद की कुर्सी शीला मंडल को मिली है. समस्तीपुर जिले में जिला परिषद के अध्यक्ष सीट को महिला अतिपिछड़ा के लिए आरक्षित किया गया था. कुल 51 सीटों में से 50 सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद 29 सीटों पर महिलाओं ने सफलता पाई है. लगातार तीन बार जिला परिषद चुनी गई प्रेमलता निर्विराध अध्यक्ष चुनी गईं. प्रेमलता पिछले चुनाव में महज एक वोट से उपाध्यक्ष का चुनाव हार गई थीं. अबकी बार पूर्व अध्यक्ष विजय लक्ष्मी देवी के पति सह पूर्व लोजपा विधायक विश्वनाथ पासवान के अलावा कई अन्य राजनीतिक धुरंधरों ने प्रेमलता को सफलता दिलाने में अहम योगदान दी है. जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव में पहली बार जिला परिषद का चुनाव जीतकर आने वाले अनिल कुमार सिंह को सफलता प्राप्त हुई. वे 28 मतों से विजयी घोषित किए गए. मुजफ्फरपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद पर इंद्रा देवी, तो मोतिहारी में प्रियंका जायसवाल को सफलता मिली. सबसे अहम सवाल यह है कि निर्वाचित अध्यक्ष जिले में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में खुद अपनी भागीदारी देंगी या उनके कार्य का संचालन उनके प्रतिनिधयों द्वारा किया जाएगा. अब आम लोगों के बीच यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोगों का कहना है कि जिनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसी महिलाएं अपना कार्य खुद भी कर सकती हैं. लेकिन जो महिलाएं पहली बार जिला परिषद अध्यक्ष बनी हैं, उनको कुशल राजनीतिक व्यक्ति की आवश्यकता होगी. यह एक ऐसा मौका है जो महिला प्रतिनिधियों को जनता बीच के बेहतर साबित कर सकता है. अन्यथा उनकी तमाम सक्रियता धरी की धरी रह जाएगी और जिला परिषद कार्यालय कमीशनखोर व दलालों का अड्डा बनकर रह जाएगा. जिले में विकास योजनाओं के सही कार्यान्वयन के लिए महिला प्रतिनिधियों को खुद पर भरोसा कर आगे आना होगा. यह महिलाओं के लिए अध्यक्ष पद पर कायम होने के बाद कठिन परीक्षा से कम नहीं होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा में जिला अध्यक्ष पद को लेकर घमासान

वाल्मीकि कुमार

वर्ष 2014 में संपन्न लोकसभा चुनाव के परिणाम ने भाजपा में उत्साह भर दिया था. हर तरफ मोदी-मोदी की गूंज एक नए युग की शुरुआत का संदेश दे रही थी. विपक्षी पार्टियों में घबराहट थी कि विधानसभा चुनाव का भी लोकसभा चुनाव जैसा ही परिणाम न हो. लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी ने भाजपा के सत्ता स्वप्न को तोड़ दिया. अब भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को लेकर पार्टी के भीतर बीते दो साल का दबा का गुबार फुटने लगा है. अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं. लोकसभा चुनाव के बाद संपन्न अन्य चुनावों में भाजपा को मोदी लहर का लाभ क्यों नहीं मिला? क्या पार्टी के अंदर की कलह असफलता की वजह है?

भाजपा जिला अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो शायद आने वाले समय में भाजपा को परेशान करें. पद की चाहत में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच की लड़ाई थम नहीं रही है. सीतामढ़ी जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष पद के लिए 21 जुलाई को संपन्न नामांकन प्रक्रिया के दौरान जिला चुनाव प्रभारी सह अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद चंद्रवंशी मौजूद थे. चंद्रवंशी की मौजदूगी में रीगा के पूर्व भाजपा विधायक मोतीलाल प्रसाद, डूमरा प्रखंड के पूर्व प्रमुख दिनकर पंडित, जिला अध्यक्ष मनोज कुमार समेत 14 पार्टी कार्यकर्ताओं ने नामांकन दाखिल किया. जबकि इससे

दिनकर पंडित | मनोज कुमार | मोतीलाल प्रसाद | नीतेश कुमार भारद्वाज | संजीव कुमार पांडेय | रामकृपाल शर्मा | राजीव कुमार सिंह | मनोज कुमार सिंह

पूर्व शिवहर जिले में 6 जुलाई को जिला चुनाव प्रभारी सह विधान पार्षद अर्जुन सहनी की मौजदूगी में जिला अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र कुमार मिश्र, जिला महामंत्री रामकृपाल वर्मा, युवा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव कुमार पांडेय, राजीव कुमार सिंह व दिनेश प्रसाद ने नामांकन दाखिल किया. नामांकन दाखिल करने वालों में वैसे पार्टी नेता शामिल हैं जिनकी पहुंच शीर्ष नेतृत्व तक है. पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पार्टी के अंदर गुटबाजी और जातिवाद का जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं. जहां तक दोनों जिलों में पार्टी संगठन के मजबूती का सवाल है, तो सातीमढ़ी से रालोसपा के राम कुमार शर्मा सांसद है और शिवहर से भाजपा की रमा देवी सांसद हैं. सांसद रमा देवी संगठन से लेकर सरकारी की योजनाओं के संदर्भ में खबरों में जरूर रहती हैं, तो वहीं शर्मा रालोसपा में उटे तूफान में ही घिरे हैं. सीतामढ़ी जिले में भाजपा के एक पूर्व पार्षद के अलावा दो पूर्व विधायक भी हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष की जिले में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है. स्थानीय समस्याओं के निदान को लेकर जिले में कोई कवायद नहीं हो रही है. लोगों का कहना है कि विपक्ष विकास के सवाल पर चुप क्यों है?

जिला अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए कोई स्थानीय नेताओं का परिक्रमा कर रहा है, तो कोई प्रदेश में बैठे शीर्ष नेताओं के आगे-पीछे घूम रहा है. कहा जा रहा है जिला अध्यक्ष पद की कुर्सी उसी को मिलने वाली है जिसकी पहुंच शीर्ष नेतृत्व तक है. अब दो बातें सामने आ रही हैं. पहली यह कि पार्टी संगठन का कमान थामने वाला जिला अध्यक्ष कैसा व्यक्ति होगा? दूसरी बात यह है कि कुर्सी मिलने के बाद वह संगठन को मजबूत करने की बजाए जातिवाद और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी विवाद तो नहीं खड़ा करेगा? क्योंकि सीतामढ़ी जिले में भाजपा के अंदर जातिवाद व गुटबाजी का बोलबाला है. नतीजतन संपन्न सभी चुनावों में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की इस जिले पर पैनी नजर रही है. अब देखना यह है कि जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर कद्दावर नेता का कब्जा होता है या किसी सामान्य कार्यकर्ता को तरजीह दी जाती है. कुर्सी किसी को मिले, लेकिन पार्टी संगठन को चलाना आसान नजर नहीं आ रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

मौसम है मानसून का खानपान में बरतें सावधानी
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

DR. DEEPAK KUMAR MBBS, KHAGARIA, MAHESHKHUT
खगड़िया के महेशखुट से डॉ. दीपक कुमार से टेलिफोन पर हुई बातचीत के कुछ अंश प्रस्तुत है। बारिश के मौसम में सेहत के प्रति जरा-सी लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है। इस मौसम में खानपान का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। गर्मी की तपन के बाद बरसात के मौसम की ठंडी फुहारें पड़ते ही मन खिल उठता है और गर्मागर्म चाय के साथ फ्राइड या जंक फूड खाने के लिए मचल जाता है। लेकिन सेहत के लिहाज से यह खुशनुमा मौसम थोड़ा नाजुक होता है। उमस भरे वातावरण में नमी का स्तर बहुत बढ़ जाता है और हवा में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया को जन्म देता है, जो हमारे पानी और खाने की चीजों में मिल कर उन्हें विषाक्त कर देते हैं। इनका सेवन करने से ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई संक्रामक बीमारियों को न्यौता देते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर नीचे चला जाता है, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है तथा रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे में केवल मुंह के स्वाद के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन की अनदेखी करना घातक होता है। आप अपच, दस्त, पेचिश, खांसी-जुकाम, टायफाइड, वायरल जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए इस मौसम में संतुलित आहार और सावधानियों की खास जरूरत होती है। लें संतुलित आहार गेहूं, मक्का, जौ, बेसन जैसे साबुत सूखे अनाज और दालों को अपने भोजन में शामिल करना बेहतर है। प्रोटीन, लौह और मैगनीशियम युक्त इन खाद्य पदार्थों के सेवन से रोग- प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। इस मौसम में आसानी से मिलने वाले भुने भुट्टे के सेवन से पर्याप्त फाइबर मिलता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए वरदान है। आहार में सूखे मेवों को शामिल करना भी जरूरी है। इस मौसम में मौसमी सब्जियों और फलों को अपने आहार का हिस्सा बनाएं। हरी पत्तेदार सब्जियों के बजाय हल्की और सुपाच्य सब्जियां जैसे घीया, तौरई, टिंडा, भिंडी, फ्रैंच बीन्स का सेवन करने से बरसात के मौसम में पेट संबंधी बीमारियों के खतरे से बचा जा सकता है। करेला, मूली, मेथी जैसी कड़वी सब्जियां संक्रमण से बचाती हैं। भोजन में अदरक, लहसुन, पुदीना, धनिया, काली मिर्च, हल्दी, हींग, मेथी दानों का उपयोग पाचनशक्ति को बढ़ाने में फायदेमंद है। इस मौसम में सलाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन एंटी ऑक्सीडेंट तत्वों से भरपूर खीरे के सेवन से कब्ज, अपच जैसे पेट के संक्रमण में फायदा होता है। ■ - भारती
URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

JOHNSON PAINTS
— Interior & Exterior Wall Paints —
JP
बड़े अच्छे लगते हैं...
PERFECT Exterior Emulsion
JOHNSON Exterior Emulsion
JOHNSON PAINTS INDUSTRIES

सपाई शिवपाल की सिफ़ारिश पर पिघल गए भाजपाई मोदी

दामाद के आगे ठेंगे पर क़ानून!

सपा नेता और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिखित मदद मांगी थी और अपने दामाद अजय यादव के कैडर परिवर्तन के लिए उन्हें चिट्ठी लिखी थी. केंद्र सरकार की नियुक्ति कमेटी ने शिवपाल को उपकृत करने के लिए कार्मिक मंत्रालय की तीन-तीन आपत्तियों को ताक पर रखते हुए इस सिफारिश को मंजूरी दे दी. अजय यादव उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के जिलाधिकारी हैं. अजय 2010 बैच के आईएएस हैं. लेकिन उनका मूल कैडर तमिलनाडु है.

दीनबंधु कबीर

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठमंत्री शिवपाल यादव ने अपने आईएएस दामाद अजय यादव का कैडर बदलवाने के लिए जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और जिस तरह केंद्र सरकार ने सारे नियम-कानून ताक पर रख कर इस सिफारिश को मंजूरी दे दी, उससे यह साबित हुआ कि राजनीतिक दलों का बाहरी और अंदरूनी चेहरा दोनों एक-दूसरे के विपरीत है. सार्वजनिक मंचों पर भाजपा को कोसते रहने वाले शिवपाल यादव ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भाजपा सरकार से सिफारिश करने में कोई संकोच नहीं किया और भाजपा सरकार ने भी कायदा-कानून तोड़ कर उन्हें उपकृत करने से संकोच नहीं किया. तमिलनाडु कैडर के आईएएस अफसर अजय यादव को उत्तर प्रदेश कैडर में बदलने की केंद्र सरकार की मंजूरी और राजनीतिक दलों का चरित्र उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है.

सपा नेता और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिखित मदद मांगी थी और अपने दामाद अजय यादव के कैडर परिवर्तन के लिए उन्हें चिट्ठी लिखी थी. केंद्र सरकार की नियुक्ति कमेटी ने शिवपाल को उपकृत करने के लिए कार्मिक मंत्रालय की तीन-तीन आपत्तियों को ताक पर रखते हुए इस सिफारिश को मंजूरी दे दी. अजय यादव उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के जिलाधिकारी हैं. अजय 2010 बैच के आईएएस हैं. लेकिन उनका मूल कैडर तमिलनाडु है. पिछले साल 28 अक्टूबर में केंद्र सरकार ने अजय यादव को तीन साल के लिए उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) दी थी. इस तैनाती को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट (एसीसी) ने बाकायदा अपनी मंजूरी दी थी. नियम यह है कि ऐसी अर्जियां पहले कार्मिक मंत्रालय जाती हैं, वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही वह आखिरी मंजूरी के लिए एसीसी के पास जाती हैं. लेकिन शिवपाल के दामाद की अर्जी का प्रभाव यह था कि कार्मिक मंत्रालय द्वारा तीन-तीन बार खारिज कर दिए जाने के बावजूद उसे पास कर दिया गया. इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव को मदद देने के लिए अपने ही मंत्रालय की अनदेखी कर दी. तमिलनाडु कैडर के आईएएस अफसर अजय यादव ने बच्चे की बीमारी और मां की देखरेख की मजबूरी बता कर कैडर परिवर्तन की अर्जी दी थी, लेकिन कार्मिक मंत्रालय ने इसे वाजिब वजह नहीं माना था. मंत्रालय ने लिखा था कि प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के लिए जो वजह बताई गई है वह अत्यंत साधारण है और निर्धारित नियमों और प्रावधानों के तहत इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती. कार्मिक मंत्रालय ने मई 2015 में ही इस अर्जी को नामंजूर कर दिया था. मंत्रालय का यह भी कहना था कि प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम नौ साल मूल कैडर में सेवा अनिवार्य है. अजय यादव इस शर्त को पूरा नहीं करते थे. कार्मिक मंत्रालय ने अजय यादव की दूसरी अर्जी को भी निर्धारित नियमावली की नत्थी लगा कर वापस कर दिया था. इसके बाद सारा तिकड़म खुल कर सामने आ गया. इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से ही एक चिट्ठी आई, जिसमें कहा गया कि समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री से सिफारिश की है. प्रधानमंत्री कार्यालय से आए पत्र में कार्मिक मंत्रालय को यह साफ-साफ कहा गया कि अगली बैठक में अजय यादव की प्रतिनियुक्ति का मामला विचार के लिए रख लिया जाए और बैठक जल्दी बुलाई जाए. इस बैठक में भी कार्मिक मंत्रालय ने अजय यादव की अर्जी को नियमों के खिलाफ माना और नियमों में किसी तरह की ढील देने से इंकार करते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी एसीसी से इसकी मंजूरी नहीं देने की ताकीद की. लेकिन भारतीय लोकतंत्र में कानून का जोर कहां चलता है! कार्मिक मंत्रालय के कानूनी सुझाव को ठेंगा दिखा कर शिवपाल की सिफारिश को मंजूरी दे दी गई.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री दफ्तर के दोतरफा चरित्र पर उंगली भी उठाई और कहा कि एम्स के पूर्व सीवीओ और 2002 बैच के वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को ओएसडी बनाने के प्रस्ताव को इन्हीं नियमों का हवाला देकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने खारिज कर दिया था, लेकिन शिवपाल यादव के दामाद के लिए उन्हीं नियमों को ताक पर रख दिया गया. बसपा नेता मायावती ने भी कहा कि इस कार्रवाई से यह साबित हुआ कि बाहर से राजनीतिक विरोधी दिखने वाली भाजपा और समाजवादी पार्टी अंदर ही अंदर मिली हुई है. सपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रामगोपाल यादव ने सत्ता-दंभ और मोदी-प्रेम से प्रभावित बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस प्रतिनियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं है. डीओपीटी प्रधानमंत्री से ऊपर नहीं है. प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकते हैं. वह नियमों में छूट देकर इस तरह पोस्टिंग दे सकते हैं.■

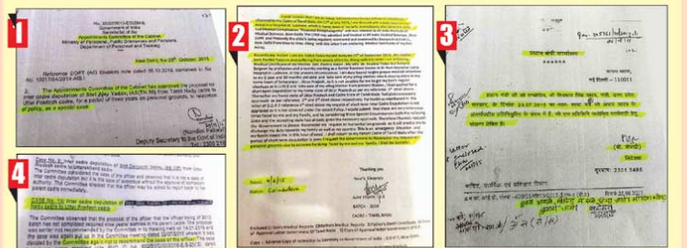

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमिटी एसीसी का 28 अक्टूबर 2015 को जारी आदेश
2. कार्मिक मंत्रालय को भेजी गई अजय यादव की अर्जी
3. शिवपाल के पैरवी-पत्र पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा डीओपीटी को दिया गया आदेश
4. प्रधानमंत्री दफ्तर के पत्र पर डीओपीटी का इन्कार

feedback@chauthiduniya.com

हाईकोर्ट के फ़ैसले की सरकार कर रही उपेक्षा, विरोध में संस्थाएं हो रहीं गोलबंद

कैसे पढ़े ग़रीब का बच्चा!

सूफी यायावर

सोशलिस्ट पार्टी, नैतिक पार्टी, ऐक्शन फॉर सोशल जस्टिस, रिहाई मंच समेत तकरीबन डेढ़ दर्जन सामाजिक-राजनीतिक संगठनों ने विभिन्न राजनीतिक दलों से पूछा है कि सरकारी वेतन पाने वाले जन प्रतिनिधियों, लोक सेवकों और न्यायाधीशों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर उनकी क्या राय है और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसे वे अपने घोषणा-पत्र में शामिल करेंगे कि नहीं? उल्लेखनीय है कि 18 अगस्त 2015 को हाईकोर्ट ने सरकारी तनख्वाह पाने वाले, जन प्रतिनिधियों, न्यायाधीशों, नौकरशाहों जैसे सरकार से लाभान्वित होने वाले लोगों के बच्चों को सरकारी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से पढ़ाने के फैसले के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे. यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू हो जानी चाहिए थी लेकिन सरकार ने इस दिशा में कुछ भी नहीं किया.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा था कि जो सरकारी विद्यालयों का संचालन करते हैं वे ऐसे काबिल शिक्षकों का चयन क्यों नहीं करते ताकि सरकारी विद्यालयों का स्तर भी उन विद्यालयों जैसा हो जाए जिनमें उनके खुद के बच्चे पढ़ते हैं? चूंकि नौकरशाहों, राजनेताओं व अमीर लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अन्य विकल्प खुले हैं इसलिए किसी को भी परिषदीय विद्यालयों की गुणवत्ता के बारे में कोई चिंता नहीं. सरकार को प्रावधानों में बदलाव लाकर उपर्युक्त श्रेणी के लोगों को अपने बच्चों को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने के लिए मजबूर करना चाहिए. न्यायाधीश ने इस तर्क को ही सिरे से खारिज कर दिया था कि लोगों का अपने बच्चों को अपने मन पसंद विद्यालय में पढ़ाने का अधिकार है.

देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं लागू हैं. पैसे वाले अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेज रहे हैं जहां बड़ा शुल्क लिया जाता है और जहां से निकलने के बाद बच्चा उच्च शिक्षा पूरी कर कहीं न कहीं नौकरी पा जाता है अथवा अपना कुछ काम शुरू कर सकता है. जिनके पास इन निजी विद्यालयों में पढ़ाने का पैसा नहीं वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने के लिए अभिशप्त हैं, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. इन विद्यालयों के बच्चे आगे चल कर नकल करके अपनी परीक्षा देने को मजबूर होते हैं. नतीजा यह होता है कि कक्षा आठ तक आते आते भारत के आधे बच्चे विद्यालय से बाहर हो जाते हैं या शिक्षा पूरी होने पर भी बेरोजगार रहते हैं. दुनिया में जहां भी शिक्षा का लोकव्यापीकरण हुआ है वह समान शिक्षा प्रणाली और पड़ोस के विद्यालय से ही सम्भव हुआ है जिसका संचालन सरकार के हाथ में रहा है.

सामाजिक-राजनीतिक संगठनों की मांग है कि देश में चुनाव लड़ने व सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए सरकारी विद्यालय से पढ़ा होना तथा उनके बच्चों का सरकारी विद्यालय में पढ़ना अनिवार्य शर्त हो. इसी तरह सरकारी वेतन पाने वालों व जन प्रतिनिधियों व उन पर आश्रित लोगों के लिए सरकारी चिकित्सालय में इलाज कराना भी अनिवार्य हो. ये संगठन शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सभी निजी संस्थानों के सरकारीकरण के पक्ष में हैं जिससे सभी नागरिकों को शिक्षा व चिकित्सा का लाभ एक समान व मुफ्त मिल सके. सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के नेता संदीप पांडेय का कहना है कि यह संघर्ष देश के संसाधनों व सुविधाओं को अपने हक में कर लेने वाली व्यवस्था के खिलाफ है जो गरीबों को वंचित बना कर जीने के लिए मजबूर किए हुए है. संघर्ष में सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के साथ फ्यूचर ऑफ इंडिया, नैतिक पार्टी, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, जन अधिकार संघर्ष मोर्चा, नींव, शिक्षा का अधिकार अभियान, बेसिक शिक्षा मंच, नगर अभिभावक मंच, आशा परिवार, आस्था किरन, एक्शन फॉर सोशल जस्टिस, इंसानी बिरादरी, बालमंच, रिहाई मंच, रेड ब्रिगेड समेत कई अन्य सामाजिक-राजनीतिक संगठन शरीक हैं.

संदीप पांडेय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ उच्च न्यायालय के फैसले की अनदेखी कर रही है तो दूसरी तरफ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत दुर्बल वर्ग एवं अलाभित समूह के बच्चों को विभिन्न विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षण के तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दाखिले के जो आदेश किए जा रहे हैं उनका पालन करवाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रही. पूरी शासन-प्रशासन व्यवस्था गरीब बच्चों के हितों के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है. इन बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं. हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में साफ-साफ कहा है कि परिषदीय विद्यालयों को चलाने के जिम्मेदार लोग अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें परिषदीय विद्यालयों की कोई चिंता ही नहीं. सरकारी विद्यालयों की स्थिति इतनी खराब है कि कोई मजबूरी में ही अपने बच्चे को वहां पढ़ाता है. अभिभावकों को भी मालूम है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने के बाद बच्चों का कोई भविष्य नहीं है. इसलिए जैसे ही उन्हें यह विकल्प नज़र आया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वे अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पढ़ा सकते हैं, उन्होंने इसे चुन लिया. इस प्रक्रिया में बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां आवेदन कर उन विद्यालयों के विकल्प दिए जाते हैं जहां अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं. बेसिक शिक्षा अधिकारी तय करता है कि बच्चा कहां पढ़ेगा. लेकिन निजी विद्यालय इस प्रावधान से बचने के लिए रास्ते खोज रहे हैं. जो बड़े शिक्षा माठाधीश हैं, वे खुल्लम-खुल्ला इसका विरोध कर रहे हैं.

संदीप पांडेय इसके उदाहरणस्वरूप लखनऊ के सबसे बड़े विद्यालय सिटी मांटेसरी स्कूल का हवाला देते हैं जिसने अदालत जाकर वर्ष 2015 में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दाखिले के लिए अनुशंसित बच्चों का दाखिला देने से इन्कार करने का दुस्साहस किया. इस पर अदालत द्वारा सख्त रुख अपनाए जाने पर सिटी मांटेसरी के मालिक जगदीश गांधी को उन बच्चों को दाखिला देना पड़ा. इस वर्ष भी 18 बच्चों को कक्षा-1 और कुछ बच्चों को नर्सरी में दाखिला देने का आदेश है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहा. संदीप पांडेय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिटी मांटेसरी स्कूल के मालिक जगदीश गांधी की पत्नी भारती गांधी को एक लाख रुपये नकद समेत रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार दिए जाने पर भी सवाल उठाया. संदीप ने कहा कि लखनऊ में सिटी मांटेसरी के अलावा नवयुग रेडियंस के मालिक सुधीर शंकर हलवासिया भी उन 15 बच्चों का अपने विद्यालय में दाखिला नहीं दे रहे, जिनके दाखिले का आदेश बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी किया हुआ है. इसके अलावा एक्सॉन इंटर कालेज, विक्टोरिया गंज, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, बंगला बाजार व कुछ अन्य विद्यालय भी शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के तहत बच्चों को दाखिला देने को तैयार नहीं और सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं. यदि निजी विद्यालय सरकार की व्यवस्था की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार से सीख लेकर इन निजी विद्यालयों का सरकारीकरण कर देना चाहिए. अंततः शिक्षा की व्यवस्था 1968 के कोठारी आयोग की सिफारिश के तहत समान शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही होनी चाहिए. इस दिशा में हाईकोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है कि जब अधिकारियों, नेताओं, न्यायाधीशों के बच्चे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ेंगे तो इन विद्यालयों की गुणवत्ता सुधर जाएगी. जब सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अभिभावक क्यों निजी विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ाने में पैसा खर्च करेंगे. धीरे-धीरे निजी विद्यालयों की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी और ये विद्यालय बंद होने लगेंगे अथवा इनका सरकारीकरण हो जाएगा.■

बसपा के बाग़ी आरके चौधरी की रैली में शरीक हुए बिहार के मुख्यमंत्री

नीतीश ने फिर ललकारा सपाइयों को

चौथी दुनिया ब्यूरो

समाजवादी पार्टी की घबराहट अब सार्वजनिक होने लगी है. बसपा छोड़ कर अलग हुए आरके चौधरी द्वारा आयोजित सभा को इजाजत देने के सवाल को लेकर जिस तरह समाजवादी सरकार ने बालहठ दिखाया, उससे पार्टी की फजीहत ही हुई. सभा को मंजूरी नहीं देने के बाद उसे वापस लेकर फिर मंजूरी देने के फैसले से पार्टी को जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आतिथ्य में सभा होने देने से नहीं होता. बहुजन समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति के तत्वावधान में आरके चौधरी ने छत्रपति शाहू जी महाराज जयंती के मौके पर लखनऊ के बिजली पासी किला परिसर में सभा आयोजित की थी. अखिलेश सरकार ने सभा की इजाजत नहीं दी, जबकि चौधरी और उनके समर्थक वहीं पर सभा करने पर आमादा थे. आखिरकार सरकार झुकी और सभा की इजाजत देनी पड़ी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर लखनऊ आकर समाजवादियों को खूब ललकारा. नीतीश ने कहा कि लोहिया के विचार पर चलने का दावा करने वाली सपा सरकार लोहियावादी नीतीश कुमार को सभा करने से रोक देती है.

नीतीश कुमार ने बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी का हवाला देते हुए फिर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया और कहा कि यूपी में शराबबंदी लागू होनी चाहिए. नीतीश ने शराबबंदी से होने वाले आर्थिक फायदे का हिसाब भी अखिलेश को सुझाया. उन्होंने कहा कि लोग जब शराब नहीं पिएंगे तो पैसा अच्छे काम में लगेगा और यूपी की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी. नीतीश ने बिहार में किए गए काम का जिक्र करते हुए यहां पर लागू महिला आरक्षण की भी याद दिलाई. इस तरह नीतीश

ने मायावती पर भी प्रहार किया और कहा कि सिर्फ बहुजन समाज बोलने से नहीं होता, उसकी पीड़ा भी समझनी चाहिए. नीतीश कुमार ने कहा कि वह आरके चौधरी के साथ कदम से कदम मिलाकर उत्तर प्रदेश में चलने के लिए तैयार हैं.

आरके चौधरी ने भी मायावती पर जमकर निशाना साधा और उन्हें पैसों का लालची बताया. चौधरी ने कहा कि मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज का हित संभव नहीं है. वो पैसे के लिए टिकट बेचती हैं. आरके चौधरी ने मायावती के साथ ही बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा पर भी आरोप लगाया कि लखनऊ में सभा न हो इस षडयंत्र में मिश्र भी लगे हुए थे, लेकिन उनकी जिद थी कि वो रैली करेंगे और उन्होंने रैली करके दिखाई. चौधरी ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक महीना पहले से ही सभा की इजाजत के लिए वे अर्जी दे चुके थे, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते उन्हें इतनी मशक्कत करनी पड़ी. सभा में बिहार जनता दल (यू) के नेता उदय नारायण चौधरी और उत्तर प्रदेश जदयू के अध्यक्ष सुरेश निरंजन भइया भी शरीक थे. ■

चौधरी आगे निकले, मौर्य भी रैली की तैयारी में

बसपा से बगावत करके निकले आरके चौधरी रैली आयोजित कर अपनी ताकत दिखाने में स्वामी प्रसाद मौर्य से आगे निकल गए. जबकि पार्टी छोड़ कर मौर्य पहले निकले थे, चौधरी बाद में. बसपा छोड़ कर निकले बागी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रमाबाई अंबेडकर स्टेडियम में 22 सितम्बर को जोरदार रैली आयोजित करने की तैयारी में लगे हैं. मौर्य अपनी जन-शक्ति को उसी स्थान पर जुटाना चाहते हैं जिस रैली स्थल का निर्माण मायावती ने ही कराया था. ■

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा नेता के अपशब्द पर बसपा नेताओं ने की गालियों की बौछार

गंदगी बनाम गंदगी

राजनीति में विचारों की मतभिन्नता के बावजूद अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए. बहरहाल, जिस बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह हतोत्साहित आंका जा रहा था, वही पार्टी अपशब्द सुन कर अचानक जाग्रत अवस्था में आ गई. उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच अपना स्थान प्रगाढ़ करने में कामयाब हो रही भाजपा को अचानक कुल्हाड़ी लग गई. निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह के मैदान में कूद पड़ने से भाजपा को थोड़ी राहत जरूर मिली और बसपा को अपने अपशब्दों के कारण बैकफुट पर जाना पड़ा.

आशीष वशिष्ठ

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दिन जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे-वैसे प्रदेश की सियासत का स्तर धराशाई होता जा रहा है. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती पर विवादास्पद टिप्पणी करने से राजनीति गर्मा गई. भाजपा ने विवादित बोल बोलने वाले नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. बसपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपशब्द का जवाब अपशब्द से देकर एक ही थैली के चट्टेबट्टे होने को प्रमाणित कर दिया है. बसपा की एकछत्र नेता मायावती को आखिर इस बात का एहसास हो ही गया कि अपमानजनक शब्दों के घाव कितने गहरे होते हैं.

राजनीति के अखाड़े में बयानबाजी के सहारे एक-दूसरे पर कीचड़ उछालना नेताओं की फितरत बन गई है. इस बार भाजपा फंसी और खस्ता हालत से जूझ रही बसपा को अवसर भुनाने का अवसर दे दिया. धरना-प्रदर्शन और नाराजगी के माहौल में मायावती ने खुद को देवी की उपाधि भी दे डाली. अपने जन्मदिन पर हीरों के जेवरात का उपहार लेने वाली इस दलित नेता के पास आज बेशुमार दौलत है. मतिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार' का नारा देने वाले कांशीराम की उत्तराधिकारिणी मायावती ने अपने गुरु का नारा, महाथी नहीं गणेश है, ब्रम्हा, विष्णु महेश है', में बदल कर सोशल इंजीनियरिंग

का दांव खेला था और 2007 के विधान सभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल किया था. मायावती ने पांच साल के राज में पार्क, स्मारक बनाने और दलित महापुरुषों के साथ अपनी मूर्ति लगाने में सारी सरकारी मशीनरी झोंक दी थी और सरकारी खजाने की लूट और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे. जनता ने मायावती को ठुकरा दिया और सपा को मौका दिया. बसपा बिलुप्तप्राय हो गई थी. लोग यह मानते हैं कि बसपा में सिद्धान्तों और आदर्शों की कोई जगह नहीं है. लेकिन भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के बयान ने मरते दल को कुरामिन दे दिया.

हालांकि मायावती और उनकी पार्टी के कई अन्य नेता सवर्ण जातियों के विरुद्ध अतीत में जिस तरह की बातें किया करते थे वह भी मर्यादा का घोर उल्लंघन ही था. कांग्रेस में कुछ बरस बिताकर सपा में लौटे बेनी प्रसाद वर्मा की जुबान किस तरह बेलगाम है, यह सर्वविदित है. अखिलेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खां को भी अनर्गल प्रलाप करने की बीमारी है. राजनीति में विचारों की मतभिन्नता के बावजूद अभिव्यक्ति की स्वछंदता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए. बहरहाल, जिस बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह हतोत्साहित आंका जा रहा था, वही पार्टी अपशब्द सुन कर अचानक जाग्रत अवस्था में आ गई. उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच अपना स्थान प्रगाढ़ करने में कामयाब हो रही भाजपा को अचानक कुल्हाड़ी लग गई. निष्कासित नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह के मैदान में कूद पड़ने से भाजपा को थोड़ी राहत जरूर मिली और बसपा को अपने अपशब्दों के कारण बैकफुट पर जाना पड़ा. ■

feedback@chauthiduniya.com

गाली कांड के लाभ

मृत्युंजय दीक्षित

जब से संसद का मानसून सत्र प्रारम्भ हुआ है तब से बसपा नेता मायावती गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र आदि भाजपा शासित राज्यों में दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे उठाकर भाजपा को घेरने का असफल प्रयास कर रही थीं. लेकिन उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ विवादास्पद शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें यह सुअवसर दे दिया. घटनाक्रम का पहला चरण निश्चय ही भाजपा के लिए बहुत भारी पड़ गया. केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को राज्यसभा में माफी मांगनी पड़ी और भाजपा हाईकमान को दयाशंकर सिंह को छह वर्ष के लिए पार्टी से निकालना पड़ा. निश्चित तौर पर मायावती इस प्रकरण को चुनाव में भुनाने का प्रयास करेंगी. बिहार चुनाव के समय मोदी के नीतीश के लिए डीएनए वाले बयान और संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान को जिस तरह विरोधियों ने भुनाया था. राजधानी लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जिस प्रकार दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों की बौछार की, वह लोकतंत्र का और भी अधिक शर्मनाक परिदृश्य पैदा कर रहा था. एक अपशब्द के मुकाबले बसपा कार्यकर्ताओं ने सभी मर्यादाओं को ताक पर रखकर मंच से हजारों गालियां उछालीं. मायावती को यह याद नहीं रहा कि समाजवादी सरकार के कार्यकाल में गेस्ट हाउस कांड के समय भाजपा ने ही उनकी प्रतिष्ठा बचाई थी. इस प्रकरण के बाद सवर्ण मतदाता बसपा से विमुख होता दिख रहा है. जबकि दलितों का एक खास समुदाय मायावती के प्रति प्रतिबद्ध है. ■

अन्य महिलाओं की प्रतिष्ठा भी उतनी ही अहम है

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

किसी पार्टी को यह खुशफहमी नहीं होनी चाहिए उसके यहां विवादास्पद बयान देने वाले बहादुरों का अभाव है. बसपा द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में दयाशंकर सिंह की पत्नी, बेटी, बहन आदि के संबंध में अश्लील बातें कह कर बसपाइयों ने दयाशंकर सिंह के बयानों के प्रति लोगों के आक्रोश और मायावती के लिए बन रहे सहानुभूति के भाव को धो कर रख दिया. यह साबित हो गया कि दयाशंकर सिंह द्वारा इस्तेमाल में लाए गए शब्द पर बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के अपशब्द भारी थे. भाजपा ने अधिकृत रूप से दयाशंकर सिंह के बयान को बेहद निन्दनीय बताया. प्रश्न मायावती से है कि दयाशंकर सिंह के घर की महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें करने वाले बसपा नेताओं को उन्होंने निष्कासित क्यों नहीं किया? मायावती ने खुद को देवी बताया, लेकिन यह नहीं समझा कि निर्दोष महिलाओं का अपमान करना भी उतना ही तिरस्कार योग्य है. केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई कि गेस्ट हाउस कांड में कैसे भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती को बचाया था. मायावती को उस दिन की घटना भूलनी नहीं चाहिए, यह भी कि भाजपा की ही मदद से मायावती दो बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थीं. ■

क्या मान-सम्मान सिर्फ मायावती का है?

श्याम कुमार

आशा की जा रही थी कि लखनऊ के प्रदर्शन में बसपाइयों द्वारा प्रयोग की गई अभद्र भाषा पर मायावती अपनी पत्रकारवार्ता में खेद व्यक्त करेंगी और एक वरिष्ठ एवं जमीनी नेता की भांति समूचे अशांत प्रकरण को शांत कर देंगी. इससे उनका कद ऊंचा उठ जाता. लेकिन मायावती ने ऐसा नहीं किया. उन्होंने उल्टा तर्क दिया कि बसपा के प्रदर्शन में जो वाक्य कहे गए, उनका गलत अर्थ निकाला गया. नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी उसी तरह के न समझ में आने वाले तर्क दिए.

दूसरी तरफ दयाशंकर सिंह ने स्वयं माफी मांग ली थी. भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने संसद में माफी मांगी थी. दयाशंकर को तुरंत न केवल पार्टी के उपाध्यक्ष पद से हटाया गया, बल्कि पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया. इन सबके बावजूद मायावती और उनके सिपहसालारों को दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं एवं बच्ची के प्रति अपशब्द उछालने से ही संतुष्टि मिली, यह बात प्रदेश के लोगों को हजम नहीं हुई. आम लोग भी कह रहे हैं कि गलती दयाशंकर सिंह ने की तो उनके घर की महिलाओं एवं बच्ची को इसमें क्यों घसीटा गया? मायावती ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहा कि वह उन्हें बुआ कहते हैं तो दयाशंकर सिंह को गिरफ्तार कराएं. इस पर लोगों का कहना है कि दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह ने भी नसीमुद्दीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस पर भी उनकी अविलम्ब गिरफ्तारी होनी चाहिए. स्वाति सिंह ने प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से मिलकर मांग की है कि उनकी बच्ची के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले बसपा नेताओं के विरुद्ध बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के अंतर्गत कार्रवाई की जाए. राज्यपाल ने बसपा के प्रदर्शन की सीडी तलब की है. उन्होंने पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद से सीडी उपलब्ध कराने को कहा है. ■

प्रख्यात तबला वादक लच्छू महाराज नहीं रहे

संत-संगीतकार का महानिर्वाण...

प्रभात रंजन दीन

प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने जैसे ही कहा कि लच्छू महाराज नहीं रहे, हम सब स्तब्ध रह गए... संतोष जी ने मुझसे कहा कि लच्छू महाराज के जीवन का आखिरी इंटरव्यू करने का सौभाग्य आपको मिला... लेकिन मुझे लगता है कि लच्छू महाराज का अंतिम संदेश सुनने का प्रकृति ने मुझे सौभाग्य प्रदान किया था. भगवान शंकर के वाद्य का वह औघड़ उस्ताद अभी कुछ ही दिन पहले जीवंत मेरे सामने था और उस अद्वितीय कलाकार का साक्षात्कार करने का मैं साहस नहीं जुटा पा रहा था. मैंने महाराज जी से कहा भी था कि मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण कर रहा हूं. जो विधा आपकी है, जो संसार आपका है, उसमें हम आपसे कोई सवाल पूछने के सक्षम नहीं हैं. जो आप कहेंगे, जो आप बताएंगे, जो आप अपने संस्मरणों से गुजरेंगे वही साक्षात्कार है... और वही साक्षात-कथ्य 'चौथी दुनिया' के अंक में प्रकाशित हुआ.

लक्ष्मी नारायण सिंह जिन्हें संगीत के आधार-वाद्य तबला के विधा-संसार में पंडित लच्छू महाराज के नाम से जाना जाता है, जो तबले पर हाथ रखते थे तो उंगलियां दिखाई नहीं देती थीं, प्रख्यात नर्तकियां तक लच्छू महाराज के तबले की थाप के आगे कठपुतली की तरह थिरकने लगती थीं और श्रोता मस्त भाव-विभोर हो जाते थे, वह लच्छू महाराज आज हमारे बीच नहीं रहे. बनारस घराने के लच्छू महाराज ने तबला के दस हजार से अधिक बोलों को आत्मसात किया था और 14 से 18 घंटे तक लगातार तबला बजाने का रिकॉर्ड एक बार नहीं, कई-कई बार बनाया था. संगीत का वह महापुरुष एक संजीदा कलाकार भी था और फक्कड़ संत भी. आधुनिकता और भौतिकता की अंधी दौड़ में भारतीय संस्कृति, खास कर शास्त्रीय संगीत के खोते जाने के प्रति लच्छू महाराज चिंतित रहते थे और संगीत की विधा में फिर से गुरुकुल परंपरा की बहाली की हिमायत करते थे. वे मानते थे कि भारतीय संगीत और संस्कृति को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी शासक की होती है. उस औघड़ संत-संगीतकार से पिछले दिनों दिल्ली में मुलाकात हुई थी तो बस उनको सुनता ही रहा. कोई औपचारिक सवाल नहीं. सवाल के नाम पर अपनी जिज्ञासाओं का केवल एक इशारा भर, और एकबारगी सारा समाधान सामने. जिस व्यक्तित्व को मैंने अभी हाल ही सुना वह इतनी जल्दी संस्मरण हो जाएगा, यह प्रकृति का विचित्र किंतु सत्य किंतु दुखद रहस्य है.

'काश लच्छू मेरा बेटा होता'

लच्छू महाराज आठ साल की उम्र में जब मुंबई में एक कार्यक्रम में तबला बजा रहे थे तो जाने-माने तबला वादक अहमद जान थिरकवा ने कहा था, 'काश लच्छू मेरा बेटा होता.' तबला के उसी पुरोधा लच्छू महाराज का बुधवार 27 जुलाई की देर रात वाराणसी में हृदय गति रुकने से निधन हो गया. 16 अक्टूबर 1944 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में उनका जन्म हुआ था. वे फिल्म अभिनेता गोविंदा के मामा और गुरु दोनों थे.

लच्छू महाराज को इस बात का कतई अफसोस नहीं था कि उन्होंने पद्म पुरस्कार लौटा दिया था. उन्होंने ठहाके लगाते हुए कहा था, 'हमारी जिंदगी तो वैसी ही रही कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटते रहे.' लच्छू महाराज शास्त्रीय संगीत के साथ देश के सम्पूर्ण भविष्य की चिंता साथ लेकर गए. उनकी इस गहरी चिंता पर पूछा था तो उन्होंने बेसाख्ता कहा था, 'जो कल के आकार के लिए चिंतित न हो, वह कलाकार हो ही नहीं सकता. कल की चिंता जब केवल पैसे और शोहरत पर टिक जाए तो क्या होगा कल का?' यह सवाल सामने रखते हुए लच्छू महाराज ने कहा था, 'जो कल का आकार इस मुल्क का होना चाहिए, वह बिल्कुल नहीं दिख रहा है. मुल्क के कल के लिए कोई चिंतित भी नहीं दिखता है और इसी वजह से मैं अत्यंत दुखी हूं आत्मा से. हम देश के उसी कल के लिए जी रहे हैं, और तो कोई इच्छा बची नहीं शरीर में.' पद्म पुरस्कार जैसा सम्मान वापस करने के औघड़ी फैसले पर पूछने का साहस किया तो महाराज बोले थे, 'अपनी कोई महत्वाकांक्षा तो कभी भी रही नहीं. हमलोग अपने ही फक्कड़ विचार से मस्त मौला जीते रहे! आप हमको क्या दोगे, इस बारे में कभी सोचा नहीं, हम आपको क्या दे सकते हैं, इसके बारे में ही सोचते रहे और करते रहे. इच्छा तो यही रही कि मुझसे जितना हो सके, उतना ले लो. मेरे जैसे व्यक्ति के लिए व्यक्ति से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है. आपसे हम मिल लिए तो हमारे मन में आपसे मिलने की इच्छा हमेशा बनी रहे, हमसे आप मिल लिए तो आपके मन में हमसे मिलने की इच्छा बनी रहे... इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है. पहले कागजों पर पुरस्कार की परंपरा थी, कागज का जमाना था, उसे तो दीमक खा गए. अब कांसा, चांदी और सोने का पुरस्कार मिलता है, उसमें लोभ का दीमक लग गया है. मेरी नजर में न तो उस पुरस्कार का कोई मतलब था और न आज के पुरस्कार का कोई मतलब है.

तबला, ढोल या मृदंग को लच्छू महाराज नाद-स्वर का स्रोत मानते थे. उन्होंने कहा था, 'नाद ही ब्रह्मस्य, नाद ही स्वरूपः जगतः, नाद ही सर्व भूतेषु, नाद ही सर्वम मम्...' सिद्ध संतों जैसी वाणी बोलते हुए लच्छू महाराज ने कहा था, 'कोई नवजात बच्चा रोया तो वह नाद है. प्रलय भी होगा तो उसमें जो ध्वनि है वह नाद है. तितली भी फड़फड़ाती है तो संगीत बजता है, हिरन के कुलांचे में भी संगीत है. ऊं में सारा संगीत, सारे स्वर और सुर निहित हैं. मुझमें तुझमें खड्ग खंभ में घट घट व्यापत राम... ताल की मंद गति स्वास से जुटी रही, चूर भई खोपड़ी मसान में पड़ी रही... आदमी जैसे-जैसे उस प्रकृति के पास पहुंचता जाता है, वैसे-वैसे भौतिक लिप्साओं से दूर होता जाता है. फिर उसमें विशुद्ध मनुष्य होने की इच्छा जाग्रत होती है. तब यह इच्छा बलवती होती है कि हमारे देश के बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, अच्छा जीवन मिले, अच्छा विचार पैदा हो, सब ईमानदार हों. चिंता में डूबा हुआ उनका स्वगत प्रश्न उठता, 'लोग ईमानदार तो तभी होंगे न, जब उनका मूल ठीक होगा. बबूल का वृक्ष लगाएंगे और आम की कल्पना करेंगे, क्या यह संभव है? क्या यह उचित है?' लच्छू महाराज ने कहा था, 'आज जो स्थिति है वह अत्यंत विषम है. सारी विधाएं धंधा बन गई हैं. भूख अब विधा की नहीं रही. सारी विधाएं पेट की भूख, यश की भूख, महत्वाकांक्षा की भूख और भौतिक सुखों की भूख के आगे-पीछे नाचने लगी हैं. यह अत्यंत चिंता का विषय है.'

संगीत के बाजारीकरण से व्यथित लच्छू महाराज ने कहा था, 'संगीत की साधना ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है. लेकिन यह कह देने से तो नहीं होगा. जबतक समर्पण न हो, तब तक यह संभव नहीं है. जिस तरह का वातावरण जरूरी है संगीत के प्रति समर्पण का संस्कार पैदा करने के लिए, वह मौजूदा समय में है ही नहीं. समर्पण के अनिवार्य खाद पर हम ध्यान ही नहीं देते. इसीलिए संस्कार सूखते जा रहे हैं.' लच्छू महाराज का मानना था कि राजसत्ता का यह धर्म होना चाहिए कि नई पौध में ऐसा समर्पण जाग्रत करने के लिए जिस तरह का वातावरण जरूरी है उसे जंगल में सृजित करे और फिर उनके साथ दस बरस के लिए विद्यार्थियों को छोड़ दे. फिर देश उनसे अतुलनीय कलाकार प्राप्त कर ले. ऐसे गुरुकुल के स्वप्न को साकार करने के लिए जब मैंने उनसे कहा कि इसके लिए आप ही अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं करते! इस पर लच्छू महाराज इतना ही बोले थे, 'जिसे देखनी हो जन्नत मेरे साथ-साथ आए.' ...और लच्छू महाराज इन चिंताओं के नर्क में हमें छोड़ कर खुद जन्नत चले गए. उनकी बातें हमें नारकीयता से उबरने का संबल दें... ■

आलू

परिचय

मूलतः दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण भागों में प्राप्त होता है. स्पेन, पुर्तगाल तथा यूरोप में 16वीं सदी में तथा भारत में 17वीं सदी में तथा अन्य देशों में 19वीं सदी में आलू का प्रवेश पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों द्वारा हुआ. समस्त भारत में विशेषतः उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, बिहार, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व गुजरात में इसकी खेती की जाती है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

मुख रोग :

- **मुखपाक-** आलू के भूने हुए कंद का सेवन करने से मुखपाक में लाभ होता है.

वक्ष रोग :

- 2-5 मिली आलू पत्ते के रस में मधु तथा सेंधा नमक मिलाकर सेवन करने से गले की जलन आदि का शमन होता है.
- **खांसी-** 2-5 मिली आलू पत्ते के रस का सेवन करने से पुरानी खांसी में लाभ होता है.

वृक्कवस्ति रोग :

- मूत्राल्पता- आलू को भूनकर खाने से मूत्राल्पता में लाभ होता है.

त्वचा रोग :

- **दग्ध-** आलू को पीसकर जले हुए स्थान पर लेप करने से व्रण तथा शोथ में लाभ होता है.
- कच्चे आलू को काटकर दाद तथा खाज वाले स्थानों पर मलने से लाभ होता है.
- कच्चे आलू को पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की कान्ति बढ़ती है तथा झाईयां दूर हो जाती हैं.

सर्वशरीर रोग :

- **दौर्बल्य-** आलू को भूनकर हलवा बनाकर सेवन करने से यह पौष्टिक तथा बलदायक होता है.
- आलू को भूनकर अदरख तथा पुदीना डालकर यूष बनाकर पीने से क्षुधा की वृद्धि होती है तथा शारीरिक दौर्बल्य का शमन होता है.

प्रयोज्यांग : कंद तथा पत्र.
मात्रा : चिकित्सक के परामर्शानुसार.
विषाक्तता : हरे आलू के फल तथा हरे छिलके वाले कंद में कभी-कभी विषाक्त प्रभाव भी देखने को मिले हैं, अतः उनका आभ्यन्तर प्रयोग सावधानी से करना चाहिए. ■

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

सामान्य समस्याएं

निष्काम सेवा ही गुरु का प्रमुख ध्येय है

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

सामान्य जीवन और गुरुमार्ग

सामान्य जीवन जीना ही एक समस्या है, फिर समय के अभाव में भी श्री गुरु-मार्ग के लिये समय कैसे निकालें?

सामान्य जीवन सिर्फ़ आज ही नहीं अपितु हर युग में कठिन रहा है. सामान्य जीवन का अभिप्राय सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन से है. जो व्यक्ति घर छोड़ कर जोगी या साधु बन गए हैं, उनका भी मार्ग सरल नहीं है परन्तु भौतिक जगत में रहकर सामाजिक तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस मार्ग पर चलना एक समस्या तो है, पर इसी समस्या के समाधान के लिए तो हम गुरु-मार्ग ढूंढ रहे हैं. यह बहुत सरल है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है. आवश्यकता है मात्र इच्छाशक्ति और ईश्वर-प्रेरणा की. प्रथम अवस्था में कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण रूप से गुरु-मार्ग पर नहीं चल सकता. इसके लिए कई वर्षों का समय चाहिए. यदि गुरु ढूंढने का प्रयास करना, इस संबंध में किताबें पढ़ना, गुरु की जीवनी पढ़ना, अपना आचरण पवित्र करना, आदि गुणों को मनुष्य विकसित करता जाए तो धीरे-धीरे उसके अंतर्मन में सद्गुरु के विचारों को प्रस्फुटन होगा. इस स्थिति में कहीं न कहीं गुरु उसको मिलेंगे ही. कहा जाता है कि शिष्य गुरु को नहीं ढूंढ सकता, मगर सद्गुरु जरूर अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं. जैसा कि बाबा ने कहा है, मेरे भक्त हजार मील की दूरी पर हों फिर भी मैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता हूं. इस कठिनाई के जीवन में भी दया, क्षमा, सहनशीलता, सेवा-भाव आदि गुणों को विकसित करना ही, असली बात है. निष्काम सेवा ही गुरु का प्रमुख ध्येय है. निष्कर्ष यह है कि शुरू में छोटे स्तर से गुरु की आज्ञा का पालन करें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें. यह गुण जीवन का अभिन्न अंग है, इन्हें जीवन से अलग नहीं किया जा सकता. सामान्य जीवनकाल में ही इन गुणों को विकसित करने का ज्यादा मौका मिलता है, क्योंकि उस संघर्ष के दौरान व्यक्ति अपने जिन गुणों को विकसित करता है, वह गुण स्थाई रूप से बने रहते हैं और तभी उसका उत्कर्ष होता है.

पारिवारिक व्यक्ति के लिए गुरु-मार्ग

परिवार यदि हमारा साथ न दे, तो क्या हमें फिर भी श्री गुरु-मार्ग को अपनाए रखना चाहिए?

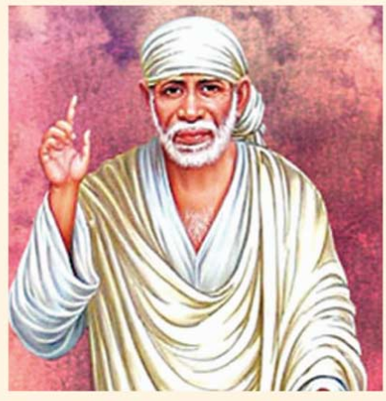

गुरु-मार्ग पर परिवार को साथ लेकर चलना चाहिए. अन्ततोगत्वा आत्मा अकेली ही है और गुरु के साथ रहेगी. सर्वप्रथम माता-पिता गुरु के रूप में मिले. जब आत्मा अकेली थी, तब माता-पिता गुरु बनकर उसको लाये. इसीलिए परिवार में सामंजस्य बनाते हुए धैर्य एवं विवेक के साथ बुद्धि का प्रयोग करते हुए गुरु को धारण करना चाहिए. परिवार के प्रति कर्त्तव्यपरायणता छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और न ही आवश्यक है गुरु की ब्रह्म पूजा. सभी कर्त्तव्यों का पालन करते हुए तथा अंतर्मन में गुरु को रखकर एवं उन्हें सर्वस्व अर्पण करते हुए मनुष्य परिवार में रहकर भी गुरु-मार्ग पर चल सकता है. परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों की अवहेलना करते हुए गुरु-पूजा नहीं हो सकती. उदाहरणार्थ बच्चे की शिक्षा की उपेक्षा करते हुए गुरु-सेवा व्यर्थ है, क्योंकि बच्चा भी तो गुरु और ईश्वर की देन है. इंसान अकेले ही यदि गुरु-मार्ग का अनुसरण करना चाहे, तो उसके लिए संन्यास लेना ही उचित है, परन्तु गृहस्थ आदमी को गुरु-मार्ग का अनुसरण पारिवारिक दायरे में रहकर ही करना होगा. ■

चौथी दुनिया व्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

रियो में पदक जीतकर मोहम्मद शाहिद को असली श्रद्धांजलि दे सकेगी भारतीय टीम

शाहिद तुमको नहीं भूल सकती है हॉकी

देश में भारतीय हॉकी को लेकर तमाम बातें होती है लेकिन इतिहास में भारतीय हॉकी अमर है. पूर्व में भारतीय हॉकी का कोई सानी नहीं था. कई ऐसे खिलाड़ी थे जो विश्व खेल पटल पर भारतीय हॉकी को एक अलग मुकाम दिया है. इनमें से एक मोहम्मद शाहिद भी थे. जिनकी हॉकी स्टिक मैदान पर चलती थी तो विरोधियों को इनकी काट खोजने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी. बनारस की तंग गलियों में शाहिद की हॉकी हमेशा सुर्खियों में रहती थी. कहा जाता है मोहम्मद शाहिद में हॉकी के जनक ध्यानचंद का अक्स दिखता था.

सैयद मोहम्मद अब्बास

देश में इस समय रियो ओलम्पिक को लेकर चर्चा हो रही है. तमाम देशों के खिलाड़ी रियो के खेल में खुद को अव्वल साबित करने में लगे हुए है. ऐसे में भारतीय दल भी अपनी मजबूत तैयारी के साथ ओलम्पिक में उतर रहे हैं. हिन्दुस्तान के नामी-गिरामी खिलाड़ी केवल भारत का झंडा बुलंद करने की बात कर रहे हैं. इनमें से एक खेल ऐसा भी है जिसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला हुआ है. जी हां हॉकी आज अपने पुराने वजूद को पाने में लगी है. यह वही हॉकी है जिसने कभी भारत को इस खेल का सिरमौर बनाया था. अतीत और वर्तमान के बीच फंसी भारतीय हॉकी अब तक 70 और 80 दशक की सुनहरी यादों के सहारे जी रही है. हाल के दिनों भारतीय हॉकी बेहद कमज़ोर साबित हुई है. 90 के दशक के बाद भारतीय हॉकी ख़स्ता हाल हो चुकी थी. आलम तो यह था कि इसके राष्ट्रीय खेल के होने पर सवाल खड़ा कर दिया गया था. भारतीय हॉकी को बचाने के लिए आये दिन योजनाएं बनाए जाने लगी. जिस हॉकी की तूती पूरे विश्व में बोलती थी वह कई लोगों के निशाने पर रही. रियो ओलम्पिक में भारतीय हॉकी कैसा प्रदर्शन करती है यह तो आने वाला वक्त बतायेगा. ओलम्पिक से पहले भारतीय हॉकी को बहुत बड़ा सदमा लगा है. हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद ने दुनिया छोड़ दी है.

80 से लेकर 90 के दशक के शुरुआती दिनों में मोहम्मद शाहिद के हॉकी की चर्चा चारों तरफ होती थी. रियो ओलम्पिक के लिए भारतीय हॉकी टीम कूच कर चुकी है लेकिन मोहम्मद शाहिद के खोने का गम किसी से छुपा नहीं है. गमगीन माहौल में ओलम्पिक में जलवा दिखाने जा रही श्रीजेश की टीम अगर रियो में कमाल करती है तो मोहम्मद शाहिद को असली श्रद्धांजलि दे सकेगी.

देश में भारतीय हॉकी को लेकर तमाम बातें होती है लेकिन इतिहास में भारतीय हॉकी अमर है. पूर्व में भारतीय हॉकी का कोई सानी नहीं था. कई ऐसे खिलाड़ी थे जो विश्व खेल पटल पर भारतीय हॉकी को एक अलग मुकाम दिया है. इनमें से एक मोहम्मद शाहिद भी थे. जिनकी हॉकी स्टिक मैदान पर चलती थी तो विरोधियों को इनकी काट खोजने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी. बनारस की तंग गलियों में शाहिद की हॉकी हमेशा सुर्खियों में रहती थी. कहा जाता है मोहम्मद शाहिद में हॉकी के जनक ध्यानचंद का अक्स दिखता था. 80 के दशक में अगर भारतीय हॉकी चमक रही थी तो इसमें शाहिद का अहम योगदान था. बनारस की धरती अगर शहनाई के बेताज बादशाह इस्ताद बिस्मिल्लाह खान के रूप में देखी जाती हो लेकिन शाहिद हॉकी स्टिक की खूब बात होती है. वाराणसी के कचहरी से सटे अर्दली बाज़ार में रहने वाले शाहिद ने गेंद को स्टिक से ड्रिबल करने की कला में महारथ हासिल की थी. केवल 17 साल

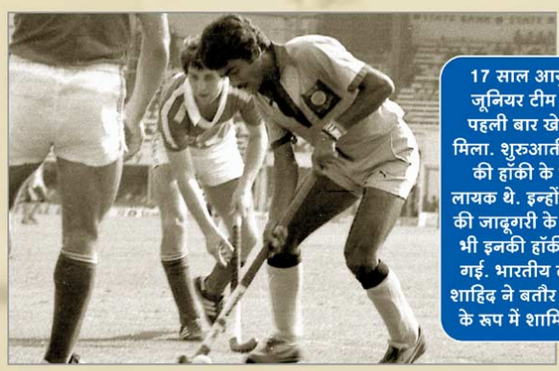

17 साल आयु में भारत की जूनियर टीम में शाहिद को पहली बार खेलने का मौका मिला. शुरुआती मैचों में शाहिद की हॉकी के करतब देखने लायक थे. इन्होंने अपनी कलाई की जादूगरी के बदौलत दुनिया भी इनकी हॉकी की मुरीद बन गई. भारतीय टीम में मोहम्मद शाहिद ने बतौर फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया.

आयु में भारत की जूनियर टीम में शाहिद को पहली बार खेलने का मौका मिला. शुरुआती मैचों में शाहिद की हॉकी के करतब देखने लायक थे. इन्होंने अपनी कलाई की जादूगरी के बदौलत दुनिया भी इनकी हॉकी की मुरीद बन गई. भारतीय टीम में मोहम्मद शाहिद ने बतौर फॉरवर्ड खिलाड़ी के रूप शामिल किया गया. जूनियर स्तर पर अपनी छाप छोड़ने के बाद शाहिद को सीनियर टीम में दस्तक देनी शुरू कर दी. 80 के दशक में मोहम्मद शाहिद के रूप में भारत को ड्रिबलिंग का एक नया सितारा मिल गया था. 1980 को भारतीय हॉकी स्वर्णिम दौर कहा जाता है. इस साल मोहम्मद शाहिद की हॉकी भी पूरे इफान पर थी. यह वही दौर था जब भारतीय हॉकी टीम को शाहिद और जफ़र की जोड़ी की चर्चा दुनिया-जहां में होती थी. 1980 में पाकिस्तान आयोजित चौम्पियंस ट्रॉफी में इनके खेल को देखकर बेस्ट फॉरवर्ड प्लेयर खिताब दिया गया था. मास्को ओलम्पिक में मोहम्मद शाहिद का खेल देखते ही बनता था. भारतीय टीम ने इस ओलम्पिक स्वर्णिम प्रदर्शन करते हुए सोने का तमगा हासिल किया था. दरअसल यह स्वर्ण इसलिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि हॉकी में भारत ने 16 बाद सोना जीता था. इस जीत में मोहम्मद शाहिद का बड़ा योगदान था. इनके हॉकी में ख़ास योगदान के लिए कई सम्मान भी दिये गए. इनमें अर्जुन अवॉर्ड (1982), पद्मश्री (1986), यश-भारती (1995) और लक्ष्मण पुरस्कार (2006) शामिल है.

ख़ैर तमाम उपलब्धि के बीच अहम मुद्दा यह है कि हाल के दिनों में मोहम्मद शाहिद जैसा कोई खिलाड़ी सामने नहीं आया. शाहिद अब हमारे बीच नहीं रहे लेकिन इनकी यादें आज भी जिंदा है. मैदान पर जीतने का दम भरने वाले शाहिद किडनी और लीवर की बीमारी से जूझने और लड़ने के बावजूद इसे हरा नहीं पाये हैं लेकिन मैदान पर इनका लड़ना हमेशा से यादगार रहा है.■

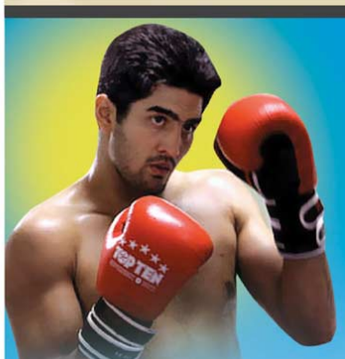

काश विजेंद्र ओलम्पिक में भाग ले सकते

ओलम्पिक शुरू होने में बेहद कम दिन रह गया है. भारतीय खिलाड़ी ओलम्पिक में दम-खम दिखाने को तैयार है. लगभग सभी खेलों में पदक जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने कमर कस ली है. दरअसल ओलम्पिक में भाग लेने का सपना हर एथलीट का होता है. करियर में एक बार ओलम्पिक में भाग ले लिया तो समझो करियर सफल हो गया. भले ही खिलाड़ियों की तमाम उपलब्धियों हो लेकिन इसमें ओलम्पिक शामिल न हो तो इसके करियर में खालीपन रहता है. रियो ओलम्पिक को लेकर भारतीय खिलाड़ियों में अलग जज्बा देखा जा सकता है. तिरंगे के बैनर तले खेलना का एक अलग अनुभव होता है. खिलाड़ी के रग-रग में देशभक्ति का खून दौड़ता है. ओलम्पिक में इस बार भारत की तरफ से 122 खिलाड़ी रियो की धरती पर भारतीय तिरंगा बुलंद कर रहे हैं. प्रत्येक खेल में भारतीय खिलाड़ी पदक की हुंकार भरने को तैयार है. निशानेबाज़ी से लेकर बैडमिंटन तक में भारतीय खिलाड़ी पदक की होड़ में शामिल है. मुक्केबाज़ी की बात की जाय तो इसमें पदक की अपार सम्भावनायें दिख रही है लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी जो ओलम्पिक में भारतीय टीम को पदक दिला सकता था. इसके मुक्के में बड़ा दम है, जब इसका मुक्का चलता है तो विरोधियों के होश ठिकाने लग जाते हैं पर अफसोस ओलम्पिक में इसका मुक्का नहीं चलेगा. भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह के पेशेवर मुक्केबाज़ी में कदम रखने के बाद से ही यह लगने लगा था कि वह ओलम्पिक जैसी प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधत्व नहीं कर पायेंगे. हालांकि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज़ी संघ के पेशेवर मुक्केबाज़ों को अनुमति देने के फैसले के बाद विजेंदर सिंह के लिए ओलम्पिक में खेलने के रास्ते खुल गये. इन्हें ओलम्पिक का टिकट तभी मिल सकता जब एआईबीए विश्व क्वालीफाईंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था लेकिन विकास कृष्णन के 75 किग्रा भार वर्ग में जगह बनायी. इस कारण से विजेंदर सिंह की उम्मीदें दम तोड़ गई क्योंकि विजेंदर सिंह भी इसी भार वर्ग में हिस्सा लेना चाहते थें. हाल के दिनों में विजेंद्र का मुक्का लगातार बरस रहा है. पेशेवार मुक्केबाज़ी में रम चुके विजेंदर सिंह की कमी ओलम्पिक में भारत को खलेंगी. प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले विजेंदर सिंह ने बेहद शानदार शुरुआत की है. उन्होंने

2015 में इसमें कदम रखा था. इसके बाद से वह लगातार सातवीं जीत दर्ज अपने मुक्के का लोहा मनवाया. अभी हाल में ऑस्ट्रेलियाई मुक्केबाज़ केरी होप को चारों-खाने चित कर दुनिया प्रोफेशनल बॉक्सरों को चेताया है. इसी क्रम में विजेंदर सिंह डब्ल्यूबीओ एशिया पैसेफिक चौम्पियन का ख़िताब भी अपने नाम किया. इसके बाद विजेंदर सिंह ने पाकिस्तान में जन्में ब्रिटिश मुक्केबाज़ आमिर खान को ललकारे हुए इनसे मुकाबला करने की बात कही लेकिन इसके पलट आमिर ने भी विजेंदर सिंह को चेतावनी दे डाली. आमिर ने यहां तक कहा डाला कि वह विजेंदर सिंह के करियर को तबाह कर देंगे.

विजेंदर सिंह भारतीय मुक्केबाज़ी के चमकते हुए सितारे हैं. इनके मुक्के का दम राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर देख रहा है. शुरुआती दिनों में विजेंदर ने बाक्सिंग के गुर भिवानी बॉक्सिंग क्लब में सीखे. इसके बाद जूनियर राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का क्रम शुरू कर दिया था. राष्ट्रीय स्तर पर अपने मुक्के का ज़ौहर दिखाने के बाद अंतरराष्ट्रीय ने विजेंदर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में तीन पदक जीतकर अपनी बाक्सिंग का अदांज बयां कर दिया था. एशियन गेम्स में दो पदक झटकर ओलम्पिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता के लिए अपने को तैयार कर लिया था. हालांकि 2004 में एंथेस ओलम्पिक में पहली बार भाग लिया लेकिन वहां पदक जीतने से चूक गए. तुर्की के मुस्तफ़ा ने इन्हें चारों खाने चित करते हुए उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया था. इसके बाद 2008 में बीजिंग ओलम्पिक में विजेंदर सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य

रियो ओलम्पिक को लेकर भारतीय खिलाड़ियों में अलग जज्बा देखा जा सकता है. तिरंगे के बैनर तले खेलने का एक अलग अनुभव होता है.

पदक जीतकर भारतीय मुक्केबाज़ी को एक नई राह दिखाई. वह रातों-रात स्टार बन गए. विजेंदर पर उम्मीदों का बोझ इसके बाद बढ़ गया लेकिन वह लंदन ओलम्पिक में भारत को पदक नहीं दिला सके. यह बात भी सत्य है कि इस दौर में वह भारतीय मुक्केबाज़ी को बुलन्दियों पर पहुंचाते हुए साल 2009 में वह मिडलवेट में नम्बर वन बॉक्सर भी बने. लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले भारतीय मुक्केबाज़ विजेंदर विवादों में फंसे लेकिन बाद में वह कामयाबी नई इबारत लिखते हुए प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग का दामन थाम लिया. भारत के दिग्गज पेशेवर मुक्केबाज़ विजेंदर सिंह प्रोफेशनल बॉक्सिंग रिंग में वह कई नामी गिरामी बॉक्सरों को धूल चटा रहे हैं. त्यागराज स्टेडियम में घरेलू दर्शकों के सामने भी बेजोड़ प्रदर्शन किया. इनके इस मुकाबले को देखने के लिए कई बड़े दिग्गज पहुंचे थे. विजेंदर ने भी किसी को निराश नहीं किया. कुल मिलाकर विजेंदर अगर ओलम्पिक होते तो भारतीय मुक्केबाज़ी की तसवीर कुछ और हो सकती थी.■

feedback@chauthiduniya.com

रजनी का क्रेज़ पसंद है

मलेशिया की सरकार ने तो रजनीकांत के सम्मान में स्पेशल स्टैम्प (डाक टिकट) भी जारी कर डाली है. फिल्म मलय भाषा में भी रिलीज़ हुई तो इस दक्षिण एशियाई देश ने रजनी के सम्मान में ख़ास कबाली स्टैम्प जारी की. कबाली इतना बड़ा सम्मान पाने वाली पहली इंडियन फिल्म होगी.

सोशल मीडिया में आजकल एक चुटकुला काफी पॉपुलर हो रहा है. एक तरफ हैं बॉलीवुड के स्टार खान्स, जो ईद, दीवाली और क्रिसमस जैसे त्यौहारों पर (यानी छुट्टी के दिन) अपनी फिल्म रिलीज़ करते हैं. वहीं दूसरी तरफ हैं साउथ के सुपरस्टार और भगवान माने जाने वाले रजनीकांत जिनकी फिल्म जब रिलीज़ होती है तो उस दिन छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है. सुनने में अजीब जरूर लगता है लेकिन यह सच है कि साउथ के तमाम ऑफिसों में रजनीकांत की फिल्म *कबाली* की रिलीज़ के दिन छुट्टी कर दी गई थी. चेन्नई की तमाम छोटी-बड़ी कंपनियों ने बीती 22 जुलाई को हॉलिडे घोषित कर दिया था.

दुनिया भर में रजनी के फैंस की कमी नहीं है, जिन्होंने कबाली को बेहद कम दिनों में विश्वभर में बॉक्स ऑफिस पर तेजी से 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करा दिया.

दुनिया भर में रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म *कबाली* रिलीज़ हुई. जिसका क्रेज लोगों में भारत के साथ-साथ दूसरे देशों में भी दिखा. लोगों में क्रेज इतना जबरदस्त था कि चेन्नई और मुंबई में फिल्म कबाली के पहले शो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच दिखाए गए. इस फिल्म को दुनियाभर में बड़े पैमाने पर रिलीज़ किया गया है. फिल्म विश्लेषकों का कहना है कि पिछले एक दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी फिल्म के रिलीज़ होने पर ऐसा क्रेज देखा गया हो.

रजनी के चलने का अंदाज, तेज तर्रार संवाद और एक्शन के अनोखे अंदाज़ से लोकप्रियता पाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत का नाम सुनते ही दिमाग़ में एक्शन की घंटियां बजने लगती है. उनके करियर पर नज़र डालें तो इसमें कोई शक नहीं कि इस महारथी को उनके प्रशंसक भगवान के रूप में पूजते हैं.

मलेशिया की सरकार ने तो रजनीकांत के सम्मान में स्पेशल स्टैम्प (डाक टिकट) भी जारी कर दिया है. फिल्म मलय भाषा में भी रिलीज़ हुई तो इस दक्षिण एशियाई देश ने रजनी के सम्मान में ख़ास कबाली स्टैम्प जारी की है. कबाली इतना बड़ा सम्मान पाने वाली पहली इंडियन फिल्म होगी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

रणबीर को देनी पड़ी सफाई

कंगना रनोट और रणबीर कपूर में अफेयर चल रहा है. दोनों पिछले कुछ समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. ऐसी ख़बरें पिछले कुछ दिनों से सुनने को मिल रही थीं. इन ख़बरों को सुन रणबीर काफी अपसेट हैं. रणबीर कपूर ने अब इन ख़बरों पर सफाई दी है. ऋतिक रोशन से चल रहे विवाद के दौरान रणबीर कपूर ने कंगना की काफी मदद की. रणबीर, कंगना को एक अच्छा दोस्त मानकर मदद कर रहे थे. लेकिन लोगों ने इसका गलत ही मतलब निकाल लिया. फिर कंगना का भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया. लेकिन फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग का मोरक्का शेड्यूल ख़त्म कर जब रणबीर स्वदेश आए और ख़बर उनके कानों तक पहुंची, तो वो काफी नाराज़ हुए. रणबीर के एक करीबी ने कहा, रणबीर को इस बात की हैरानी है कि आख़िर ये अफ़वाह कहां से शुरू हो गई कि वो कंगना को डेट कर रहे हैं क्योंकि इन बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है. रणबीर पिछले काफी समय से भारत में नहीं थे. वो मोरक्को में जग्गा जासूस की शूटिंग कर रहे थे. लेकिन भारत आकर जब उन्हें इस बात का पता चला तो वह काफी अपसेट हुए. वह जानते हैं कि इन ख़बरों को फैलाने के पीछे किसका हाथ है. अगर ऐसी ख़बरें आनी बंद नहीं होती हैं, तो वह इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे. गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही रणबीर का कैटरीना कैफ से ब्रेकअप हुआ है. ऐसे में रणबीर पहले ही टेंशन में हैं. इस पर उनका नाम कंगना के साथ जोड़कर लोगों ने उन्हें और परेशान कर दिया है.■

अक्षय की बहादुरी

अक्षय कुमार रीयल लाइफ में भी हीरोपंती दिखाते रहते हैं. एक कारनामा उन्होंने फिल्म रुस्तम के सेट पर दिखाया. शूटिंग के दौरान एक सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें एक घोड़े पर अक्षय कुमार और दूसरे पर इलियाना डीक्रूज सवार थे. अचानक इलियाना का घोड़ा बेकाबू हो गया. इलियाना का उस पर से नियंत्रण छूट गया. यह देख अक्षय ने फौरन उस घोड़े की लगाम थाम ली. घोड़े को काबू में ले आए. यह सीन इतना अच्छा बन पड़ा कि इसे फिल्म में भी रख लिया गया.■

बिपाशा के करियर पर ब्रेक

कभी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी बिपाशा बसु के पास अब फिल्मों की काफी कमी है. रिपोर्ट्स की मानें तो बिपाशा के पास ऑफर तो आते हैं, लेकिन उनमें से कोई चैलेंजिंग नहीं है. बिपाशा बसु का करियर कुछ ख़ास नहीं चल रहा. वहीं, करण सिंह ग्रोवर भी अपने करियर की शुरुआत में ही हैं. ऐसे में बिपाशा ने कुछ और ही प्लान कर रखा है. बिपाशा नहीं चाहतीं कि वे फिल्मों में सिर्फ इसीलिए काम करें, क्योंकि उन्हें मज़बूरी में करना पड़ रहा है. बल्कि वे ऐसी फिल्में करना चाहती हैं, जो उन्हें पसंद भी हों और चुनौतीपूर्ण भी. उनकी पिछली कुछ फिल्में क्रीचर थ्री डी, अलोन व आत्मा कोई ख़ास कमाल नहीं दिखा सकीं.■

बेबी को नहीं था बेस पसंद

अनुष्का ने किया सलमान को नाराज़

अनुष्का ने सलमान के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं कि सल्लू मियां नाराज़ हो गए हैं. अनुष्का का कहना है कि सलमान ने जो बलात्कार पीड़ित वाला कमेंट किया था वो बहुत ही असंवेदनशील था. साथ ही अनुष्का ने कहा कि सलमान अपने में मस्त रहने वाले इंसान हैं. जो मन में आया करते हैं. सामने वाले का ध्यान नहीं रखते. यही वज़ह है कि अनुष्का और उनमें तालमेल नहीं बैठा.

प्रवीण कुमार

सुल्तान फिल्म का गाना *बेबी को बेस पसंद है* इन दिनों काफी धूम मचा रहा है, लेकिन इस गाने की ठीक सिचुएशन फिल्म में नहीं बनाई गई. साथ ही आरफा (अनुष्का शर्मा) का जो किरदार है उस पर यह गाना बिलकुल फिट

नहीं बैठता है. अनुष्का ने कुछ ऐसा ही फील इस गाने की शूटिंग के दौरान किया था. उन्होंने निर्देशक अली अब्बास ज़फर से इस बारे में लंबी बात भी की. कहा कि यह गाना जम नहीं रहा है, पर अली अड़ गए और अनुष्का की एक ना सुनी. दबाव डालकर अनुष्का से यह गाना करवा ही लिया. जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया. खैर फिल्म ने वर्ल्ड वाइड्ड 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है और साल की ब्लॉक बस्टर फिल्म भी बन गई. लेकिन इसी बीच अनुष्का और सलमान के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा. ख़बरों की मानें तो अनुष्का सलमान से खुश नहीं हैं.

हाल में अनुष्का ने सलमान के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं कि सल्लू मियां नाराज़ हो गए हैं. अनुष्का का कहना है कि सलमान ने जो बलात्कार पीड़ित वाला कमेंट किया था वो बहुत ही असंवेदनशील था. साथ ही अनुष्का ने कहा कि सलमान अपने में मस्त रहने वाले इंसान हैं. जो मन में आया करते हैं. सामने वाले का ध्यान नहीं रखते. यही वज़ह है कि अनुष्का और उनमें तालमेल नहीं बैठा. अनुष्का का कहना है कि वे तो सलमान को ठीक से जानती भी नहीं हैं क्योंकि सलमान से उनकी बातचीत कभी नहीं हुई. शूटिंग के दौरान जब ग्रुप डिस्कशन होता था तभी दोनों के बीच बातें होती थी.

सुल्तान 2016 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है और अब ऐसी बातें सामने आ रही हैं. अनुष्का के इस प्रकार की बयानबाज़ी से सलमान काफी नाराज़ बताए जा रहे हैं. कहा जाए तो अनुष्का ने एक तरह से सल्लू से पंगा ले लिया है. सभी जानते हैं कि सलमान एक बार जिससे चिढ़ जाते हैं तो फिर वह किसी की नहीं सुनते. अगर यह बात सही साबित हुई तो संभव है कि वे अनुष्का के साथ दोबारा काम ही नहीं करें.■

feedback@chauthiduniya.com